सम्पादकीय

देर रात सड़कों पर गाड़ियां नहीं यमदूत चल रहे हैं, खतरे में हैं फुटपाथों पर सोने वाले लोगों की जिंदगियां

महानगरों की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि ये हर आदमी को ठिकाना मयस्सर नहीं करा पाते। वहां लोगों को गुजारे का कोई जरिया भले मिल जाए, पर हर किसी को सिर पर छत नसीब नहीं हो पाती। लाखों लोग दिन भर दिहाड़ी करके, रिक्शा-रेहड़ी-ठेला खींच कर या भीख मांग कर किसी तरह गुजारे भर की आमद तो कर लेते हैं, पर रात गुजारने के लिए उन्हें फुटपाथों पर खुले आसमान या उपरिगामी पुलों के नीचे, खाली बंद दुकानों के बाहर कोई जगह तलाशनी पड़ती है। इस तरह इन्हें मौसम की मार तो झेलनी ही पड़ती है, अक्सर तेज रफ्तार वाहनों के नीचे आकर दम तोड़ देने या अपंग होने का खतरा भी बना रहता है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर एक बेकाबू ट्रक के चढ़ जाने की घटना इसकी ताजा कड़ी है। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो को गंभीर स्थिति में भर्ती कराना पड़ा। ऐसे हादसों की खबरें कुछ-कुछ समय पर हर महानगर से मिल जाती हैं। हर घटना के बाद सवाल उठता है कि आखिर इस तरह सड़कों के किनारे, फुटपाथों पर सोने वालों के लिए कोई सुरक्षित इंतजाम क्यों नहीं किया जाता।

हालांकि अनियंत्रित वाहनों के सड़कों के बीच की जगहों और फुटपाथों पर चढ़ने से रोकने की गरज से बहुत सारी जगहों पर लोहे की मजबूत बाड़ लगाई जाती है, मगर बहुत सारी जगहों पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदि शहरों में सड़कों पर रात में भी आवाजाही लगी रहती है। रात के वक्त शहरों की सड़कें खासकर माल ढुलाई वाले वाहनों के लिए खोल दी जाती हैं। इसके अलावा, बहुत सारे युवा देर रात को शराब पीकर वाहन दौड़ाना अपनी शान समझते हैं। वाहनों के अनियंत्रित होकर फुटपाथों पर चढ़ जाने की घटनाएं अक्सर शराब के नशे में गाड़ी चलाने की वजह से होती पाई गई हैं। हालांकि दिल्ली में जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाती है, इसके बावजूद बहुत सारे वाहन चालकों की मनमानी पर लगाम लगाना कठिन बना हुआ है। देर रात को उनकी मनमानी और बढ़ जाती है। इससे यातायात व्यवस्था पर तो प्रश्नचिह्न लगता ही है, रोजी-रोजगार की तलाश में हर वर्ष लाखों की संख्या में आने वाले लोगों के लिए रहने की व्यवस्था पर भी गंभीरता से विचार की जरूरत रेखांकित होती है। अनेक मौकों पर यह बात कही जाती रही है कि बढ़ते पलायन और महानगरों पर उसके बढ़ते बोझ की वजह से सरकारों के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना चुनौती है। इसके समाधान की दिशा में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मगर न तो सरकारों ने रोजी-रोजगार के साधनों के विकेंद्रीकरण पर गंभीरता से विचार किया, न महानगरों में सबके रहने के ठिकाने उपलब्ध कराने की व्यावहारिक पहल हो पाई। दिल्ली में रैन बसेरे बनाए तो गए, मगर उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि लोगों को फुटपाथों पर सोने को मजबूर न होना पड़े। उनमें भी जरूरी सुविधाओं के अभाव की शिकायतें आती रहती हैं। दरअसल, महानगरों में बेआसरा लोगों के बारे में कोई व्यावहारिक नीति बनाने के बारे में सोचा ही नहीं गया। अगर जगह-जगह, थोड़े शुल्क के साथ भी, धर्मशाला जैसी रात गुजारने की जगहें बना दी जाएं।

छत्रपति प्रतिमा का ढहना शासन-तंत्र की भ्रष्टता का प्रमाण

सिंधु दुर्ग में शिवाजी महाराज की इस प्रतिमा के गिर जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आना स्वाभाविक है, इससे लोगों का आहत होना भी उचित हैं। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के महानायक एवं जन-जन की आस्था के केन्द्र हैं। वे महाराष्ट्र के जीवन का अभिन्न अंग हैं एवं वहां की राजनीति उनके नाम के इर्द-गिर्द घूमती है। महाराष्ट्र ही नहीं सम्पूर्ण देश में शिवाजी महाराज के प्रशंसक हैं। मराठों के अस्तित्व एवं अस्मिता के वे प्राण रहे हैं, मराठों को उन्होंने ने ही लड़ना सिखाया, उनके जीवन को उन्नत बनाया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के महाराष्ट्र की सभी जातियों को एक भगवा झंडे के नीचे एकत्रित किया और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने अपने राज्य-शासन में मानवीय नीतियां अपनाई थी जो किसी धर्म पर आधारित नहीं थी।

ललित गर्ग

मराठा पहचान और परम्परा के प्रतीक पुरुष, प्रथम हिन्दू नेता छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हाल ही में की गयी 35 फीट ऊंची प्रतिमा का थरथरा कर गिर जाना राष्ट्रीय शर्म एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार का दुःखद अध्याय है। इस तरह हमारे एक महानायक की महान स्मृतियों से जुड़ी इस प्रतिमा का गिरना एवं ध्वस्त होना सरकार में गहरे पैठ चुके भ्रष्टाचार, लापरवाही एवं रिश्वतखोरी को उजागर करता है। आजादी के अमृत-काल में पहुंचने के बाद भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी हमारी व्यवस्था में जिस तीव्रता से व्याप्त है, उसका यह एक ज्वलंत उदाहरण है, जो सरकार की साख को धुंधला रही है, यह घटना भारतीय नौसेना की साख को भी बट्टा लगा रही है, यह घटना इसलिए भी गंभीर चिंता की बात है कि इससे हमारे सार्वजनिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की कलई खुल गई है। गौर कीजिए, इस प्रतिमा के निर्माण पर करीब 3,600 करोड़ रुपये की लागत आई थी और इसी 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर इसका अनावरण किया गया था। महाराष्ट्र क्योंकि उनकी जन्मस्थली ही नहीं कर्मस्थली भी रहा इसलिए महाराष्ट्र की आबोहवा में वे आज भी जीवंत हैं। ऐसे महानायक की प्रतिमा के गिर जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया है। मूर्ति का निर्माण और डिजाइन नौसेना ने तैयार किया था। कहा तो यही जा रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के कारण प्रतिमा टूटकर गिर गई। छत्रपति शिवाजी के महाराष्ट्र और मराठा संस्कृति के ही नहीं, बल्कि भारतीयता के प्रतीक एवं प्रेरणा पुरुष हैं। आम मराठी भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा है। ऐसे में, इस मूर्ति का ढहना राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार एवं भारतीय नौसेना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। चंद महीने बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने के कारण यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनना निश्चित है। एक मजबूत विपक्षी पार्टी शिव सेना की पूरी राजनीति शिवाजी के शौर्य व आत्म-गौरव से प्रेरित है, एनसीपी शरद पवार, कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने एकनाथ शिंदे सरकार को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और आरोप लगाया है कि छत्रपति शिवाजी का स्मारक चुनावों को देखते हुए जल्दबाजी में बनाया गया था और इस काम में गुणवत्ता को पूरी तरह से अनदेखा किया गया। प्रतिमा का ढह जाना छत्रपति शिवाजी का अपमान तो है ही और यह जाहिर है कि इसका काम घटिया गुणवत्ता का था। इसीलिये घटना को शिवाजी के अपमान के रूप में पेश किया जाने लगा है। चुनाव की सरगर्मियों के बीच शिवाजी की प्रतिमा का मुद्दा चर्चा में आ गया है। इस मुद्दे को वोट जुटाने के लिए असरदार हथियार के रूप में जरूर इस्तेमाल किया जायेगा। लेकिन मूल प्रश्न है ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में कब सार्थक प्रयास होंगे? राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करके दोषियों को कड़ी सजा दिलानी चाहिए, ताकि न सिर्फ विपक्ष के आरोपों की धार को निस्तेज किया जा सके, बल्कि सार्वजनिक निर्माण में किसी किस्म की लापरवाही या उदासीनता बरतने वालों को भी यह संदेश मिल सके कि वे बख्शे नहीं जाएंगे।

यह पहली घटना नहीं है, जिसमें किसी बड़ी निर्माण योजना की कमी इस तरह की भ्रष्ट एवं लापरवाही के रूप में उजागर हुई है। हमारे सार्वजनिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बार-बार तार-तार होती रही है। मई 2023 में उज्जैन के महालोक कोरिडोर में लगी सप्तऋषियों की मूर्तियां भी इसी तरह आंधी-तूफान में धराशायी हो गई थीं। अयोध्या में भी सड़कें ध्वस्त हो गयी थी। बिहार में एक पखवाड़े के भीतर लगभग एक दर्जन छोटे-बड़े पुलों के ध्वस्त होने की घटनाएं हैरान करने के साथ-साथ चिंतित करने वाली बनी हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल-1 पर छत गिरने की घटना से भी हर कोई हैरान हुआ है। मुंबई में घाटकोपर का होर्डिंग गिरना 14 लोगों की मौत का कारण बना था। कहीं नई बनी सड़कें धंस हो जाती हैं तो कहीं नई सरकारी इमारतों में दरारे पड़ जाती है। इन मूर्तियों, पुलों, सड़कों एवं सार्वजनिक निर्माण के अन्य सरकारी निर्माणों के ध्वस्त होने की घटनाओं ने एक बार फिर यही साबित किया है कि निर्माण कार्यों में फैले व्यापक भ्रष्टाचार और शासन तंत्र में बैठे लोगों की मिलीभगत के बीच ईमानदारी, नैतिकता, जिम्मेदारी या संवेदनशीलता जैसी बातों की जगह नहीं है। आज हमारी व्यवस्था चरमरा गई है, दोषग्रस्त हो गई है। उसमें दुराग्रही इतना तेज चलते हैं कि ईमानदारी बहुत पीछे रह जाती है। जो सद्प्रयास किए जा रहे हैं, वे निष्फल हो रहे हैं। प्रतिमाएं हो या पुल-इनके गिरने से जितने पैसों की बर्बादी होती है, उसकी भरपाई आखिर किससे कराई जाएगी? जाहिर है, इनकी वजहों को समझने के लिए किसी मजबूत, पारदर्शी एवं निष्पक्ष तंत्र की जरूरत है। निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता से समझौता और राजनीतिक दबाव में जल्द से जल्द कार्य पूरा करने की प्रवृत्ति ने ऐसी दुर्घटनाओं की गति एवं मात्रा बढ़ाई है। इसके लिए समूचे तंत्र को अपनी कार्य-संस्कृति पर भी गौर करने की जरूरत है। शिवाजी की प्रतिमा के तेज हवा में यूं ढह जाने से हमें सबक सीखने की जरूरत है। सवाल है कि जब सरकार किसी कंपनी को ऐसे राष्ट्रीय महत्व के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपती हैं, उससे पहले क्या गुणवत्ता की कसौटी पर पूरी निर्माण योजना, डिजाइन, प्रक्रिया, सामग्री, समय-सीमा और संपूर्णता को सुनिश्चित किया जाना जरूरी समझा जाता? देश में भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है, विशेषत: राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने देश के विकास को अवरूद्ध कर रखा है। यही कारण है कि पुल या दूसरे निर्माण-कार्यों के लिए रखे गए बजट का बड़ा हिस्सा कमीशन-रिश्वतखोरी की भेंट चढ़ जाता है। इसका सीधा असर निर्माण की गुणवत्ता पर पड़ता है। निर्माण घटिया होगा तो फिर उसके धराशायी होने की आशंका भी बनी रहती है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने की पारदर्शी नीति नियामक केन्द्र बनाने के साथ उस पर अमल भी जरूरी है। विकसित देशों में भी ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन अंतर यह है कि भारत में ऐसे हादसों से सबक नहीं लिया जाता। यह प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण है। विडम्बना देखिये कि ऐसे भ्रष्ट शिखरों को बचाने के लिये सरकार कितने सारे झूठ का सहारा लेती है।

रणनीति में सभी अपने को चाणक्य बताने का प्रयास करते हैं पर चन्द्रगुप्त किसी के पास नहीं है। घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए हल्ला उनके लिए राजनैतिक मुद्दा होता है, कोई नैतिक आग्रह नहीं। कारण अपने गिरेबान में तो सभी झांकते हैं वहां सभी को अपनी कमीज दागी नजर आती है, फिर भला भ्रष्टाचार से कौन निजात दिलायेगा? ऐसी व्यवस्था कब कायम होगी कि जिसे कोई रिश्वत छू नहीं सके, जिसको कोई सिफारिश प्रभावित नहीं कर सके और जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सके। ईमानदारी अभिनय करके नहीं बताई जा सकती, उसे जीना पड़ता है कथनी और करनी की समानता के स्तर तक। आवश्यकता है, राजनीति के क्षेत्र में जब हम जन मुखातिब हों तो प्रामाणिकता का बिल्ला हमारे सीने पर हो। उसे घर पर रखकर न आएं। राजनीति के क्षेत्र में हमारा कुर्ता कबीर की चादर हो। तभी इन मूर्तियों, पुलों, निर्माण कार्यों का भर-भराकर गिरना बन्द होगा।

शख्सियत

हमारे कार्य करने का तरीका कुछ ऐसा हो जिसमें दिखावे से परे सच में कार्य नजर आए । ईश्वर ने हमें इस लायक इसलिए ही बनाया है कि हम परिवेदनाओं के अंतिम छोर तक जाकर लोगों की मदद कर सकें........

आनन्दी
(वरिष्ठ आईएएस अधिकारी)

नमस्कार दोस्तों हमारे आज शख्सियत कॉलम की चमकती हुई सितारा हैं आईएएस श्रीमती आनन्दी। इनका जन्म 1 मार्च सन 1982 को तमिलनाडु में हुआ। इनकी योग्यता बी.ए। ऑनर्स (समाजशास्त्र) एलएलबी (कानून) एम.ए (अर्थशास्त्र) से की है। वर्तमान में ये शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान के पद को सुशोभित कर रही हैं। ये विभिन्न बड़े पदों व बड़े जिलों में जिलाधिकारी के पद पर रही हैं बेहतरीन कार्यकुशलता इनके जीवन के अनुभव व पारिवारिक पृष्ठभूमि को इंगित करते हैं। ये सचिव शासन सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर। उप निदेशक, एलबीएसएनए मसूरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर। संयुक्त शासन सचिव, वित्त कराधान विभाग, जयपुर। आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशेष सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजसमंद। निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर। निदेशक, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर। रजिस्ट्रार, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी। प्रबंध निदेशक, राजफैड, जयपुर। आयुक्त,जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषदए जोधपुर। उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर।लेसना, मसूरी में प्रशिक्षणाधीन रही हैं। बेहतरीन व्यक्तित्व और कार्य के प्रति निष्ठा का भाव ही इन्हे आनन्दी बनाता है। एक दम सरल व सहज जीवन शैली और अपने कर्तव्य के प्रति अनुशासन इनकी शख्सियत का एक बड़ा हिस्सा है। अलवर व उदयपुर जिला कलक्टर के दौरान इनके द्वारा किए गए कार्य मील का पत्थर साबित हुए। अलवर जिला कलक्टर पद पर रहते हुए इन्होंने कोविड़ महामारी जैसी बड़ी घटनाओं पर लोगों को जहां जागरूक किया वहीं अधिक से अधिक जॉंच करा बीमारी के संक्रमण पर रोक लगवाई। ये सच में साधुवाद की पात्र रही हैं। दैनिक बढ़ता राजस्थान इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।

जय हिन्द

आज का इतिहास

- 1612 - सूरत की लड़ाई में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया,
- 1833 - ब्रिटिश दास उन्मूलन अधिनियम ने कानून का रूप लिया।
- 1842 -
- ग्रेट ब्रिटेन और चीन ने नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर किये।
- अफ़ीम युद्ध समाप्त।
- 1914 - न्यूजीलैंड सैनिकों ने जर्मन समोआ पर कब्ज़ा किया।
- 1916 - अमेरिकी कांग्रेस ने जोन्स अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की= फिलीपींस को मिली स्वतंत्रता।
- 1932 - नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध-विरोधी समिति का गठन।
- 1941 - रूस में जर्मन इंस्तजकमांडो ने 1469 यहूदी बच्चों की हत्या की।
- 1945 - ब्रिटिश ने हांगकांग को जापान से मुक्त कराया।
- 1957 - कांग्रेस ने नागरिक अधिकार अधिनियम, 1957 पारित किया।
- 1974 - चौधरी चरण सिंह की अध्यक्षता में लोकदल पार्टी स्थापना।
- 1987 - कर्नल राबुका ने फिजी को गणराज्य घोषित किया।
- 1996 - आर्कटिक द्वीप के स्पिट्सबर्गेन की पहाड़ी में वनुकोवो एयरलाइंस के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार सभी 141 लोगों की मौत।
- 1998 - पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित।
- 1999 - बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष के दौरान टाइगर सिद्दीकी के नाम से मशहूर सांसद कादिर सिद्दीकी ने संसद की सदस्यता से इस्तीफ़ा दिया।
- 2000 - न्यूयार्क में चार दिवसीय विश्व शांति शिखर सम्मेलन शुरू।
- 2001 - पश्चिम एशिया में पुन= हिंसा भड़की, तीन फ़िलिस्तीनी मरे; जापान के एच-2 ए रॉकेट का सफल प्रक्षेपण।
- 2002 - पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ़ का नामांकन पत्र स्वीकार किया।
- 2003 - कोलंबिया अंतरिक्ष यान हादसे के लिए नासा की त्रुटिपूर्ण कार्य-संस्कृति को ज़िम्मेदार ठहराया गया।
- इराक के पवित्र शहर नजफ़ में हुए एक आत्मघाती हमले में शिया नेता सहित 75 लोग मारे गये।
- 2004 - एथेंस ओलम्पिक का समापन।
- 2008-तृणमूल कांग्रस के कार्यकर्ताओं के बवाल से क्षुब्ध होकर टाटा मोटर्स ने सिंगुर में नैनों परियोजना स्थल से अपने कर्मचारी हटाए।
- झारखण्ड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री शिबु सोरेन ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया।
- 2012 - चीन में सिचुआन प्रांत के शियाओजियावान कोयला खदान में हुए विस्फोट से कम से कम 26 चीनी श्रमिकों की मौत हो गयी जबकि 21 लापता हो गये।

विशेष आलेख

आरक्षण खत्म करने की बात कौन करेगा?

अशोक मधुप

दलित और पिछड़े युवाओं के उत्थान के लिए लाया गया आरक्षण अब सत्ता मे पंहुचने माध्यम बनता जा रहा है। अलग - अलग राज्य मे राजनैतिक दल जहां आरक्षण को अपने हिसाब से अदल - बदल रहे हैं, वहीं प्राइवेट सैक्टर में भी आरक्षण लागू करने की कोशिश हो रही है। कुछ राज्यों ने अपने यहां ये आरक्षण लागू किया पर वहां के हाईकोर्ट ने उसे अवैध बताते हुए रोक लगा दी,पर ये कोशिश जगह-जगह जारी है। सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायधीश की संविधान पीठ आरक्षण मे क्रीमीलेयर लागू करने की बात की तो विपक्ष ने राजनैतिक लाभ उठाने के लिए इसका विरोध शुरू कर दिया। हालाकि प्रधानमंत्र नरेंद्र मोदी आश्वस्त कर चुके है कि आरक्षण मे क्रीमीलेयर लागू नही होगा ,इसके बावजूद आरक्षण समर्थक राजनैतिक दलों ने इसके विरूद्ध आंदोलनरत हैं। अभी वे भारत बंद का आह्वान कर ही चुके हैं। इससे पहले कर्नाटक में प्राइवेट नौकरी मे स्थानीय के लिए शत प्रतिशत आरक्षण को लागू करने पर खड़ा हो गया। हालाकि प्रदेश कैबनेट में पास किया गया ये कानून विरोध को देखते हुए ठंडे बस्ते मे डाल दिया गया है, पर खत्म नही किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगली कैबनेट की बैठक मे इसपर फिर विचार होगा। हाल के लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के आते -आते प्रचार आरक्षण पर आकर सिमट गया। भाजपा नेता अपने भाषणों में दावा कर रहे है कि हम देश मे मुस्लिम आरक्षण लागू नही होने देंगे।खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में मुस्लिम आरक्षण पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि सत्ता में आते ही इंडिया गठबंधन दलित और पिछड़ों का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को दे देगा।ये देश का विभाजन करवा देंगे।इस पर कुछ बड़े नेता तो चुप्पी साधे है किंतु समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने एक बयान में कहा है कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आते ही संविधान मे संशोधन कर मुस्लिमों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा। देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए।आजादी के बाद दलित समाज को विकास की धारा में शामिल करने के लिए दस साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।आज ये आरक्षण राजनेताओं को सत्ता में पंहुचने का माध्यम नजर आने लगा है, वे इसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं।खत्म करने की नही। किसी को यह सोचने की फुरसत नही कि आरक्षण की मार से बचने के लिए देश के प्रतिभाशाली युवा आज विदेशों मे जाकर शिक्षा ले रहे है। शिक्षा पूरी कर वहीं नौकरी या व्यवसाय कर चुने गए देश के विकास मे योगदान कर रहे हैं।भारत के बाहरर जाकर बसी भारत की मेधा से प्रभावित होते देश के विकास पर किसी को सोचने का समय नहीं ।

प्राइवेट सैक्टर की नौकरियों में आरक्षण को लेकर कर्नाटक सरकार ने यूटर्न ले लिया है। सरकार ने पहले सी और डी कैटेगरी की प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की बात कही थी। फिलहाल, आरक्षण के उस फैसले पर रोक लगा दी गई है। कैबिनेट ने फैसला स्थगित कर दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्राइवेट सैक्टर में कन्नड़ लोगों को 100 फीसदी आरक्षण देने को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की थी। अपनी इस पोस्ट में उन्होंने कहा, हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं।सरकार के इस फैसले का चौतरफा विरोध होने पर इस पर रोक लगा दी गई। सरकार का कहना है कि इस बिल पर वह पुनर्विचार करेगी. देश में यह पहला ऐसा मामला नहीं है। कर्नाटक से पहले प्राइवेट सैक्टर में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए आंध्र प्रदेश और हरियाणा मे कोशिश की गई थी. वहीं, मध्य प्रदेश में भी सरकार ने ऐसा ही कहा था, लेकिन यह कोशिश रंग नही ला पाई थी। 2019 मे आंध्र प्रदेश में पहली बार ऐसा कोई कानून बना था जहां 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही गई थी। पर हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। फिलहाल, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। महाराष्ट्र में 2019 में शिवसेना-कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की सरकार बनने के बाद प्राइवेट नौकरियों में स्थानीयों को 80 प्रतिशत नौकरियां देने का प्रस्ताव लाया गया था। सरकार सरकार इसे विधानसभा में भी लाना चाहती थी। लेकिन इसे लाया नहीं गया।कर्नाटक में कई बार प्राइवेट जॉब में कन्नड़ों के लिए आरक्षण तय करने की कोशिश हो चुकी है। सिद्धारमैया सरकार में ये तीसरी बार है जब ऐसी कोशिश हो रही है। इससे पहले 2014 और 2017 में भी सरकार कोशिश कर चुकी है। वहीं अक्टूबर 2020 में येदियुरप्पा की अगुवाई में बीजेपी सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में ग्रुप सी और डी में 75 प्रतिशत आरक्षण स्थानीयों को देने का ऐलान किया था। हालांकि, ये लागू नहीं हो सका था। हरियाणा मे 2020 में तब की मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीयों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून पास किया था। हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस कानून को रद्द कर दिया।झारखंड में दिसंबर 2023 में हेमंत सोरेन की सरकार ने सरकारी नौकरियों की ग्रुप तीन और चार मे स्थानीयों को 100 प्रतिशत आरक्षण देने के मकसद से बिल पास किया था। ये बिल विधानसभा में पास हो गया था, लेकिन गवर्नर ने इसे लौटा दिया था। आज के हालात का निष्कर्ष ये है कि प्रत्येक दल आरक्षण की सीढ़ी से सत्ता मे पंहुचने के प्रयास में लगा है।

उसे उससे वास्ता नही कि आरक्षण की जद में आने वाली प्रतिभाएं इसे लेकर क्या सोचती हैं? 2012 में केंद्र सरकार प्रमोशन में आरक्षण का बिल ला चुकी है। संसद में बिल रखे जाने के दौरान एक सांसद द्वारा मंत्री से छीन कर बिल की प्रति फाड़ दिए जाने के कारण ये अटक गया। नहीं तो प्रमोशन में भी आरक्षण लागे हो चुका होता। अब क्रीमीलेयर तै करने के बारे मे सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के आदेश को वे ही ठेंगा दिखाने को तैयार हैं जो अब तक इससे लाभ लेते रहे हैं। आरक्षण का लाभ उठा चुके उच्च स्थिति में पंहुचने वाले ही विकास की धारा से वंचित अपनी जाति वालों के लिए आरक्षण का लाभ छोड़ने को तैयार नही हैं। आज हालत यह है कि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ आदेश करे या कोई अन्य मांग हो, आरक्षण को कम करने को कोई राजनैतिक दल छोड़ने को तैयार नही। कोई इसके खत्म करने की बात नही कर रहा।सब बढ़ाने की बात कर रहे हैं।आरक्षण के दायरे से बाहर की जाति और उसे युवा ये सब देख रहे हैं। अभी हाल में यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर हुए बवाल ने बाद सरकार ने 45 पदों पर लेटरल एंट्री का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। विपक्ष का कहना था कि सरकार आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, सरकार अपनी छवि बचाने को बार -बार पीछे हटती जा रही है। ऐसे में आरक्षण से बाहर रह रही युवा पीढ़ी के भविष्य की किसी को चिंता नहीं।आरक्षण समर्थक कोई नेता और राजनैतिक दल ये नही सोच रहा कि ये आरक्षण से बाहर रहे युवा उनके बारे में क्या विचार और सोच बना रहे हैं?

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई [illegible]

मेष
संतान पक्ष से अच्छे समाचार मिलेंगे। नौकरीपेशा लोगों से आपको लाभ होगा। आय में वृद्धि होगी। वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी। आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। आप आज हर काम सरलता से पूरे कर पाएंगे।

वृष
नौकरी में आपके अधिकारी खुश रहेंगे। आपकी पदोन्नति के योग हैं। अधिकारियों के साथ किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा होगा। परिजनों के साथ खुले मन से बातचीत होगी। घर के डेकोरेशन पर कुछ खर्च हो सकता है।

मिथुन
आपका शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य अच्छा रहेगा। जरूरी कामों पर धन खर्च होगा। बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। दफ्तर में सहकर्मियों का अच्छा साथ मिलेगा।

कर्क
हेल्थ का ध्यान रखने और खासकर बाहर के खाने-पीने से परहेज करने की सलाह आपको दी जाती है। आज आपमें क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, इसलिए वाणी में गुस्सा ना रखें। परिजनों से उग्र चर्चा के कारण मनमुटाव न हो। महिलाओं के मायके से समाचार आने के योग हैं।

सिंह
स्वजनों एवं परिजनों के साथ विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा और ज्यादा परिश्रम के बाद ही सफलता मिलेगी। दुर्घटना हो सकती है, सावधान रहें। आज आपका दिन बहुत लाभदायी है।

कन्या
आज धन का व्यय अधिक होगा। आज नियम विरुद्ध कामों से दूर रहें। आज आपका दिन आनंद-प्रमोद में गुजरेगा। रोमांस के लिए आज का दिन अच्छा है और किसी खास व्यक्ति का साथ आपको आनंद देगा। धन लाभ होगा और अधूरे काम पूरे हो सकते हैं।

तुला
आप तन-मन से स्वस्थ होकर कई तरह के काम आसानी से पूरे कर पाएंगे। सफलता मिलने से आपके उत्साह में वृद्धि होगी। आज भाग्य आपका साथ देगा। इनकम बढ़ेगी। परिजनों के साथ आनंद एवं उल्लास से समय गुजरेगा।

वृश्चिक
बाहर जाना हो सकता है। माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। सरकारी लाभ होगा एवं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। पहले से निर्धारित काम के लिए आपका प्रयास ज्यादा रहेगा।

धनु
माता से लाभ होने के संकेत आपको मिल रहे हैं। मित्र और संबंधियों से घर का वातावरण अच्छा रहेगा। आज अचानक होने वाली घटनाओं से आप चिंतित रहेंगे। स्वास्थ्य खराब होने और आंखों में दर्द होने की आशंका बनी रहेगी।

मकर
मित्र एवं प्रियजन आपके प्रवास को आनंद से भर देंगे। नए वस्त्रों की खरीदी के योग हैं। तन-मन की तंदुरस्ती अच्छी रहेगी। अच्छे भोजन एवं वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी। आज आप के घर में सुख शांति और आनंद का माहौल रहेगा।

कुंभ
आज आपके धार्मिक एवं मांगलिक कामों में व्यस्त रहने की संभावना ज्यादा रहेगी। आप में आज क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, इसलिए आप सावधान ही रहें। संतान एवं व्यापार की परेशानियों के कारण आपका मन अशांत रहेगा।

मीन
अविवाहितों को योग्य जीवनसाथी मिलने के योग हैं। धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। मित्रों से अचानक हुई मुलाकात आनंददायी रहेगी। मित्रों से लाभ होगा। आज आपको अच्छा खाना नसीब होगा। मित्रों से लाभ होगा। आपका व्यवहार न्यायपूर्ण रहेगा।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीदपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 ''प्रतीक्षा'' सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान"। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 29 अगस्त, 2024

कल्पमेधा

बिना शिक्षा के 'कामन सेंस' या विवेक होना, शिक्षा प्राप्त करके भी 'कामन सेंस' या विवेक न होने से हजार गुना बेहतर है।

– राबर्ट ग्रीन इन्गेर्सोल

प्रतिरोध का स्वर

लगा था कि सर्वोच्च न्यायालय की दखल के बाद कोलकाता चिकित्सक बलात्कार और हत्या मामले को लेकर उभरा लोगों का रोष कुछ कम हो जाएगा, मगर वह और बढ़ता जा रहा है। अदालत ने घटना के विरोध में आंदोलन कर रहे चिकित्सकों से काम पर लौटने की अपील की थी। मामले पर कार्रवाई में बरती गई शिथिलता और लापरवाहियों को लेकर पुलिस और चिकित्सालय प्रशासन को फटकार लगाई थी। मगर उससे लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा। मंगलवार को पश्चिम बंग छात्र समाज ने 'नवान्न' अभियान शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि यह छात्रों का गैरराजनीतिक मंच है और इसकी तीन प्रमुख मांगें हैं- पीड़िता को न्याय मिले, मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें और अपराधी को मृत्युदंड मिले। अब छात्रों के विरोध में कुछ सरकारी कर्मचारी संगठनों ने भी अपना स्वर मिला दिया है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को बारह घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया था, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कई जगह झड़पें भी हुईं। ऐसे वातावरण में राष्ट्रपति ने भी अपने संबोधन में कहा कि अब समय आ गया है कि बेटियों पर अत्याचार को सहन न किया जाए। किसी भी हाल में महिलाओं का उत्पीड़न रुकना चाहिए।

स्वाभाविक ही इस विरोध प्रदर्शन से ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि इस मामले पर सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। ममता बनर्जी इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे भाजपा का हाथ बता रही हैं और उनका आरोप है कि केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। विपक्षी गठबंधन के नेता भी इसमें सियासी रंग घोल रहे हैं। इस तरह कोलकाता बलात्कार और हत्या प्रकरण में अब असल मुद्दे पर कार्रवाई से अधिक राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। हालांकि इस घटना को बीस दिन हो गए और शुरू में ही ममता बनर्जी ने इस पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया था। आरोपी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लापरवाही बरतने वाले अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई। मामले की जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंप दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। आरोपी के सच से सामना कराने से कुछ तथ्य सामने आने की उम्मीद बनी हुई है। मगर लोगों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही, तो इसकी कुछ वजहें साफ हैं। अभी तक अनेक आपराधिक मामलों में ममता बनर्जी सरकार का रवैया संतोषजनक नहीं देखा गया है। उन सबका मिलाजुला, लंबे समय से जमा रोष इस घटना के बाद फूट पड़ा है।

कोलकाता चिकित्सक बलात्कार और हत्या कांड को लेकर पूरे देश में आक्रोश प्रकट हुआ है, तो उसके पीछे भी बड़ी वजह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बरती जा रही शिथिलता है। राष्ट्रपति के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत है कि निर्भया कांड के बारह बरस बाद भी ऐसे जघन्य अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। मगर जब तक सरकारें राजनीतिक नफे-नुकसान से ऊपर उठ कर इस दिशा में सामूहिक प्रयास से कोई व्यावहारिक और कारगर कदम नहीं उठाएंगी, तब तक ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना मुश्किल बना रहेगा। ममता बनर्जी को इसे राजनीतिक रस्साकशी का मुद्दा बनाने के बजाय लोगों को यह भरोसा दिलाना होगा कि वे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं और बलात्कार तथा हत्या मामले में न्याय दिलाने का हर प्रयास करेंगी।

भविष्य पर संकट

भारतीय युवाओं में विदेश जाकर पढ़ाई करने और वहीं कोई अच्छा रोजगार तलाश लेने की प्रवृत्ति पिछले कुछ समय से काफी बढ़ी है। इसके लिए भारतीयों के पसंदीदा देशों में कनाडा भी शामिल है। हर वर्ष बड़ी संख्या में भारतीय युवा वहां पढ़ाई करने जाते हैं। वहां छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ अस्थायी तौर पर नौकरी भी मिल जाती है। मगर, अब कनाडा सरकार ने अपनी आव्रजन नीति में बदलाव कर दिया है, जिससे वहां रह रहे भारत समेत अन्य देशों के विद्यार्थियों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। इनमें से बहुत से युवाओं को निर्वासन की चिंता सताने लगी है। इसके विरोध में सैकड़ों भारतीय छात्र कनाडा की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल, कनाडा सरकार ने अब उन क्षेत्रों में विदेशी कामगारों को 'परमिट' न देने का फैसला किया है, जहां बेरोजगारी दर छह फीसद या उससे ज्यादा है। कम वेतन वाली अस्थायी नौकरियों के लिए 'परमिट' दो के बजाय अब एक वर्ष के लिए जारी होंगे। इसका मकसद कनाडा की बढ़ती आबादी और बेरोजगारी दर को नियंत्रित करने के लिए अप्रवासियों की संख्या को सीमित करना है।

कनाडा की नई आव्रजन नीति का सबसे ज्यादा असर भारतीय छात्रों पर पड़ेगा। जो छात्र पढ़ाई के साथ-साथ अस्थायी नौकरी कर रहे हैं, उनके 'परमिट' की अवधि जल्द खत्म हो जाने से उन्हें अपना खर्चा जुटाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भारतीय छात्र कनाडा में जगह-जगह प्रदर्शन कर नई आव्रजन नीति का विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि इस वर्ष के अंत में जब छात्रों के 'वर्क परमिट' समाप्त हो जाएंगे, तो उन्हें निर्वासित किया जा सकता है। वैसे यह पहली बार नहीं है, जब कनाडा में भारतीय विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। कभी नस्लीय हिंसा, कभी आतंकी गतिविधियों, तो कभी वीजा एजंटों की धोखाधड़ी की वजह से वहां भारतीय छात्रों के लिए मुश्किलें खड़ी होती रही हैं। भारत सरकार को इस पक्ष पर गंभीरता से विचार करना होगा कि जिन सुविधाओं और बेहतर भविष्य की चाह में युवा विदेश जाते हैं, क्यों न उन्हें अपने देश में ही वह सब उपलब्ध कराया जाए। इससे भारत से बौद्धिक पलायन भी काफी हद तक रुकेगा।

वृद्धि दर और अर्थव्यवस्था का सच

अर्थव्यवस्था में अंग्रेजी अक्षर 'के' आकार की वृद्धि यह बताती है कि इसमें कुछ उद्योग और व्यावसायिक समूह ऊपर उठ रहे हैं, जबकि अन्य नीचे की ओर जाते हुए, संघर्ष करते लग रहे हैं।

अजय जोशी

कोरोना के चलते वर्ष 2020 से 2022 तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वर्ष 2022 के अंत से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आना शुरू हुआ। इस महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को कुछ अर्थशास्त्री अंग्रेजी अक्षर 'के' आकार की वृद्धि मान रहे हैं, जिसमें अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। अगर हम 'के' अक्षर की कल्पना करें तो इसमें दो रेखाएं नजर आती हैं। एक रेखा ऊपर की तरफ जाती है और दूसरी नीचे की तरफ। अर्थव्यवस्था में अंग्रेजी अक्षर 'के' आकार की वृद्धि यह बताती है कि इसमें कुछ उद्योग और व्यावसायिक समूह ऊपर उठ रहे हैं, जबकि अन्य नीचे की ओर जाते हुए, संघर्ष करते लग रहे हैं।

इस वृद्धि में मोटे तौर पर पूरी अर्थव्यवस्था में सुधार होता प्रतीत होता है, जबकि यह सुधार सभी क्षेत्रों में सामान रूप से नहीं होता। इसमें कुछ क्षेत्र ठीक हो पाते हैं, जबकि अन्यों को संघर्ष करते रहना पड़ता है। इसमें संगठित क्षेत्र आगे बढ़ता है, तो असंगठित क्षेत्र पीछे बना रहता है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कोरोना काल के बाद जहां समाज के संपन्न वर्ग द्वारा अधिक खर्च करने के कारण महंगे सामान की मांग में वृद्धि हुई है, वहीं आमजन की जरूरत की वस्तुओं के बाजार की मांग में कमी आई है।

हालांकि सरकार और कुछ आर्थिक विश्लेषक 'के' आकार की वृद्धि के विचार को खारिज करते हैं। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक वृद्धि हो रही है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) में यह विभाजन स्पष्ट नजर आता है। यह सूचकांक विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि दरों का मापन करता है। वित्तवर्ष 2014 में आइआइपी 3.3 फीसद था, जो वित्तवर्ष जनवरी 2024 में बढ़कर 5.5 फीसद हो गया। इसमें वृद्धि मुख्य रूप से सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास हेतु किए जाने वाले खर्च, जो कि मुख्य रूप से इस्पात और सीमेंट आदि की मांग में वृद्धि के कारण हुई है। उपभोक्ता आधारित उद्योग जैसे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और गैरटिकाऊ जैसे खाद्य, परिधान, किराना आदि में बढ़ोतरी की दर कम हुई है या घटी है। असंगठित क्षेत्र महामारी के पहले के कारोबार वाली स्थिति में अब भी नहीं पहुंच पाया है और यह लगातार गिरावट की ओर है।

'सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनामी' (सीएमआइई) की रपट के अनुसार भीषण गर्मी और मानसून में देरी की वजह से रोजगार के लिहाज से जून 2024 का महीना असंगठित क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं रहा। खरीफ फसलों के बुवाई सीजन की शुरुआत में रोजगार की उम्मीद में 70 लाख से अधिक लोग जून में श्रम बाजारों में शामिल हुए, लेकिन उनमें अधिकांश को निराशा हाथ लगी। श्रम बाजारों ने उन्हें जोड़ने के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के बजाय विद्यमान रोजगार में भी कटौती कर दी। इससे रोजगार ढूंढ़ने वालों की संख्या और बढ़ गई। इसी प्रकार लगभग 90 लाख छोटे व्यापारी और दिहाड़ी मजदूर, जिनमें कृषि मजदूर भी शामिल थे, श्रम बाजार से बाहर हो गए।

देश के असंगठित श्रम बाजारों में कोरोना काल के बाद भारी उतार-चढ़ाव रहा है, इसकी दिशा अधिकांशतः नकारात्मक ही रही है। जून 2024 भी असंगठित क्षेत्र की दृष्टि से काफी मुश्किल भरा महीना रहा। इस अवधि में असंगठित क्षेत्र में कुल रोजगार में 28 लाख की गिरावट देखने को मिली और बेरोजगारों की संख्या करीब एक करोड़ बढ़ गई। इससे देश में बेरोजगारी दर जून में बढ़कर 9.2 फीसद तक पहुंच गई। रपट में कहा गया कि भीषण गर्मी के कारण रोजगार के लिहाज से निर्माण क्षेत्र को भी बड़ा झटका लगा है। इस क्षेत्र में जून में 1.7 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया। यह चिंताजनक है कि इस क्षेत्र में मार्च 2024 से ही रोजगार में लगातार गिरावट आ रही है। व्यावसायिक क्षेत्र में भी रोजगार में 50 लाख की गिरावट रही। इस नुकसान का अधिकांश असर ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ा। रपट के अनुसार असंगठित क्षेत्र की तुलना में संगठित क्षेत्र में नौकरियां बढ़ी हैं। जून 2024 में वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या 28 लाख बढ़ गई। यह वृद्धि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में हुई है।

> **देश में अमीर लोगों के और अमीर होने और गरीब लोगों के और गरीब होने की स्थिति आजादी से लेकर आज के दौर तक बनी हुई है। सभी सरकारों ने इस खाई को पाटने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बढ़ती आबादी और देश की बड़ी अर्थव्यवस्था में यह खाई आज तक बनी हुई है। इस दिशा में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योग जगत और सभी हित धारकों के मिले-जुले गंभीर प्रयासों की जरूरत है, तभी अर्थव्यवस्था स्वस्थ विकास की दिशा में अग्रसर हो सकती है और गरीब तथा अमीर के बीच की खाई को पाटा जा सकता है।**

संगठित क्षेत्र में पैदा हुए रोजगार को लेकर ईपीएफओ द्वार जारी पिछले चार वर्ष के आंकड़ों पर नजर डालें, तो वित्तवर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान 4.86 करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े हैं। एसबीआइ रिसर्च ने अपने आंकड़ों में बताया है कि दुबारा नौकरी पाने वाले या फिर से ईपीएफओ में पंजीकरण कराने वालों की संख्या 2.27 करोड़ रही। 'नेशनल पेंशन सिस्टम' यानी एनपीएस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तवर्ष 2022-23 में 8.23 लाख नए कर्मचारी नई 'पेंशन स्कीम' से जुड़े हैं। इसमें राज्य सरकारों के 4.64 लाख, गैर-सरकारी क्षेत्रों के 2.30 लाख और केंद्र सरकार के 1.29 लाख कर्मचारी जुड़े। इस प्रकार ईपीएफओ और एनपीएस से जो आंकड़ों मिले, उनके अनुसार संगठित क्षेत्र में 5.2 करोड़ से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, इनमें महिलाओं की भागीदारी लगभग 27 फीसद है।

रोजगार में कमी और वृद्धि के साथ आय में असमानता भी 'के' आकर वृद्धि की अवधारणा को बल देती है। 'इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च' के विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी जगत, जिसमें उच्च आय श्रेणी के शीर्ष 50 फीसद का प्रतिनिधित्व है, उसमें वित्तवर्ष 2022 में आय 11.6 फीसद, तो वित्तवर्ष 2023 में 10.7 फीसद बढ़ी, लेकिन कम आय श्रेणी वाले कृषि ग्रामीण मजदूरों और शहरी क्षेत्रों के कुशल कामगारों की मजदूरी में या तो कोई वृद्धि नहीं हुई या घट गई। शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी वित्तवर्ष 2022 में तीन फीसद घटी और वित्तवर्ष 2023 में 0.55 फीसद की कमी आई। कृषि आय, जो ग्रामीण मजदूरी का आईना होती है, वह भी वित्तवर्ष 2022 में 3.4 फीसद घटी और वित्तवर्ष 2023 में मात्र एक फीसद बढ़ी है।

संगठित और असंगठित क्षेत्र के रोजगार के आंकड़ों और विभिन्न आयवर्ग के व्यक्तियों में उपभोग उत्पादों की मांग में कमी और वृद्धि से मोटेतौर पर यही लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था में 'के' आकार की वृद्धि की दिशा में है, लेकिन अगर हम समग्र रूप से स्वाधीनता के 77 वर्षों में अर्थव्यवस्था की दिशा का अध्ययन करें, तो देश में अमीर लोगों के और अमीर होने और गरीब लोगों के और गरीब होने की स्थिति आजादी से लेकर आज के दौर तक बनी हुई है। सभी सरकारों ने इस खाई को पाटने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बढ़ती आबादी और देश की बड़ी अर्थव्यवस्था में यह खाई आज तक बनी हुई है। इस दिशा में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योग जगत और सभी हित धारकों के मिले-जुले गंभीर प्रयासों की जरूरत है, तभी अर्थव्यवस्था स्वस्थ विकास की दिशा में अग्रसर हो सकती है और गरीब तथा अमीर के बीच की खाई को पाटा जा सकता है।

सपनों का संजाल

दुनिया मेरे आगे

ललित शौर्य

सपनों की एक अलग दुनिया होती है। हर किसी को सपने देखना पसंद होता है। हर आयु वर्ग के लोगों के सपने अलग-अलग होते हैं। यह सिलसिला बच्चे के जन्म लेने के साथ ही शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि बच्चा जन्म लेने के बाद नींद में भी मुस्कराता है। होठों को हिलाता है। इसका मतलब है कि वह सपनों की दुनिया में खोया हुआ है। शायद उसे सपने में मां थपकी दे रही हो या दूध पिला रही हो, झूला झुला रही हो। यह सब महसूस कर वह उमंग में रहता है। थोड़ा बड़ा हो जाने पर उसे चाकलेट, परियों वगैरह के सपने आने लगते हैं। कई बच्चों को कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने या फिर क्रिकेट में छक्का मारने के भी सपने आते हैं। यह दौर चलता रहता है। तरुणाई के सपने अलग तरह के होते हैं। प्रेमी और प्रेमिकाओं के सपनों की उमंग कुछ और ही होती है। धीरे-धीरे इंसान जीवन के उस पड़ाव पर भी पहुंचता है, जब वह खुली आंखों से सपने देखने लगता है। इस दौर में यह क्रम जवानी से ही शुरू हो जाता है। जल्दी अमीर बनने के सपने, कम समय में अधिक ख्याति प्राप्त करने के सपने। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के मंचों की रील वाली दुनिया युवाओं को भी सपनों के रील में उलझाए हुए है। अब युवाओं के भीतर धैर्य, परिश्रम जैसे गुणों का लोप होता दिखाई दे रहा है। यह सब खुली आंखों से सपने देखने के कारण हो रहा है। सपने ऐसे, जिनकी हकीकत बनने की चाह तो है, लेकिन उसके लिए समर्पित होकर कार्य करने की क्षमता नहीं है, न ही उस क्षमता को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

गृहस्थी में रमे हुए मध्यवर्ग के दंपती के सपने भी उसे अपने भार से दबाए जा रहे हैं। अच्छा मकान, बड़ी गाड़ी, देशाटन, बैंक में पैसे के सपनों ने अवसाद को आमंत्रित कर दिया है। सीमित संसाधनों के साथ ये सब सपने खुली आंखों से देखे जा रहे हैं। फिर जब ये सब हकीकत में नहीं बदलता तो पारिवारिक कलह सामने आती है। इससे परिवार में टूटन और बिखराव देखने को मिल रहा है। इस सबसे बच्चों में अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कुछ दंपती यह सब प्राप्त करने के लिए ऋण लेकर घी पीने वाली प्रवृत्ति को अपनाते हैं। जो कुछ समय के लिए सुखद अहसास तो देता है, लेकिन उसके परिणाम सदैव सुखद नहीं होते। आज बड़े-बड़े महानगरों में रहने वाले युवा दंपती अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति रख रहे हैं। मासिक किस्त और ऋण के दम पर सारे शौक पूरे किए जा रहे हैं।

> **जीवन की राह में सपनों का अनियंत्रित हो जाना दुर्घटना को आमंत्रित करने जैसा है। इस दौर में हर आयु वर्ग के लोगों को जीवन की रफ्तार को थोड़ा-सा विराम देकर विचार करने की जरूरत है। यह बेवजह की रफ्तार हमसे हमारा सुकून छीन रही है। हमारे भीतर अनेक तरह के विकारों को जन्म दे रही है।**

ऐसे लोग अपने भविष्य से अनजान हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रहीं हैं, जो पीड़ादायक हैं। जो सभ्य समाज और बुद्धिजीवी समाज के लिए बड़ा प्रश्नचिह्न हैं। सपनों को टूटता देख, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा न कर पाने पर दंपती आत्महत्या जैसा त्रासद कदम उठा रहे हैं। पिछले दिनों इन्हीं सब कारणों से एक इंजीनियर ने उफनती नदी में कूदकर अपनी जीवनलीला को समाप्त कर लिया। यह सब सपनों की अति के कारण है। सपने देखना अच्छी बात है। उन सपनों के लिए प्रयास करना उससे भी अच्छी बात है। लेकिन सपनों के पूरा न होने पर टूट कर बिखर जाना सबसे बुरी बात है। हमें संयम, समझ और धैर्य से काम लेना चाहिए। सीमित संसाधनों में कैसे खुशी को खोजा जा सके ऐसा उपक्रम करना चाहिए।

हमारे पूर्वजों ने जो जीवन पद्धति हमें विरासत में दी, हमने उसको जीवन में आत्मसात नहीं किया। हमने उसे भुलाकर सिर्फ उपभोग के पीछे भागते रहने का सिद्धांत अपना लिया। आज हम आत्मनियंत्रण जैसे विचारों को छोड़ चुके हैं। जब हम आत्मनियंत्रित होकर कार्य करेंगे तो निश्चित ही सारे संकटों से बचे रहेंगे। सपनों की अप्रतिम शाखाओं में झूलने का मन सभी का करता है, लेकिन उन शाखाओं में इतना भार न पड़े कि वे टूटकर बिखर जाने लगें और हम कोई गलत कदम उठा बैठें। जीवन में सपनों की अति से बचना अति आवश्यक है। इच्छाओं के अप्रतिम विस्तार से बचना चाहिए। चाह की भूख कभी खत्म नहीं होती। प्रतिपल बढ़ती ही जाती है।

सपनों की अति के पीछे भागना एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही चली जाती है। बिना लक्ष्य के अप्रतिम आकांक्षाओं के साथ भगाना कहां की बुद्धिमत्ता है? आज के इस दौर में सपनों के मकड़जाल में महानगर से लेकर गांव, कस्बों तक के लोग फंसे हुए हैं, जो इससे बाहर निकलने का उपक्रम नहीं कर पाते। जीवन में लक्ष्य बड़े होने आवश्यक हैं, लेकिन जो प्राप्त है, वही पर्याप्त है। उस विचार का अनुगमन करना भी आवश्यक है। अन्यथा हम स्वयं ही कलह, विशाद, बेचैनी और अवसाद को आमंत्रित कर बैठेंगे। जीवन की राह में सपनों का अनियंत्रित हो जाना दुर्घटना को आमंत्रित करने जैसा है। इस दौर में हर आयु वर्ग के लोगों को जीवन की रफ्तार को थोड़ा-सा विराम देकर विचार करने की जरूरत है। यह बेवजह की रफ्तार हमसे हमारा सुकून छीन रही है। हमारे भीतर अनेक तरह के विकारों को जन्म दे रही है। इन विकारों का मर्दन संयमित जीवन चर्या से ही संभव है। इस दौर में आत्मवालोकन की जरूरत सबसे ज्यादा है। बेवजह के सपनों के बोझ तले जीवन के उमंग और आनंद को दबने देने से बचाना होगा।

चौपाल

शांति की राह

आज भारत शांति की ज्यादातर उस प्रक्रिया में शामिल है, जिससे विश्व में शांति एवं समृद्धि आए। भारत की नीति हमेशा से गुटनिरपेक्षता की रही है। इसलिए आज भारत किसी के दबाव में कार्य नहीं करता, बल्कि दूसरों को अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर कर देता है। भारत हमेशा से कूटनीति, संवाद और आपस में साथ बैठकर बातचीत का समर्थन करता है। बात चाहे वर्ष भर से ज्यादा चले आ रहे यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध ही क्यों न हो। असल में यह युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच जितना है, उससे ज्यादा यह रूस और अमेरिका के बीच लगता है। यूक्रेन सिर्फ इसमें युद्धभूमि है, इसका अंदाजा अब ज्यादातर लोग लगा पा रहे हैं। भारत इकलौता देश है, जिस पर इस युद्ध से जुड़ा हर पक्ष भरोसा कर रहा है। वह भारत ही है, जो पूरी दुनिया के सामने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से यह कह पाता है कि यह युद्ध का समय नहीं है। तब दुनिया ध्यान से सुनती भी है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ा है। उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म कराने में भारत की मजबूत भूमिका सामने आएगी।

– समराज चौहान, कार्बी आंग्लांग, असम

संवेदनशीलता की जगह

आज की शिक्षा के प्रति पालकों और उनके बालकों में केवल ज्ञान और नौकरी की ललक दिखाई देती है, जबकि शिक्षा प्राप्ति का मूल उद्देश्य मानव को सहृदय बनाना है। मगर कुछ घटनाएं बताती हैं कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान परोसा जा रहा है, जिससे उनमें संवेदनशीलता नजर नहीं आती। दिल्ली के दयालपुर के एक मदरसे में घटित घटना बताती है कि तालीम आखिर किस दिशा में जा रही है। इस विद्यालय के तीन बच्चों ने एक अन्य बच्चे की हत्या सिर्फ इसलिए कर डाली कि स्कूल की छुट्टी घोषित हो सके। निश्चित रूप से यह घटना बच्चों में संवेदनहीनता का परिणाम है, जहां उन्हें प्रेम, प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे के प्रति अपनी जवाबदेही से वंचित रखा जाता है। नाबालिग बच्चों को सजा उनका भविष्य बर्बाद करेगी, पर उन्हें अपराध बोध के लिए दंडित किया जाना भी जरूरी है। यों एक सभ्य समाज में बच्चों को हत्या जैसे अपराध के लिए दंडित किया जाए, यह दुखद है।

– अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

आश्चर्य के बजाय

हाल ही में आई एडीआर की रपट के अनुसार देश के 151 सांसद और विधायकों के ऊपर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले दर्ज हैं। 'दागी नुमाइंदे' (संपादकीय, 23 अगस्त) पढ़ा। सभी नुमाइंदे सियासी आरोप के शिकार नहीं हो सकते, बल्कि कुछ तो अपराधी पृष्ठभूमि के हैं भी, लेकिन हमारी लचर कानूनी प्रक्रिया और सियासी हस्तक्षेप के कारण समय पर कोर्ट का निर्णय नहीं हो पाता और आरोपी को अपराधी घोषित करना लंबित रहने से ऐसे लोग चुनाव जीत कर पुनः सांसद या विधायक बन जाते हैं। अभी तक कठोर कार्रवाई इसीलिए नहीं हो सकी, क्योंकि इनमें सभी दलों के नुमाइंदे हैं, वरना पुरजोर विरोध होता और किसी तरह से इन्हें पदच्युत या टिकट नहीं मिलती या इनको जेल में डाल देते और कठोर कानून भी बन जाता। आरोपियों की संख्या और लंबित प्रकरणों पर तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।

– बीएल शर्मा 'अकिंचन', उज्जैन

कर्ज के बरक्स

किसी समय मुफ्त की रेवड़ी कही जाने वाली विभिन्न सरकारी योजनाएं आजकल देश की नई संस्कृति बन गई है। लगभग सभी दलों द्वारा नाम बदल कर ऐसी योजनाओं के नाम पर मुफ्त की रेवड़ियां वितरित की जा रही हैं। कोई भी सरकार या पार्टी अपनी ओर से इन योजनाओं का खर्चा वहन नहीं करती, बल्कि यह सब पैसा जनता से ही वसूल किया जाता है। वर्तमान समय में विभिन्न सरकारें कर्ज के भयंकर बोझ तले डूबी हुई हैं, लेकिन कोई भी इस रोग पर प्रभावी रोक लगाकर अपने गले में घंटी बांधना नहीं चाहता। मुफ्त की रेवड़ियों के बजाय उत्पादकता और रोजगार के सृजन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। कमाई बढ़ाकर ही देश की जनता को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इस प्रकार राज्य और केंद्र सरकार पर कर्जे के बोझ को भी कम किया जा सकता है।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

चुनाव जनता से संबंधित हैं। यदि वह इनसे मुंह मोड़ती है, तो यह खुद को आग में जलाकर फफोलों पर बैठने जैसा होगा। -अब्राहम लिंकन

शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार वायु की गुणवत्ता सुधारने के विभिन्न प्रयासों का असर जमीनी स्तर पर दिखना शुरू हुआ है। लेकिन इस संबंध में मुंबई स्थित अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है, जो संकेत देता है कि वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई।

हवा, जहर और जंग

शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट, 'वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक, 2024' का यह बताना कि भारत में 2021 की तुलना में 2022 में वायु प्रदूषण में 19.3 फीसदी की महत्वपूर्ण कमी आई है, जिससे हर भारतीय की जीवन प्रत्याशा में औसतन 51 दिन का इजाफा हुआ है, इस संदर्भ में अपनाई जा रही नीतियों व प्रयासों में ठोस प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेत है। रिपोर्ट में भारत और दूसरे दक्षिण एशियाई देशों में पार्टिकुलेट प्रदूषण में कमी का एक प्रमुख कारण अनुकूल मौसम बताया गया है। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में केंद्र व राज्य सरकारों ने वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जो अब जमीनी स्तर पर अपना असर दिखा रही हैं। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के अलावा 2019 में शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम भी है, जिसका लक्ष्य 2026 तक 2017 के प्रदूषण-स्तर को 40 फीसदी तक कम करना है। हालांकि इसके साथ रिपोर्ट चेतावनी भी देती है कि अगर देश पांच ग्राम प्रति घन मीटर वाले पीएम 2.5 कणों की सांद्रता के वार्षिक मानक को पूरा नहीं करता है, तो लोगों की जीवन प्रत्याशा में करीब साढ़े तीन साल की कमी होने की भी आशंका है। मुंबई के अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान का हालिया शोध भी बताता है कि पीएम 2.5 कणों की अधिकता की वजह से जहरीली हो रही हवा के कारण नवजात शिशुओं में जोखिम करीब 86 फीसदी, तो पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में यह जोखिम करीब सौ से 120 फीसदी तक बढ़ गया है। मुंबई स्थित संस्थान की रिपोर्ट का यह बताना चिंतित करता है कि यह खतरा उन घरों में ज्यादा है, जहां अलग से रसोई नहीं है। दरअसल, रिपोर्ट पीएम 2.5 कणों और मृत्यु दर में मजबूत संबंध को दर्शाती है, जो उत्तर भारत में ज्यादा है, जहां पराली जलाने और औद्योगिक कचरे के उत्सर्जन के मामले ज्यादा दिखते हैं। हालांकि शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत आने वाले शहरों में पीएम 2.5 में 19 फीसदी की गिरावट आई है, जो एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन इसे स्थायी बदलाव में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। प्रदूषण के स्रोतों को नियंत्रित करने, खासकर कोयले के जलने, वाहनों के उत्सर्जन और औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि मानव जनित पीएम 2.5 उत्सर्जन को कम किया जा सके। यह भी समझना होगा कि अब तक के प्रयासों के रंग सामने जरूर आए हैं, लेकिन वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।

क्या जम्मू-कश्मीर में स्थिरता आएगी

जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा ने छह साल के केंद्रीय शासन के बाद लोकतंत्र की वापसी की उम्मीद जगा दी है। लेकिन माहौल में उत्साह के बावजूद एक सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या जम्मू-कश्मीर में स्पष्ट जनादेश आएगा? या फिर खंडित लोकतांत्रिक आकांक्षाए लोगों को परेशान करती रहेंगी?

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा ने छह साल के केंद्रीय शासन के बाद लोकतंत्र की वापसी की उम्मीद जगा दी है। इन दिनों राजनीतिक गतिविधियों से यह इलाका गुलजार है, क्योंकि पार्टियां गठबंधन बनाने और तीन चरणों में होने वाले मतदान के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुटी हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा आगामी चार अक्तूबर को की जाएगी। हालांकि माहौल में उत्साह के बावजूद एक सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या जम्मू-कश्मीर में स्पष्ट जनादेश आएगा? या फिर राजनीतिक अनिश्चितता और खंडित लोकतांत्रिक आकांक्षाएं लगातार जम्मू-कश्मीर के लोगों को परेशान करती रहेंगी?

आरती आर जेरथ
राजनीतिक विश्लेषक

अगले महीने होने वाले चुनावी समर की रेखाएं खींची जा रही हैं, लेकिन जो तस्वीर उभर रही है, वह अस्पष्ट एवं भ्रमित करने वाली है। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू-कश्मीर में स्थापित राजनीतिक प्रतिमान बिखर गया। लेकिन केंद्र के पांच साल के शासन और भाजपा के वैचारिक प्रयोगों के बाद भी इस क्षेत्र में कोई नई व्यवस्था नहीं बन पाई है।

यदि हाल में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान देखे गए रुझानों पर गौर करें, तो कई कारक मुख्यधारा की क्षेत्रीय पार्टियों-नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए स्थिति को बिगाड़ सकते हैं, और देश के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य में भाजपा की सरकार बनाने की योजना को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनमें से एक कारक है, जेल में बंद अलगाववादी नेता इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) का मैदान में उतरना। इंजीनियर रशीद की बारामुला में शानदार जीत, जहां उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराया, ने उनकी नई पार्टी को घाटी में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है। एआईपी ने अभी यह तय नहीं किया है कि वह कितनी सीटों पर लड़ेगी, लेकिन शुरुआती संकेत हैं कि वह कश्मीर की 47 सीटों में से 30-35 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है।

इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद ने शिक्षक की सरकारी नौकरी छोड़ दी है और वह चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं, जबकि उनका बेटा अबरार रशीद चुनाव प्रचार का नेतृत्व करेगा, जैसा कि उसने लोकसभा चुनाव में अपने पिता के लिए किया था। इंजीनियर रशीद ने खुद पैरोल के लिए अर्जी दी है, ताकि वह चुनाव में हिस्सा ले सकें। यदि एआईपी कश्मीरी युवाओं में लोकसभा चुनाव की तरह ही उत्साह पैदा करने में सफल हो जाती है, तो इससे लगभग निश्चित रूप से विधानसभा में किसी को बहुमत नहीं मिलेगा और अलगाववादियों को राजनीतिक वैधता मिल जाएगी, जिससे कश्मीर में हालात पूरी तरह से बदल सकते हैं।

यह एक ऐसा परिदृश्य है, जिससे भाजपा चिंतित है। जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने की उम्मीदों को तोड़ने के अलावा, इंजीनियर राशिद भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान यह उम्मीद की गई थी कि वह उमर अब्दुल्ला के वोटों में सेंध लगाएंगे और भाजपा के सहयोगी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन के लिए बारामुला सीट जीतने का रास्ता साफ करेंगे। लेकिन इंजीनियर राशिद ने दोनों को हराकर भारी बहुमत से जीत हासिल की, जिससे उमर अब्दुल्ला को खत्म करने और उनकी जगह एक 'मित्रवत' सांसद को लाने की भाजपा की सुविचारित रणनीति पर पानी फिर गया। सज्जाद लोन तीसरे स्थान पर रहे।

बहरहाल, यह देखना अभी बाकी है कि एआईपी विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही उत्साह पैदा कर पाती है या नहीं, लेकिन भाजपा को समझना चाहिए कि उसने लोकसभा चुनाव के समय कश्मीर में लोकप्रिय मूड को पूरी तरह से गलत समझा। उसे गलत धारणाओं के आधार पर भविष्य की रणनीति नहीं बनानी चाहिए। भाजपा के लिए दुखद है कि जम्मू में भी स्थिति अनिश्चित है। जम्मू को भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे पर बारीकी से नजर डालें, तो चिंताजनक तस्वीर नजर आती है। हालांकि भाजपा जम्मू की दोनों संसदीय सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन विधानसभा क्षेत्रों में उसका प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं है।

जम्मू में भाजपा की मुश्किलें विधानसभा उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची को तुरंत वापस लेने से स्पष्ट हैं। भाजपा ने पहले 44 नामों की सूची जारी की, लेकिन कुछ ही घंटों में उसे वापस ले लिया। दूसरी सूची में सिर्फ 15 नाम थे। जाहिर है, पुराने चेहरों को हटाकर उनकी जगह नए लोगों को लाने के फैसले के कारण पार्टी में विद्रोह की स्थिति बन गई है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में एकतरफा प्रयोगों से लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाने के बाद भाजपा नेतृत्व अब कोई जोखिम लेना नहीं चाहता। विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए भाजपा को जम्मू की सभी 43 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, जो कि एक कठिन काम है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन तय कर लिया है। दोनों पार्टियां 83 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगी, जबकि पांच सीटों पर अलग-अलग अपने उम्मीदवार उतारेंगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन के बाद तय हो गया है कि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी अकेले चुनाव लड़ने के लिए मजबूर है, उसने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। भाजपा भी अकेले चुनाव लड़ने का इरादा रखती है। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट न जीत पाने के बाद पीडीपी का फिलहाल कोई भविष्य नहीं दिख रहा है।

हाल के वर्षों में उभरी अन्य पार्टियों की बात करें, तो वे धीरे-धीरे खत्म होती जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में लोन की पार्टी के साथ ही एक अन्य पार्टी 'अपनी पार्टी' का प्रदर्शन भी खराब रहा, जिससे भाजपा को काफी उम्मीदें थीं। कांग्रेस के पूर्व दिग्गज गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी भी एक और विफल पार्टी है। लोकसभा चुनाव में इसके तीनों उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। चर्चा है कि कुछ वरिष्ठ नेता कांग्रेस में वापसी के लिए प्रयासरत हैं। इसी बिखरी पृष्ठभूमि में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा जम्मू पर मंडरा रहे आतंकी खतरे को भी जोड़ लें, जहां जून से अब तक नौ हमले हो चुके हैं, तो आगे की चुनौतियां विकट हैं। हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव लड़ने वाली पार्टियां परिपक्वता और बुद्धिमत्ता के साथ चुनाव लड़ेंगी और विभाजनकारी राजनीति के जरिये जम्मू-कश्मीर को बर्बादी के कगार पर नहीं धकेलेंगी।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

महात्मा गांधी

आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं और उसे नहीं जीते हैं, तो आप स्वयं के साथ बेईमानी कर रहे हैं। खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। लेकिन अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा भरोसा करना एक प्रकार से मूर्खता ही है।

अपने शब्दों को संभालें और कार्यों पर विचार करें

पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। मनुष्य के रूप में हमारी सबसे बड़ी क्षमता दुनिया को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को बदलना है। अपने विचारों पर ध्यान से नजर रखें, क्योंकि वे आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों को संभालें और देखें, क्योंकि वे आपके कार्य बन जाएंगे। अपने कार्यों पर विचार करें और उनका मूल्यांकन करें, क्योंकि वे आपकी आदतें बन जाएंगे। अपनी आदतों को पहचानें और देखें, क्योंकि वे आपके मूल्य बन जाएंगे। अपने मूल्यों को समझें और अपनाएं, क्योंकि वे आपकी नियति बन जाते हैं। जब भी निराशा सामने हो, तो एक बात हमें जरूर याद कर लेनी चाहिए कि पूरे इतिहास में सत्य और प्रेम का मार्ग हमेशा विजयी रहा है। एक समय ऐसा भी आता है, जब कुछ समय के लिए अत्याचारी और हत्यारे हमें अजेय लग सकते हैं, लेकिन अंत में वे हमेशा हार जाते हैं। आप कभी नहीं जान सकते कि आपके कार्यों का क्या परिणाम आएगा, लेकिन यदि आप कुछ नहीं करेंगे, तो कोई परिणाम नहीं आएगा। क्योंकि मनुष्य अक्सर वही बन जाता है, जो वह खुद को मानता है। अगर मैं खुद से कहता रहूं कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, तो संभव है कि मैं अंत में उसे करने में असमर्थ हो जाऊं। इसके विपरीत, अगर मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से इसे करने की क्षमता हासिल कर लूंगा, भले ही शुरुआत में मेरे पास यह क्षमता न हो। वह परिवर्तन स्वयं बनें जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।

जीवन ऐसे जीना चाहिए जैसे कि हम कल ही मरने वाले हों और ऐसे सीखना चाहिए जैसे कि हम हमेशा जीने वाले हों। इस संसार में बदले की भावना हमें बर्बाद कर देती है। आंख के बदले आंख लेने से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। कमजोर लोग कभी माफ नहीं कर सकते हैं। असल में माफी मजबूत लोगों का गुण है। अगर आपके कार्य से किसी एक हृदय में खुशी उत्पन्न होती है, तो वह प्रार्थना में झुके हजारों सिरों से बेहतर है। आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं और उसे नहीं जीते हैं, तो आप स्वयं के साथ बेईमानी कर रहे हैं। खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। लेकिन अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा भरोसा करना एक प्रकार से मूर्खता ही है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो सबसे मजबूत व्यक्ति है, वह भी एक दिन कमजोर पड़ सकता है और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी गलती कर सकता है। हमारे समाज में वैसे अज्ञानी लोग हैं, जो आपकी निंदा करेंगे और आपके सत्य बोलने पर वे लोग आपको दंडित करना चाहेंगे। अगर आप सही हैं और आपको पता है, तो किसी अज्ञानी के कहने पर कभी भी माफी नहीं मांगें। आप कितने ही कमजोर क्यों न हों, क्योंकि सच तो सच ही है। मैं उसे धार्मिक कहता हूं, जो दूसरों की पीड़ा को समझता हो।

मानवता पर भरोसा रखें

सूत्र

भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। साल में दो दिन ऐसे होते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते, बीता और आने वाला कल। हमें मानवता पर भरोसा नहीं खोना चाहिए। मानवता एक महासागर है, यदि इसकी कुछ बूंदें गंदी हैं, तो महासागर गंदा नहीं हो जाता। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से हजार गुना प्रभावी होती है।

दूसरा पहलू

एक अध्ययन इस परिकल्पना में पुख्ता सबूत जोड़ता है कि घातक चट्टान मूल रूप से बृहस्पति ग्रह की कक्षा से परे बनी थी।

डायनासोर युग समाप्त करने वाले पिंड का रहस्य

वैज्ञानिकों ने इस बात के नए सबूत खोजे हैं कि 6.60 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर टकराई वह चट्टान थोड़ी अजीब थी, जिससे डायनासोर युग अचानक समाप्त हो गया था। इसे चिक्सुलब टक्कर के नाम से जाना जाता है। लंबे समय से बहस चल रही है कि क्या यह चट्टान धूमकेतु थी या क्षुद्रग्रह। लेकिन हाल के वर्षों में इस बात के पुख्ता सुबूत मिले हैं कि लगभग छह मील चौड़ा यह पिंड क्षुद्रग्रहों के एक परिवार से संबंधित था।

अब जर्मनी में कोलोन विश्वविद्यालय के डॉ. मारियो फिशर गोडे की अगुवाई में वैज्ञानिकों की टीम ने दुर्लभ रूथेनियम तत्व की मदद से साबित किया है कि यह चट्टान क्षुद्रग्रह ही थी, क्योंकि रूथेनियम क्षुद्रग्रहों में प्रचुर मात्रा में है, लेकिन पृथ्वी की परत पर बेहद दुर्लभ है। दरअसल, टीम ने चिक्सुलब टक्कर के भूवैज्ञानिक अवशेषों में रूथेनियम के आइसोटोप की खोज की। वैज्ञानिकों को इसके प्रभाव से छोड़ी गई परत पर एक जैसे निशान मिले हैं। साइंस में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, ये निशान अपनी उच्च कार्बन सामग्री के कारण कार्बनयुक्त क्षुद्रग्रहों के रूप में पहचाने जाने वाली अंतरिक्ष चट्टानों के एक समूह की संरचना से स्पष्ट रूप से मेल खाते हैं। डॉ. गोडे कहते हैं कि ये रूथेनियम आइसोटोप निशान कार्बोनेसियस क्षुद्रग्रह के अलावा और कुछ नहीं हो सकते हैं। पिछले अध्ययनों ने के-पीजी सीमा में रासायनिक निशानों का पता लगाया है, जो गैर-एवियन डायनासोर और पृथ्वी पर अन्य सभी प्रजातियों के लगभग दो तिहाई की मौत में एक कार्बनयुक्त क्षुद्रग्रह को भी शामिल करता है।

बेकी फरीरा

टीम ने चट्टान के भूवैज्ञानिक अवशेषों में रूथेनियम के आइसोटोप की खोज की और इसके प्रभाव से छोड़ी गई परत पर एक जैसे निशान मिले हैं।

चिक्सुलब टक्कर ने डायनासोरों को नष्ट कर दिया, लेकिन इसने मनुष्यों सहित स्तनधारियों के उदय को भी सक्षम बनाया, तो हम उस दुष्ट क्षुद्रग्रह के प्रति कुछ हद तक कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं।

डॉ. गोडे की टीम ने पिछले 5.41 करोड़ वर्षों में हुए पांच अन्य क्षुद्रग्रह प्रभावों के नमूनों में रूथेनियम को मापा। उनके अनुसार, डायनासोर युग को समाप्त करने वाली चट्टान सूर्य के करीब बनी है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट में केंद्रित है। चिक्सुलब प्रभाव के विशेषज्ञ डेविड क्रिंग का कहना है कि चिक्सुलब प्रभाव के साथ-साथ पृथ्वी पर जीवन के उद्भव और विकास में क्षुद्रग्रह हमलों की व्यापक भूमिका के बारे में कई रहस्य बने हुए हैं। क्षुद्रग्रहों ने अतीत में पृथ्वी पर अनगिनत प्रजातियों को नष्ट कर दिया है, लेकिन उन्होंने पृथ्वी को पानी और जीवन के लिए अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान करने में भी मदद की होगी। चिक्सुलब टक्कर ने डायनासोरों को नष्ट कर दिया, लेकिन इसने मनुष्यों सहित स्तनधारियों के उदय को भी सक्षम बनाया, तो हम उस दुष्ट क्षुद्रग्रह के प्रति कुछ हद तक कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं।

©The New York Times 2024

आंकड़े

जनधन योजना

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत दस वर्षों में 53 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं। इससे निजी से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तक लोगों की पहुंच आसान हुई है।

कुल खाते	53.13
कुल जमा रुपये	231235.97
डेबिट कार्ड जारी	36.14
महिला खाते	29.56

आंकड़े करोड़ में हैं। 14 अगस्त, 2024 को जारी रिपोर्ट के आधार पर। स्रोत : pmjdy.gov.in

युधिष्ठिर हिमालय पर चढ़ रहे थे, तब उनके साथ एक कुत्ता भी था। युधिष्ठिर को लेने के लिए इंद्र आए, तो उन्होंने कहा, 'कुत्ता मेरा सच्चा साथी है, इसे नहीं छोड़ सकता।'

युधिष्ठिर ने शरणागत को नहीं छोड़ा

धर्मराज युधिष्ठिर का संसार में कोई भी शत्रु नहीं था। इसलिए उनका दूसरा नाम अजातशत्रु भी है। युधिष्ठिर स्वभाव से ही निर्वैर, अक्रोधी, क्षमाशील, धैर्यवान, सत्यवादी, विद्वान, शांत, त्यागपरायण और समदर्शी थे। महाभारत का युद्ध जीत लेने पर वह महाराज बने, लेकिन राजकाज में उनका चित्त नहीं लगा। अंत में वह विरक्त होकर द्रौपदी और अपने चारों भाइयों के साथ हिमालय चले गए।

वह जब हिमालय पर चढ़ रहे थे, तो क्रमशः द्रौपदी, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सभी एक-एक कर बर्फ से फिसलकर गिर गए। युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। एक कुत्ता साथ में था, वह नहीं गिरा। अंत में देवराज इंद्र रथ लेकर आए और बोले-आप इस रथ पर बैठकर सशरीर स्वर्ग चलें। युधिष्ठिर ने कहा, 'मैं अपने इस सच्चे साथी कुत्ते को छोड़कर अकेला स्वर्ग नहीं जाऊंगा।' देवराज ने उन्हें बहुत समझाया कि कुत्ता भला स्वर्ग में आपके साथ कैसे जा सकता है? लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी बात नहीं छोड़ी। वह बोले, 'मैंने कभी धर्म नहीं छोड़ा है, मैं शरणागत को नहीं छोड़ सकता, स्वर्ग छोड़ सकता हूं।' उनकी धर्म में ऐसी निष्ठा देखकर कुत्ता अपने असली रूप में प्रकट हो गया, असल में कुत्ते के रूप में साक्षात धर्मराज थे, वह युधिष्ठिर को अपनी गोदी में बिठाकर सशरीर स्वर्ग ले गए। तभी तो कहा है कि 'धर्मो विवर्धति युधिष्ठिरकीर्तनेन।' अर्थात धर्मराज युधिष्ठिर के गुणगान से धर्म में वृद्धि होती है।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला पुराने पन्नों से — 15 अगस्त, 1958

विमान दुर्घटना में 99 लोगों की मौत

विमान दुर्घटना में ९९ व्यक्ति मारे गये
आयर के समुद्र में डच विमान गिरा

हॉलैंड (अब नीदरलैंड) की शाही हवाई कंपनी केएलएम का एक सुपर कांस्टेलेशन वायुयान आयरलैंड में दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर गया। वायुयान में 91 यात्री और आठ चालक सवार थे।

संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण का सवाल

330 ईस्वी के फारस से लेकर आज के बांग्लादेश तक सभ्यता और संस्कृति के प्रतीकों को नष्ट करने का सिलसिला जारी है।

इंद्र कांत मिश्र

मुद्दा

बांग्लादेश की अशांति से समूचा विश्व इस बात को लेकर चिंतित है कि वहशी भीड़ ने आखिर उन लोगों को क्यों निशाना बनाया, जो जिम्मेदार नागरिक होने के साथ देश के विकास में किसी न किसी रूप में अपना योगदान कर रहे थे। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि उन्मादी अपनी ही धरोहर और संस्कृति को नष्ट करने पर आमादा हैं। इन्हें समझ नहीं है कि पुरातात्विक महत्व की अमूल्य वस्तुओं को जलाकर वे अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं। धरोहर, पर्यटन और अर्थ, तीनों एक-दूसरे से जुड़े हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था धरोहरों पर ही निर्भर है। इससे उन्हें क्या हासिल होने वाला है?

आखिर क्या मिला प्रख्यात लोकगायक राहुल आनंद के 140 साल पुराने घर पर हमला कर और उनके तीन हजार से ज्यादा दुर्लभ वाद्ययंत्रों को जला देने से? कई देशों से ये वाद्ययंत्र उन्होंने संकलित किए थे। घर के एक कमरे को राहुल ने संग्रहालय में तब्दील कर दिया था। कमरे में ही उनका 'जोलेर गान' ग्रुप अभ्यास और रिकॉर्डिंग करता था। वह किसी तरह पत्नी और बेटे को लेकर पीछे के दरवाजे से निकल सके। अन्यथा भीड़ फिल्म निर्माता सलीम खान और उनके बेटे शांतो खान की तरह उनका भी वही हाल कर सकती थी। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ दिया। जब हम किसी शहर में जाते हैं, तब किसी न किसी महान हस्ती की प्रतिमा देखने को मिल जाती है। यह कालांतर में धरोहर बन जाती है। भीड़ ने इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र पर हमला किया। सुनामगंज में बंगबंधु लिबरेशन वॉर म्यूजियम में रखीं दुर्लभ तस्वीरों और दस्तावेजों आदि को क्षति पहुंचाई।

ढाका एक शहर ही नहीं, बल्कि दुनिया के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में से एक रहा है। धन संपदा क्षति की भरपाई हो सकती है, लेकिन धरोहर और पुरातात्विक वस्तुओं की नहीं। सभ्यता और संस्कृति को तहस-नहस करने का सिलसिला दुनिया में सैकड़ों वर्षों पहले से चला आ रहा है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर गठित किए जाने के बाद भी इसे रोकने के ठोस उपाय नहीं किए गए। धरोहर नष्ट करने की पहली घटना इतिहास में 330 ईस्वी की मिलती है, जब सिकंदर ने फारस की राजधानी पर्सेपोलिस पर हमला कर वहां की सभ्यता को भारी क्षति पहुंचाई। भारत में खिलजी, गुलाम, तुगलक, मुगल और फिर अंग्रेज हुकूमत ने यही किया। अंग्रेजों ने तो मुगलों की कई इमारतों के प्रमुख हिस्सों को तोड़कर अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया। लाल किले में रंग महल को सैनिकों की रसोई में तब्दील कर दिया। वर्ष 1193 में दीन मुहम्मद बिन अख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्षति पहुंचाई।

ओपियम युद्ध के दौरान वर्ष 1860 में ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं ने चीन के युवानमिंगयुन स्थित ग्रीष्मकालीन शाही महल में आग लगा दी और वहां रखीं कलाकृतियां, स्वर्ण व चांदी जड़ित कलात्मक वस्तुएं लूट ले गईं। 14 अगस्त, 1900 को चीन में बॉक्सर विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली के 19 हजार सैनिकों ने बीजिंग पर कब्जा कर पुरातात्विक महत्व की हजारों वस्तुएं लूटीं। ऐसी कई घटनाओं के बाद 1899 में हेग सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मसौदा तैयार कर सभी देशों से अपील की गई कि युद्ध के दौरान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थलों और स्मारकों को क्षति नहीं पहुंचाएं। हालांकि इस समझौता पत्र पर बेनिन और चीन ने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान नाजियों ने सोवियत संघ और पोलैंड में कला व संस्कृति से संबंधित वस्तुएं लूटीं और जर्मनी ले जाकर तहस-नहस कर दीं। 1917 में रूस की बोल्शेविक हुकूमत ने महलों, संग्रहालयों, चर्चों से प्राचीन कलाकृतियां जब्त कर लीं। चीन में माओत्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सत्ता ने 1966 में मठों, म्यूजियम आदि पर पहरा बिठा दिया। कम्युनिस्ट सत्ता ने सबसे ज्यादा क्षति तिब्बत में पहुंचाई। 1949 से पहले तक यहां छह हजार से अधिक मंदिर और मठ थे, अब केवल 13 बचे हैं। 2012 में इस्लामी आतंकियों ने माली के टिंबुकटू शहर पर हमला कर ज्यादातर समाधियां नष्ट कर दीं। अफगानिस्तान में बामियान स्थित बुद्ध की विशाल प्राचीन प्रतिमा को तालिबान ने विकृत कर दिया। रूस और फ्रांस क्रांति में भी यही हुआ।

अब प्रश्न यह उठता है कि इन अमूल्य संपदाओं को कैसे स्थायी तौर पर संरक्षित किया जाए? वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की भूमिका धरोहरों की सूची बनाने तक सीमित है। वहशी भीड़ का शिकार ये न बनें। संरक्षण का काम संबंधित देश की सरकारों का है। ध्यान देने की बात है कि जब हमलावर भारी पड़ते हैं, तब सरकारें भी लाचार हो जाती हैं। चूंकि इस मामले में सभी देश प्रभावित रहे हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र को ठोस और प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। धरोहरों को क्षति पहुंचाने के कृत्यों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

चिंतन

बंगाल में जीवन का हिस्सा क्यों बनती जा रही है हिंसा

अपराध व हिंसा देश के किसी भी राज्य में हो सकते हैं और उस पर तुरंत काबू भी पा लिया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं मूलतः राजनीतिक प्रकृति की होती हैं। हिंसा हमेशा से बंगाल के इतिहास का अभिन्न अंग रही है। समय के साथ-साथ हिंसा के स्वरूप में भी बदलाव आते रहे हैं। कभी राजनीतिक हिंसा तो कभी जमीन बचाने की जंग। कभी सत्ता से टकराव की हिंसा तो कभी अपराध से निपटने की असफलता पर उपद्रव। जैसे समय के साथ विरोध और विद्रोह का चेहरा बदलता है, वैसे ही हिंसा का चेहरा भी बदलता है। औपनिवेशिक शासन के दौरान बंगाल में जो हिंसा देखी गई, उसने स्वतंत्रता के बाद के दौर में अपना रूप बदल लिया। इस अवधि में हिंसा सड़क पर युद्ध और माफिया अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के रूप में प्रकट हुई। इसमें जबरन वसूली और अनौपचारिक करों में वृद्धि हुई। हिंसा के इस बदले हुए रूप में योगदान देने वाला अन्य कारक एक विशेष प्रकार का विकास मॉडल था जो इस अवधि में आकार लेना शुरू हुआ। वह मॉडल जिसमें विभिन्न किराया-मांगने वाले समूह, भूमि विकास और निर्माण उद्योग से आय निकालने के लिए अत्यधिक हिंसा का सहारा लेते थे। फिर दौर आया वामपंथ सरकार का। वाम मोर्चे के शासन के दौरान, प्रलयकारी हिंसा कम हो गई और राजनीतिक हिंसा 'सामान्य' हो गई। वाम मोर्चे के 34 साल के शासन में राजनीतिक हत्याएं बेरोकटोक जारी रहीं। उसके बाद ममता बैनर्जी के शासनकाल में हिंसा तो वैसे ही रही, बस उसका स्वरूप बदल गया। पहले जहां वामपंथ पैर पसारने को हिंसा का समर्थन कर रहा था, अब तृणमूल जड़ें मजबूत करने के लिए इसे समर्थन कर रहा है। अब नया उपद्रव ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर के बाद शुरू हुआ है। हालांकि पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन घमासान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद भाजपा ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया तो हंगामा खड़ा हो गया। बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई है। कई नेताओं-वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपारा में भाजपा नेता प्रियंगु पांडे की कार पर फायरिंग हुई। टीएमसी केकरीब 50-60 लोगों ने हमला किया। गाड़ी पर 6-7 राउंड फायरिंग की और बम फेंके गए। ड्राइवर समेत दो लोगों को गोली लगी है। तृणमूल समर्थकों ने भाजपाइयों पर लाठी-डंडे से हमला किया। बनगांव और बारासात दक्षिण में ट्रेनें रोकी गईं। भाजपा 27 अगस्त को कोलकाता में छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और उन्हें हिरासत में लेने का विरोध कर रही है। बंद के दौरान लगभग पूरे राज्य में दहशत का माहौल रहा। बंद के दौरान के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वे हैरान करने वाले हैं। बस ड्राइवर भी सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट लगाकर चल रहे हैं। शायद हिंसा प. बंगाल में जनजीवन का हिस्सा बन चुकी है। कोई राज्य अपने पूरे इतिहास में एक ही तरह की हिंसा का अनुभव नहीं करता है, लेकिन प. बंगाल जैसे हिंसा में ही चल रहा है। केंद्र सरकार को तुरंत इस ओर ध्यान देना होगा। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। जब राज्य सरकार इससे निपटने में असफल रहे या फिर हिंसा के सहयोगी की भूमिका में हो तो इस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में हिंसा पर लगाव के लिए जो भी जरूरी हों, सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।

शिक्षा
कल्लोल चक्रवर्ती

शिक्षा की असमानता खत्म हो

चिंतित करने वाली बात यह है कि वर्ष 2022 के मुकाबले 2023 में ओवरऑल पास प्रतिशत कम रहा। इस सच्चाई की अनदेखी भी नहीं की जा सकती कि तमाम घोषणाओं और दावों के बावजूद उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे हिंदीभाषी राज्य स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अब भी बहुत पीछे हैं। एनसीईआरटी के संगठन 'परख' द्वारा तैयार रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि देश के अलग-अलग शिक्षा बोर्ड के सिलेबस और मूल्यांकन प्रक्रिया में असमानता इस दिशा में बड़ी चुनौती है। इसी के चलते छात्रों को बराबरी के मौके नहीं मिल पाते। ऐसे में, सिलेबस और मूल्यांकन प्रक्रिया में समानता आज की जरूरत है। वोकेशनल और स्किल कोर्स को बढ़ावा देना भी जरूरी है।

शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2022 की तरह 2023 में भी देशभर के 59 स्कूल बोर्डों (56 राज्य बोर्डों और तीन राष्ट्रीय बोर्डों) के रिजल्ट का विश्लेषण कर एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष जहां लंबे समय से चले आ रहे ट्रेंड के बारे में बताते हैं, वहीं कुछ निष्कर्ष चिंताजनक भी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह पहल क्यों की है? दरअसल मंत्रालय की कोशिश है कि देश के अलग-अलग स्कूल बोर्ड्स को साझा मंच पर लाकर सभी छात्रों को बराबरी के मौके दिए जाएं। रिपोर्ट का एक निष्कर्ष यह है कि वर्ष 2022 की तरह 2023 में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में पास होने के मामले में लड़कियां लड़कों से आगे रहीं। यह ट्रेंड आज का नहीं है।

पिछले काफी समय से 10वीं-12वीं की तरह नीट और जेईई जैसे प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षाओं और सिविल सर्विस की रैंकिंग तक में लड़कियों का दबदबा कायम है। इसके बावजूद समाज में लड़के-लड़कियों की शिक्षा में भेदभाव जारी है, जो स्कूलों में दाखिले तक में दिखता है। अभिभावक निजी स्कूलों में, जहां खर्च ज्यादा है, दाखिले के मामले में लड़कियों की तुलना में लड़कों को प्राथमिकता देते हैं। ज्यादातर अभिभावक लड़कियों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें खर्च कम पड़ता है। इस साल की रिपोर्ट भी बताती है कि प्राइवेट स्कूलों में लड़के आगे हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में लड़कियां ज्यादा हैं। इसके बावजूद हर तरह के स्कूलों के रिजल्ट में लड़कियां आगे हैं। 2023 में 10वीं में लड़कियों की कामयाबी का पर्सेंटेज 89 फीसदी और लड़कों का 83 प्रतिशत रहा। जबकि 12वीं में लड़कियों का पास पर्सेंटेज 86.3 फीसदी और लड़कों का पास पर्सेंटेज 78.9 प्रतिशत रहा। स्ट्रीम या शाखा चुनने में भी छात्रों और छात्राओं के बीच का फर्क साफ दिखता है।

साइंस में छात्रों का और आर्ट्स में छात्राओं का नामांकन ज्यादा होना समाज में व्याप्त इस रूढ़ि के बारे में ही बताता है कि लड़कों को साइंस पढ़ना चाहिए और लड़कियों को आर्ट्स। लेकिन साइंस और आर्ट्स, दोनों स्ट्रीम में पास होने वालों में लड़कियों की संख्या ज्यादा रही। यह तथ्य बताता है कि तमाम रूढ़िवाद और वर्जनाओं के बावजूद लड़कियां लड़कों को पीछे छोड़ती जा रही हैं। हैरानी की बात अलबत्ता यह है कि लड़कों-लड़कियों में फर्क करने वाला समाज न तो लड़कियों की मेहनत और प्रतिभा को रेखांकित कर रहा है, न उसे इससे कोई परेशानी है कि तमाम जतन किए जाने के बावजूद लड़के सालोंसाल पिछड़ रहे हैं। 2023 की रिपोर्ट के इस सकारात्मक पहलू का अलबत्ता संज्ञान लिया जाना चाहिए कि एससी/एसटी और पिछड़े वर्ग के छात्रों का नामांकन बढ़ा है और उनकी पास पर्सेंटेज में भी वृद्धि हुई है। एससी/एसटी लड़कियों का प्रदर्शन भी 2023 में बेहतर हुआ। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में वंचित तबकों की जगह बढ़ रही है। रिपोर्ट के दूसरे निष्कर्ष देश भर में स्कूली शिक्षा में व्याप्त अंतर के बारे में बताते हैं। जैसे, शिक्षा में सबसे उन्नत राज्यों में गिने जाने वाले केरल में 10वीं में पास पर्सेंटेज देश में सर्वाधिक 99 फीसदी है, तो मेघालय में यह सबसे कम 51.9 प्रतिशत

है, जो केरल का लगभग आधा है। आम सोच यह है कि मुख्यधारा से दूरी का पूर्वोत्तर को बहुत नुकसान हुआ है। मेघालय इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां 12वीं में साइंस पढ़ने वाले छात्र देश में सबसे कम मात्र 11 फीसदी हैं। त्रिपुरा में इससे थोड़ा ज्यादा लगभग 12.8 प्रतिशत छात्र साइंस के थे। हालांकि यह पूर्वोत्तर का पूरा सच नहीं है, क्योंकि मणिपुर में 68.4 फीसदी साइंस के छात्र पाए गए। राज्यवार विश्लेषण से कुछ और चीजें साफ होती हैं। जैसे केरल में पास प्रतिशत सबसे ज्यादा होना तथा आंध्र बोर्ड में साइंस पढ़ने वाले छात्रों का सर्वाधिक 78 फीसदी और तमिलनाडु में 65.9 प्रतिशत होना दक्षिण भारत में स्कूली शिक्षा के उन्नत स्तर के बारे में बताता है। अगर आर्ट्स या मानविकी की बात करें, तो त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में आर्ट्स के सर्वाधिक 84.6 फीसदी छात्र थे, तो गुजरात बोर्ड में 82.8 प्रतिशत और मेघालय में 81.1 फीसदी छात्र आर्ट्स के पाए गए।

चिंतित करने वाली बात यह है कि वर्ष 2022 के मुकाबले 2023 में ओवरऑल पास प्रतिशत कम रहा। इस मामले में राज्य बोर्डों में विफलता की दर सीबीएसई और आईसीएसई जैसे राष्ट्रीय बोर्डों की तुलना में अधिक रही। ओपन स्कूल का प्रदर्शन भी खराब रहा। इस साल 10वीं-12वीं में 65 लाख से अधिक छात्र फेल हुए। फेल होने वालों में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के छात्र सबसे अधिक थे। 10वीं में फेल होने वाले छात्रों में सबसे अधिक मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के थे। जबकि 12वीं में फेल होने वालों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश रहे। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्य शिक्षा के क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से पिछड़े होने के टैग से अब भी निकल नहीं पाए हैं।

केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति (एनईपी), 2024 का उद्देश्य देश में शिक्षा के मानक को वैश्विक स्तर पर ले जाना है। इसके लिए सरकार ने पुरानी शिक्षा नीति में कई बदलाव किए हैं, जिसका लक्ष्य शिक्षा के स्तर को बेहतर करना और अच्छी शिक्षा तक बच्चों की पहुंच बनाना है। नई शिक्षा नीति के अनुसार, पढ़ाई का तनाव घटाने के लिए 2025-26 के शैक्षणिक सत्र से छात्रों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में दो बार देने का विकल्प मिलेगा। निश्चित रूप से ये अच्छे उपाय हैं, लेकिन शिक्षा के स्तर में केरल और मेघालय के बीच का विराट अंतर पाटने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।

इस सच्चाई की अनदेखी भी नहीं की जा सकती कि तमाम घोषणाओं और दावों के बावजूद उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे हिंदीभाषी राज्य स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अब भी बहुत पीछे हैं। दरअसल एनसीईआरटी के संगठन 'परख' द्वारा तैयार रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि देश के अलग-अलग शिक्षा बोर्ड के सिलेबस और मूल्यांकन प्रक्रिया में असमानता इस दिशा में बड़ी चुनौती है। इसी के चलते छात्रों को बराबरी के मौके नहीं मिल पाते। ऐसे में, सिलेबस और मूल्यांकन प्रक्रिया में समानता आज की जरूरत है। वोकेशनल और स्किल कोर्स को बढ़ावा देना भी जरूरी है। आज 61.11 फीसदी स्कूल बोर्डों में फिजिकल एडुकेशन को, तो 38.80 स्कूल बोर्डों में आर्ट और क्राफ्ट को अनिवार्य विषय के तौर पर शामिल किया गया है। इसी तरह अभी 25 प्रतिशत स्कूल बोर्ड 50 फीसदी से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देते हैं, जबकि 32 फीसदी स्कूल बोर्डों में 40 प्रतिशत प्रश्न अति लघु उत्तरीय होते हैं। दूसरी तरफ, कुछ स्कूल बोर्डों में 90 प्रतिशत से ज्यादा प्रश्न आसान होते हैं, तो कुछ बोर्डों में 50 फीसदी प्रश्न बेहद सरल होते हैं। इन फर्कों को मिटाने पर ही बात बनेगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

राष्ट्रीय खेल दिवस
डॉ. मोनिका शर्मा

खेलों से सामाजिकता सीखे नई पीढ़ी

हॉकी का जादूगर के नाम से चर्चित भारत के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यान चन्द के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस रूप में मनाया जाता है। यह दिन जीवन में खेलों की अहमियत को भी रेखांकित करता है। असल में जीवन की जंग हो या खेल का मैदान बहुत कुछ एक सा होता है। कड़ी मेहनत, जीतने का जज्बा, हौसला, नेतृत्व दृढ़ता, गंभीरता, सधी-अनुशासित दिनचर्या और हार मिलने पर भी असीम धैर्य। जो कुछ जिन्दगी से जूझने के लिए चाहिए, वही खेल के मैदान में टिके रहने के लिए भी आवश्यक होता है। यही वजह है कि बच्चों का खेलों से जुड़ाव बेहद जरूरी है। विचारों की सही दिशा, श्रमशील व्यक्तित्व और स्वास्थ्य संभाल के लिए जीवन के पहले ही पड़ाव पर नई पीढ़ी की खेल के मैदान में मौजूदगी रहे। देश के भावी नागरिकों को व्यक्तित्व के ठहराव और संघर्ष का पाठ पढ़ाने के लिए खेलों से जोड़ना सबसे जरूरी है।

ध्यातव्य है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद सिंह और हॉकी के खेल में उनकी असाधारण उपलब्धियों के स्मरण से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, खेलों और शारीरिक गतिविधियों के महत्व को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए भी यह दिन मनाया जाता है। देशभर में शारीरिक सक्रियता और खेलों से मिलने वाली मानसिक मजबूती का संदेश देने के लिए कई कार्यक्रम, समारोह और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। हर बार एक विषय विशेष के मद्देनजर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस की वर्ष 2024 की आधिकारिक थीम 'शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन और विकास के लिए खेल' रखी गई है। यह विषय बताता है कि लोगों की एकजुटता, समुदायों की समावेशिता और शांति को बढ़ावा देने के लिए खेल एक सार्थक परिवेश बना सकते हैं। इस वर्ष की थीम खेलों और सामाजिक बंधनों की मजबूती को जोड़कर देखने-समझने का संदेश लिए है।

असल में सोशल बॉंडिंग हो या आपसी संवाद और मेलजोल। वर्चुअल स्क्रीन में खेलते आज के बच्चे सहज जीवन से जुड़ी कई बातों से दूर हैं। बच्चों की निष्क्रिय जीवनशैली तो अब चिंता का विषय बन गई है। मोटापा और कम उम्र में दूसरी बीमारियों की दस्तक अभिभावकों को भी डरा रही है। इतना ही नहीं, तकनीकी गैजेट्स में गुम आज के बच्चे अपने हमउम्र साथियों के साथ मिलकर खेलने और हार-जीत को जीने का भाव भी भूल रहे हैं। लांसेंट मेडिकल जर्नल में छपे एक अध्ययन के मुताबिक बीते चार दशक में 18 साल से कम उम्र के बच्चों में मोटापे के स्तर में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। ध्यातव्य है कि वैश्विक स्तर पर 200 देशों के आंकड़ों के आधार पर सामने आया कि यह अध्ययन अपनी तरह का सबसे बड़ा शोध है।

विचारणीय है कि नयी पीढ़ी की जीवनशैली और तकनीकी व्यस्तता कमोबेश दुनिया के हर समाज में ही बढ़ी है। नतीजतन, खेल-कूद के अभाव में बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। समझना मुश्किल नहीं कि बालमन के उत्साह, ऊर्जा और सामाजिक जुड़ाव को पोषण देने वाली खेलने की गतिविधि उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। ज्ञात हो कि बीते दिनों केरल उच्च न्यायालय ने भी अपने एक निर्देश में खेलकूद को बच्चों का मौलिक अधिकार कहा था। असल में खेल और हमउम्र बच्चों से मेलजोल ही बच्चों की अधिकतर शारीरिक-मनोवैज्ञानिक परेशानियों का हल है। आज आपराधिक गतिविधियों तक में लिप्त हो रहे बच्चों का आक्रोश और चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए भी उनका खेलना आवश्यक है। साथ ही खेलों से जुड़ने वाले बच्चे समय प्रबंधन और अनुशासन सीखते ही हैं। इसके अलावा वे स्मार्ट स्क्रीन से भी दूर रहत पाते हैं। एक ओर वर्चुअल खेल खेलने वाले बच्चे दुखदायी कदम तक उठा लेते हैं तो दूसरी ओर मन की व्याधियों से घिरते भी बच्चे खेल के मैदान में उतर कर मानसिक तनाव भूल जाते हैं।

खेलों के माध्यम से बच्चों में बेहतर शारीरिक और बौद्धिक विकास का परिवेश बनता है। खास तौर पर एकल परिवारों के इस दौर में खेल ही बालमन को अपने आप तक सिमटे रहने के दायरे से बाहर निकालकर लाते हैं। मन की झिझक दूर कर उन्हें मिलनसार बनाते हैं। बचपन में मिलने वाला सामाजिकता, नियमितता और स्वनियमन का यह सकारात्मक पाठ बच्चों को जिम्मेदार और सहयोगी नागरिक भी बनाता है। ज्ञात हो कि वर्ष 2024 की थीम भी सोशल बॉंडिंग के इसी भाव को सम्बोधित है।

(लेखिका स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है समर्पण

संकलित
दर्शन

समर्पण प्रत्येक प्राणी के लिए अत्यंत आवश्यक भाव है। यही वह भाव है जिसके माध्यम से हम अपने आत्मीय जनों के प्रिय बन सकते हैं। यह स्मरण रहे कि राग, द्वेष, घृणा तथा स्वार्थ का त्याग किए बिना समर्पण की कल्पना व्यर्थ है। हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में समर्पण का भाव आवश्यक है। समर्पण हमारे लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक है। संबंधों में मधुरता के लिए हमें परस्पर समर्पण भाव रखते हुए रिश्तों का निर्वहन करना होता है। स्वार्थ की दृष्टि से बनाए गए रिश्ते अल्पावधि के उपरांत समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी समर्पण भाव का होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने संपूर्ण समर्पण के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं, तब कोई भी लक्ष्य हमसे दूर नहीं रहता। समर्पण के साथ-साथ विश्वास का होना भी आवश्यक है। जिस प्रकार एक बीज धरती में रोपित किया जाता है, तो वह संपूर्ण रूप से खुद को धरती मां की गोद में समर्पित कर देता है। तभी उसमें विकास के नए अंकुर फूट पड़ते हैं। भास्कर की किरणें उसे शक्ति प्रदान करती हैं। पवन की शीतलता उसे दुलारती है। मेघ उसका अभिसिंचन करते हैं। इस प्रकार उसे संपूर्ण प्रकृति का सहयोग एवं साहचर्य मिलने लगता है। उसके बाद वह धीरे-धीरे एक संपूर्ण वृक्ष का आकार ले लेता है। एक ऐसे वृक्ष का, जिसके आश्रय में तमाम प्राणी शीतलता प्राप्त करते हैं। यही नहीं, वह वृक्ष सैकड़ों बीजों के जनक होने का गौरव भी प्राप्त करता है।

लक्ष्मी जी कहां निवास करतीं हैं

संकलित
प्रेरणा

एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकान्त स्थान पर गधे के रूप में छिपे हुए थे। देवराज इन्द्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन इन्द्र ने उन्हें खोज निकाला और उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया। साथ ही उन्हें तत्वज्ञान का बोध कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपात्मा स्त्री निकली। उसे देखकर इन्द्र ने पूछाः दैत्यराज! यह स्त्री कौन है? देवी, मानुषी अथवा आसुरी शक्ति में से कौन-सी शक्ति है? राजा बलि बोलेः देवराज! ये देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं हैं। आप स्वयं पूछ लें। इन्द्र के पूछने पर वे शक्ति बोलीं: देवेन्द्र! मुझे न तो दैत्यराज बलि जानते हैं और न ही तुम या कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं। जैसे- श्री, लक्ष्मी आदि। इन्द्र बोलेः देवी! आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? लक्ष्मी जी बोलीं: देवेन्द्र! मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डिगा नहीं सकता है। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती-जाती रहती हूं। जैसा काल का प्रभाव होता है मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूं। अर्थात मैं समयानुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूं। इन्द्र बोलेः देवी! आप असुरों के यहां निवास क्यों नहीं करतीं? लक्ष्मी जी बोलीं: देवेन्द्र! मेरा निवास वहीं होता है जहां सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान देने के कार्य होते हों। लेकिन असुर भ्रष्ट हो रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को वश में कर सकते थे, सत्यवादी थे।

अंतर्मन

आज की पाती

बर्फ के पहाड़ों का पिघलना शुभ संकेत नहीं

उतराखंड के पिथौरागढ़ में ओउम पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 19,356 फीट अर्थात यह लगभग 5900 मीटर है। यहां ओम शब्द भी लिखा दिखता था, लेकिन हमने जो आधुनिकता और भौतिकतावादी चीजों के लिए प्रकृति की नाक में दम किया और इस कारण पर्यावरण में गर्मी बढ़ी, इसका बुरा असर पहाड़ों पर भी पड़ना शुरू हुआ और इसी कारण ओउम पर्वत से ओम शब्द भी नहीं रहा, अर्थात वह पिघल गया। वैज्ञानिक और अन्य विशेषज्ञ इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग भी बता रहे हैं और हिमालयी क्षेत्रों से बर्फ का पिघलना बहुत ही हानिकारक बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी कि जहां एक तरफ देश के बहुत से मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश हो रही थी, वहीं कश्मीर में गर्म हवाएं चल रही थीं और अब अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के समय से पहले पिघलने की खबर है।

– मनीष बघेल, धमतरी

ट्रेंड

लाभार्थियों को बधाई

प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू की गई 'पीएम जन-धन योजना' ने करोड़ों गरीबों के वित्तीय समावेशन से उनके सपनों को नई ऊँचाई देकर अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। देश की अर्थव्यवस्था में अकल्पनीय परिवर्तन लाने वाली इस योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने की सभी लाभार्थियों को बधाई।

-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

इतनी जल्दबाजी क्यों

इतनी भयावह घटना के बाद एक पिता को ये सवाल क्यों उठाने पड़ रहे हैं? क्या एक पीड़ित पिता का ये भी हक नहीं कि उसे अपनी बेटी के साथ हुए सुलूक का सच पता चल सके? आखिर प्रशासन बच्चियों के शवों को जलाने की जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है?

-प्रियंका गांधी वढ़ेरा, कांग्रेस नेत्री

जयशाह का कार्यकाल

उत्साही होना और क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा रखना एक क्रिकेट प्रशासक के लिए आवश्यक गुण है। बीसीसीआई सचिव के रूप में जयशाह ने अपने कार्यकाल के दौरान इन गुणों को अद्भुत ढंग से प्रदर्शित किया।

-सचिन तेंदुलकर, पूर्व क्रिकेटर

निष्क्रियता और क्रिया

निष्क्रियता भी क्रिया का ही एक रूप है। कभी-कभी कुछ न करना अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ करने से ज्यादा कुछ कहता है।

-काजोल, फिल्म अभिनेत्री

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

अमेरिकी संयंत्र ने तोप के गोलों का उत्पादन बढ़ाया

रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में इस्तेमाल के लिए तोप के गोले बनाने वाले पेनसिल्वेनिया स्थित संयंत्र ने बढ़ती मांग के मद्देनजर उत्पादन को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। सरकारी अधिकारियों ने ऐतिहासिक कारखाने के 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत से किए जा रहे आधुनिकीकरण के बारे में बताते हुए उत्पादन में हुई वृद्धि की इस सप्ताह जानकारी दी। 'स्क्रैंटन आर्मी एम्युनीशन प्लांट' इस्पात की 2,000 पाउंड (907 किलोग्राम) छड़ों को काटकर 155 मिमी 'हॉवित्जर' के गोलों में ढालता है, जिन्हें आयोवा भेजा जाता है और वहां उन्हें विस्फोटकों से भरा जाता है और 'फ्यूज' से जोड़ा जाता है। वहां से कई गोलों को यूक्रेन में लड़ाई के लिए भेजा जाता है जहां इनकी अत्यधिक मांग है।

स्क्रैंटन संयंत्र के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि उसने निकटवर्ती विल्क्स-बर्रे में स्थित दो अन्य गोला-बारूद संयंत्रों के साथ मिलकर अपना उत्पादन 24,000 गोले प्रति माह से हाल में बढ़ाकर 36,000 गोले प्रति माह कर दिया है। उन्होंने बताया कि तीन नयी उत्पादन लाइन विकसित की जा रही हैं, जिससे स्क्रैंटन संयंत्र को इन अहम हथियारों का उत्पादन और बढ़ाने में मदद मिलेगी।

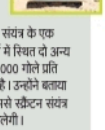

ऑफ बीट

अटलांटिक नीना मौसम को कैसे प्रभावित करता है

उत्तरी अटलांटिक महासागर में कई महीनों से भीषण गर्मी चल रही है और सतह का तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर या इसके करीब है। लेकिन अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत दोनों में भूमध्य रेखा के साथ ठंडा होने से अंतत: कुछ राहत मिलनी शुरू हो सकती है, खासकर, मूंगा चट्टानों के कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। यह ठंडक समान नामों वाली दो जलवायु घटनाओं से आती है: ला नीना, जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में बनती है, और कम प्रसिद्ध अटलांटिक नीना। दोनों अटलांटिक तूफान के मौसम को प्रभावित कर सकते हैं। जबकि ला नीना अटलांटिक तूफानों के लिए आदर्श स्थितियाँ लाता है, कम शक्तिशाली अटलांटिक नीना में तूफान के कुछ जोखिम को कम करने की क्षमता है। हम महासागर और वायुमंडलीय वैज्ञानिक हैं जो इस प्रकार की जलवायु घटना का अध्ययन करते हैं। दोनों निनाओं को एक ही समय में देखना दुर्लभ है, फिर भी अगस्त 2024 में दोनों विकसित होते दिख रहे हैं। आइए बारीकी से देखें कि इसका क्या मतलब है। ला नीना और उसका चचेरा भाई, अटलांटिक नीना ला नीना अल नीनो-दक्षिणी दोलन का हिस्सा है, जो एक प्रसिद्ध जलवायु घटना है जिसका दुनिया भर में जलवायु और मौसम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

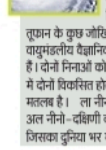

राष्ट्रीय
सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 29 अगस्त • 2024
www.rashtriyasahara.com

जल्द हो फैसला

बंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर निचली अदालतें अग्रिम जमानत पर त्वरित फैसला नहीं लेती तो सारा बोझ हाई कोर्ट पर आ जाता है। एकल पीठ ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता वामन म्हात्रे की अग्रिम जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय न लेने पर ठाणे की कल्याण स्थित निचली अदालत से अप्रसन्नता जाहिर करते हुए यह टिप्पणी की। बीते हफ्ते म्हात्रे पर बदलापुर में हुए दो बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में महिला पत्रकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने का आरोप है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सत्र अदालत उसकी याचिका पर सुनवाई स्थगित कर रही है। अदालत ने कहा कि जब याचिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है तो आदर्श रूप से अदालत को कम से कम अंतरिम सुरक्षा का

अनुरोध करने वाले आवेदन पर विचार करना चाहिए। अदालत ने नागरिक की स्वतंत्रता के लिए गिरफ्तारी से पहले ही जमानत के लिए आवेदन स्वाकरने या अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने का फैसला जल्द लेने का भी सुझाव दिया। चूंकि खासकर इस मामले में याचिकाकर्ता पर ऐसा गंभीर आरोप नहीं है, न ही वह अपराधी है, जिसे फौरन जमानत न दी जाए। हालांकि राजनीतिज्ञों के मसले में आम तौर पर अदालतें फौरी तौर पर बीच का कोई मार्ग ले लेती हैं। महिला के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी माफी योग्य अपराध नहीं है। बच्चियों के यौन शोषण को लेकर जनता में भी भारी आक्रोश है। राजनेताओं से जितनी समझदारी की उम्मीद की जाती है, उसमें वे विफल होते हुए कई दफा नजर आते हैं। वे उस जनता के भी नुमाइंदे हैं, जो पीड़िता है और जो प्रदर्शन कर रही है। उन्हें सार्वजनिक तौर पर शालीनता भरा बर्ताव करना चाहिए। सत्र अदालत टिप्पणीकर्ता को सख्त हिदायतों के साथ जमानत दी जा सकती थी परंतु कई दफा ऐसे गंभीर और चर्चित मामलों में नेताओं के साथ बरती जाने वाली नरमियत को लेकर आमजन नाराजगी भी व्यक्त करते हैं। यह कहना गलत न होगा कि हो सकता है अदालत इस विवाद से बचना चाहती हो। रही बात ऊपरी अदालतों के बोझ की तो कई बार सबसे बड़ी अदालत भी उच्च न्यायालयों को मामले को अपने स्तर पर ही निपटाने संबंधित हिदायतें देती रही है। व्यक्ति की स्तंत्रता महत्वपूर्ण है परंतु जब वह शासन में है, तो उसकी पहुंच का भी ख्याल रखा जाना अनुचित नहीं कहा जा सकता। दरअसल, निचली अदालतों की इस मामले में महती जिम्मेदारी है, जिसका निभाह होना चाहिए।

घाटी में अग्नि परीक्षा

जम्मू-कश्मीर में पहले चरण के विधानसभा चुनाव में 18 सितम्बर को सात जिलों की 24 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राजनीतिक दलों ने सूबे की नई चुनावी जमीन पर अपनी-अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक गोटियां फिट करनी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया जिसके कारण दोनों के बीच सुगमता से गठबंधन और सीटों का बंटवारा हो सका। एनसी 51, कांग्रेस 32, पैंथर्स पार्टी और सीपीएम एक-एक सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। घाटी की सोपोर और जम्मू संभाग के डोडा, बनीहाल, भद्रवाह और नगरोटा सीटों पर दोनों के बीच सहमति कायम न हो पाने से उनके बीच दोस्ताना मुकाबला होगा। पिछले करीब एक दशक से इस सूबे में कांग्रेस का राजनीतिक प्रभाव कम होता जा रहा है। इसके बावजूद एनसी ने कांग्रेस को 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर दिया है तो इसके राजनीतिक मायने बहुत स्पष्ट हैं। वास्तव में 2014 के बाद से सूबे का

राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। एनसी भी सूबे की राजनीति में प्रायः अप्रासंगिक होती जा रही है। अपने को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उसे कांग्रेस के साथ गठबंधन करना अपरिहार्य था। दूसरी ओर कांग्रेस को भले ही अपनी राजनीतिक हैसियत के मुकाबले गठबंधन में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल गया है, लेकिन अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने के मुद्दे पर उसका रुख एनसी से अलग है। एनसी ने घोषणा कर दी है कि गठबंधन सत्ता में आता है, तो अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने के विरुद्ध विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। गठबंधन की सरकार बनती है तो इस मसले पर कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसीलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल को कहना पड़ा कि हमारी सरकार बनती है, तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सरकार चलाएंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) भी अब अलग-थलग पड़ गई है। भाजपा के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में भारी असंतोष है। आतंकवाद पीड़ित इस सूबे की राजनीति अनिश्चितताओं से भरी हुई है, लेकिन इतना सुनिश्चित है कि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलने जा रहा। हां, इतना जरूर है कि इस चुनाव में सभी राजनीतिक दलों की अग्नि परीक्षा होने जा रही है।

कटाक्ष/ सहीराम

नया बमबाज

एक जमाना था, जब देश में बड़े बमबाज पाए जाते थे जी। वह उग्रवाद, आतंकवाद का दौर था। भाजपा सत्ता में आई तो उसने उग्रवाद, आतंकवाद सब खत्म कर दिया और इसके साथ ही बमबाज भी खत्म हो गए। बमबाज क्या अब तो पत्थरबाज भी नहीं मिलते। पहले कहते थे कश्मीर में हैं, लेकिन अब तो वहां भी नहीं। धारा तीन सौ सत्तर जो हट गई। ऐसा रामराज्य आने के बाद भाजपा को बड़ा खालीपन महसूस हुआ। बलात्कारी जुगुप्सा पैदा करने में तो सफल रहे, पर वे बमबाजों वाला थ्रिल पैदा नहीं कर पाए। सो, इस खालीपन को भरने और थोड़े एडवेंचर के लिए भाजपा ने खुद अपना एक बमबाज पैदा किया। एकदम स्वनिर्मित। अब भाजपा चूंकि एक सत्ताधारी पार्टी है, सो, छोटा-मोटा बमबाज पैदा करना उसे अपनी तौहीन लगा होगा, सो, उसने एक बड़केवाला, बाकायदा मुख्यमंत्री बमबाज पैदा दिया। वैसे तो यह किसी फिल्म का नाम भी हो सकता है-नया बमबाज।

भाजपा के दो नंबरी नेता-हालांकि शरद पवार जैसे नेता उन्हें तड़ीपार कह कर दस नंबरी ही करार देना चाहते हैं, बहरहाल-अमित शाह जी ने अपने इस बमबाज मुख्यमंत्री को वैसे पेश नहीं किया, जैसे आम तौर पर किया जाता है कि इन से मिलिए-यह हैं हमारे मणिपुर के मुख्यमंत्री-बमबाज मुख्यमंत्री बीरेन सिंह। उन्होंने जरा डपटने के अंदाज में उनका लाड़ लड़ाया-अरे, बीरेन जी आप तो बम मारता है। अपनी इस तारीफ से बीरेन सिंह इतने शरमाए कि यह भी नहीं कह पाए कि आप क्या जानें कि मैंने क्या-क्या मारा है-जनता की एकता को मारा, भाईचारे को मारा, इंसानियत को मारा, इंसान होने की गरिमा को मारा, मैंने क्या नहीं मारा। मैंने तो पूरे मणिपुर को मारा है। लेकिन शरमाने से ज्यादा वे दो नंबरी नेता से डरे और अपनी तारीफ को हजम कर गए। लेकिन जैसे बॉस को उन पर लाड़ आया था, वैसे ही उन्हें अपने उन मातहतों पर लाड़ आया और उन्हें उसी तरह लाड़ से डपटते हुए उन्होंने कहा-तुम क्या इतनी जोर से बम मारते हो, देखो दिल्ली में बैठे बॉस को भी पता चल गया। अब धीरे से बम मारना। अगर बमबाज मुख्यमंत्री नाम से कोई फिल्म बनती है, तो उसमें धीरे से बम मारने वाले भाव का कोई गाना भी हो सकता है-धीरे चलो मोरी बांकी हिरनिया टाइप का। नहीं क्या?

अनमोल वचन

धर्म करते हुए मर जाना अच्छा है पर पाप करते हुए विजय प्राप्त करना अच्छा नहीं।

-महाभारत

माओवाद की हिलती जमीन

सामयिक

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने

माओवाद को पूरी तरह खत्म करने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, वह अभूतपूर्व है। पिछले दो-तीन दशकों में माओवादी हिंसा को रोकने को लेकर किसी भी गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ की इतनी यात्राएं नहीं की होंगी जितनी अमित शाह पिछले पांच-छह वर्षों में कर चुके हैं। वे रेड कॉरिडोर में तैनात बीएसएफ, सीआरपीएफ, अन्य अर्द्धसैनिक बलों, विशेष पुलिस और आम लोगों से मिलते हैं, और जमीनी हकीकत जानने का प्रयास करते हैं। गृह मंत्री का विश्वास है कि सरकार की बहुआयामी नीतियों से विकास और आत्मसमर्पण में तेजी आई है, और मार्च, 2026 से पहले देश में पूरी तरह वामपंथी उग्रवाद समाप्त हो जाएगा।

केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अब नौ राज्यों के 38 जिले ही उग्रवाद प्रभावित रह गए हैं। इनमें 15 जिले छत्तीसगढ़, ओडिशा के सात जिले और झारखंड के पांच जिले वामपंथी उग्रवाद की चपेट में हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि रेड कॉरिडोर में तैनात सुरक्षा बल माओवादियों को खदेड़ने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। बेहद पिछड़े और दूरस्थ इलाकों, जहां पहुंचना मुश्किल हुआ करता था, में भी पक्की सड़कें बन रही हैं, स्कूल और अस्पताल खुल रहे हैं तथा बाजार भी रोशन हैं।

माओवादी सड़कें नहीं बनने देना चाहते थे और उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को कई बार निशाना भी बनाया लेकिन अर्द्धसैनिक बलों के साहस और बलिदान के कारण अत्यधिक वामपंथ प्रभावित छत्तीसगढ़ के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और मोहल्ला मानपुर जिला मुख्यालय पर जाना इस समय आसान हो गया है। स्थानीय पुलिस की भूमिका यहां बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उन पर शांति और व्यवस्था बनाएं रखने की जिम्मेदारी होती है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में थानों की निगरानी अर्द्धसैनिक बलों को करनी होती है। स्थानीय पुलिस आज भी दूरस्थ गांवों में जाने का साहस नहीं जुटा पाती। हाल के वर्षों में स्थानीय पुलिस के जवानों के अपहरण और हत्या के कई मामले सामने आए हैं। स्थानीय जनता पर दबाव बढ़ाने के लिए नक्सली ऐसा करते हैं, जिससे ग्रामीण पुलिस भर्ती से दूर रहें। सरकार की सुरक्षा पुनर्वास नीति कारगर रही है। छत्तीसगढ़ में नियद नेल्लानार या आपका अच्छा गांव योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों के 5 किमी. के दायरे में स्थित गांवों में सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

इन क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ना निर्णायक साबित हुआ है, और नक्सलियों के खिलाफ संघर्ष में सुरक्षा बलों को सफलताएं भी मिल रही हैं, लेकिन मोबाइल टावर सुरक्षा बलों के कैंप के सुरक्षा घेरे में रहने से सुरक्षित हैं।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बिना सुरक्षा के टावर की स्थापना अब भी चुनौतीपूर्ण है। रेड कॉरिडोर की भौगोलिक परिस्थितियां माओवाद के अनुकूल होती हैं, स्थानीय गरीब और भोले-भाले युवक-युवतियों को गुमराह करने में माओवादी सफल भी हो जाते हैं। वहीं भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है।

गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र के दक्षिणपूर्वी कोने में स्थित है। यह पश्चिम में चंद्रपुर जिला, उत्तर में गोंदिया जिला, पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य और दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में तेलंगाना राज्य से घिरा है। गढ़चिरौली आदिवासी जिला है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का यह जिला रेड कॉरिडोर का हिस्सा है, जहां माओवादी गतिविधियां काफी होती हैं। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के सदस्यों ने इस जिले के घने जंगलों और पहाड़ियों में शरण ली है। वामपंथी उग्रवाद ने विदर्भ क्षेत्र में चंद्रपुर और गोंदिया की सीमा पर स्थित इस सुदूर जिले में अपना असर दिखाया है, जहां राज्य के दर्जे की मांग भी देखी जा रही है। सुरक्षा बलों की शानदार कार्रवाइयों के बाद भी यह जिला माओवादी प्रभाव से अभिशप्त है, और इसका प्रमुख कारण भ्रष्टाचार है। सुरक्षा बल जान पर खेल कर यहां सड़क तो बनवा देते हैं, लेकिन नदियों और नालों से भरपूर इस क्षेत्र में बनाए गए पुल या तो कमजोर होते हैं, या पूरी तरह बह जाते हैं। रेड कॉरिडोर में विकास के लिए सरकार अरबों रुपये का प्रावधान करती है। खर्च करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की भूमिका होती है। माओवादी हिंसा की आड़ लेकर योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार किया जाता है। इसमें अधिकारियों, नेताओं यहां तक कि नक्सलियों की भी मिलीभगत होती है। माओवाद के उभरने और प्रभावी होने का एक बड़ा कारण आदिवासी इलाकों में वे बड़ी परियोजनाएं भी हैं, जिनको लेकर आदिवासी आशंकित रहते हैं।

घने जंगलों को उजाड़ कर विकास का सपना दिखाने के साथ खनन से जंगलों और नदियों को बर्बाद करने की कीमत आदिवासी जीवन को चुकानी पड़ती है। इससे आदिवासी जीवन प्रभावित होता है, और उनकी प्रथाओं और परंपराओं पर इसे हमले की तरह माना जाता है। यहां यह देखने और समझने की जरूरत है कि सरकारें आदिवासियों को आधुनिक क्यों बनाना चाहती हैं। वन्य संसाधनों से भरपूर क्षेत्रों में गरीबी और पलायन आदिवासियों की प्रमुख समस्या है जबकि पूंजीवादी शक्तियां लोकतांत्रिक सरकारों की नीतियों का भरपूर फायदा उठाकर प्राकृतिक संसाधनों को भरपूर दोहन करने में कामयाब हो जाती हैं। आदिवासी जीवन से जुड़े ये प्रमुख मुद्दे हैं, जिन्हें हवा देकर माओवाद फलने-फूलने लगता है, और वे आदिवासियों को जल-जंगल-जमीन की रक्षा करने के नाम पर लामबंद करने में कामयाब हो जाते हैं।

दरअसल, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर रेड कॉरिडोर में गरीबी, भौगोलिक जटिलताएं, राजनीतिक सौदेबाजी, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार और वन्य जीवन की उन्मुक्तता से प्रभावित जीवन के अनेक रंग हैं। माओवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों के व्यापक प्रयास जारी हैं, और उन्हें सफलताएं भी मिल रही हैं। लेकिन यह माओवाद के पूर्ण खत्म होने की गारंटी नहीं है। केंद्र सरकार की रेड कॉरिडोर में विकास की रणनीति के कामयाब होने की संभावनाओं के पूरा होने के लिए जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर माओवाद को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मदद नहीं मिले तथा आदिवासियों को विश्वास में लेकर तथा वनों को सुरक्षित रख कर विकास की व्यापक कार्ययोजना बनाई जाएं तथा पूरे रेड कॉरिडोर में केंद्र, राज्य, स्थानीय प्रशासन और आदिवासियों की भागीदारी से समन्वित प्रयास करके उन्हें ईमानदारी से लागू किया जाए।

(लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं)

> केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अब नौ राज्यों के 38 जिले ही उग्रवाद प्रभावित रह गए हैं। इनमें 15 जिले छत्तीसगढ़, ओडिशा के सात जिले और झारखंड के पांच जिले वामपंथी उग्रवाद की चपेट में हैं। बेशक, रेड कॉरिडोर में तैनात सुरक्षा बल माओवादियों को खदेड़ने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। बेहद पिछड़े और दूरस्थ इलाकों, जहां पहुंचना मुश्किल हुआ करता था, में भी पक्की सड़कें बन रही हैं, बाजार भी रोशन हैं

- नौकरी कर रहे देश के 70-85 फीसद ग्रामीण युवा नये अवसरों की तलाश में अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं। 'स्टेट ऑफ रूरल यूथ इंप्लॉयमेंट रिपोर्ट-2024' से यह खुलासा हुआ है
- रिपोर्ट ट्रांसफोर्म रूरल इंडिया और संबोधी रिसर्च की संयुक्त पहल-डवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट ने तैयार की है
- रिपोर्ट 21राज्यों के 18-25 वर्ष के युवाओं के बीच किए गए सर्वे पर आधारित है। सर्वे में सबसे रोचक तथ्य यह पता चला कि ग्रामीण युवा कृषि को कॅरियर की तरह नहीं देखते

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

यूक्रेन में भारत के प्रयास पर सहमति-असहमति के इतर जेलेंस्की का यह कहना गलत है कि रूस से सस्ते कच्चे तेल से केवल भारत को ही फायदा हुआ है। पश्चिम रूस के कच्चे तेल के बाजार से खुश था कि हर किसी का फायदा हो रहा है। वरना आज ऊर्जा के दाम सातवें आसमान पर पहुंच चुके होते।

एम.के. वेणु, पत्रकार
@mkvenu1

डिटिजल वित्तीय क्रांति के दस साल

जनधन **नितेश रंजन**

प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएम जेडीवाई) दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल की आज 10वीं वर्षगांठ है। यह एक बुनियादी समावेशन परियोजना है जिसे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 2014 में शुरू किया गया था। जनधन योजना ने अर्थव्यवस्था में वित्तीयकरण, औपचारिकरण और डिजिटलीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता की है। आज जबकि 53 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 80% वयस्कों का किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान में खाता है। यह 2500 अमेरिकी डॉलर के बराबर प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक मानदंडों की तुलना में कहीं अधिक है।

बैंक खाते खोले जाने से महिलाओं (जनधन खातों में 55% हिस्सेदारी) के साथ-साथ पिरामिड के निचले हिस्से के लोगों को भी सशक्त बनाने में मदद मिली क्योंकि सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के हिस्से की सब्सिडी बिना किसी लीकेज के सीधे उन्हें प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का उपयोग किया। भारत ने तीन महत्त्वपूर्ण आयामों को साथ जोड़कर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कार्यनीति को सावधानीपूर्वक तैयार किया जिससे यह संभव हुआ जैसे कि जैम ट्रिनिटी और बैंक खाता (जनधन) इस ट्रिनिटी का महत्त्वपूर्ण हिस्सा था, इसके अतिरिक्त डिजिटल पहचान (आधार) और मोबाइल नंबर भी इसका हिस्सा हैं। डीबीटी के उपयोग के माध्यम से इसने राजकोषीय बचत को बढ़ावा दिया। मार्च, 2023 तक संचयी बचत 3.5 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है क्योंकि सरकार लगभग 7 लाख करोड़ रुपये सालाना अंतरित करती है। 'बैंक रहित' लोगों के पास अब बैंक खाते तक पहुंच है और उन्हें निःशुल्क रूपे कार्ड प्रदान किया गया है जिससे अर्थव्यवस्था में नकदी के कम उपयोग को बढ़ावा मिला है। डीबीटी के 65% से अधिक लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में जनधन की भूमिका का संकेत मिलता है।

जनधन की शुरुआत के दो साल बाद अप्रैल, 2016 में भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई नामक तत्काल भुगतान प्रणाली की शुरुआत की गई जिसने खुदरा

डिजिटल भुगतानों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में यूपीआई के माध्यम से 1200 करोड़ मासिक डिजिटल भुगतान लेनदेन ने इसे विश्व स्तर पर मान्यता प्रदान की है। भुगतान/वित्तीय लेनदेन के मामले में यूपीआई क्रांति के लिए बुनियाद तैयार करके इसमें जनधन ने प्रमुख भूमिका निभाई है। जनधन और यूपीआई ने मिल कर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण को बढ़ावा दिया है, जो डेटा एक्सेस या अंतर-संचालनीयता के विस्तारीकरण बनाने में सहायता प्रदान करता है, जिसका लाभ वित्तीय संस्थानों द्वारा छोटे टिकट की उधारी की ऋण हामीदारी के लिए लिया जा सकता है। इसने फिनटेक जगत में नवोन्मेषिता को भी बढ़ावा दिया है। कुल मिला कर 2014 में जनधन से शुरू हुए सुधार उसके बाद 2016 में यूपीआई और फिर 2017 में जीएसटी ने भारत को 'विश्व में सबसे बड़ा 'निजी डेटा-कैश' वाला 'डेटा संपन्न देश' बनाने में सहायता प्रदान की है।

भारत वर्तमान में विश्व में डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में सबसे तेज वृद्धि उचित इकोसिस्टम के माध्यम से प्राप्त हुई है जिसकी नींव 2014 में जनधन सुधार के माध्यम से रखी गई थी। डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टम में नवीनतम जुड़ाव यूएलआई (यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस) है जो विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे उधारकर्ताओं, जिनकी ऋण मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है, को परेशानी रहित ऋण प्रदान करता है। यह कृषि, एमएसएमई आदि के क्षेत्र में छोटे उधारकर्ताओं के लिए वित्तीय क्रांति होगी। आरबीआई गवर्नर के अनुसार, 'जैम-यूपीआई-यूएलआई की 'नई ट्रिनिटी' भारत की डिजिटल अवसंरचना यात्रा में क्रांतिकारी कदम होगी।' बैंकिंग प्रणाली, पिरामिड के निचले हिस्से में लोगों हेतु छोटे-टिकट वाले उत्पादों के प्रावधान के माध्यम से बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करके उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है। हम डीबीटी प्राप्तियों के आधार पर क्रेडिट इतिहास/क्षमता के साथ सूक्ष्म-ऋण, माइक्रो-इंश्योरेंस (जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा के लिए पृथक और एक साथ) के साथ-साथ कम मूल्य के सुनियोजित निवेश योजना (एसआईपी) के माध्यम से सूक्ष्म-निवेश विकल्पों, सरकारी बॉन्ड में प्रत्यक्ष खुदरा भागीदारी के लिए आरबीआई के पोर्टल के माध्यम से कम टिकट निवेश जैसे उत्पादों पर विचार कर सकते हैं। बैंकों के लिए बाद वाले विकल्प विभिन्न निवेश विकल्पों को ढूंढने के इच्छुक युवा आबादी की बढ़ती आकांक्षाओं को समझने का एक सुनहरा अवसर हो सकता है।

(लेखक यूनियन बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं)

तान् तितिक्षस्व **डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी**

अनेक भोगों का घर अर्थात यह संसार! हर प्राणी अपनी इंद्रियों की शक्ति के अनुसार संसार के विविध भोगों में प्रवृत्त होता है। भगवान

स्वामीनारायण समझाते हैं कि संसार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पंचविषयों में श्रोत्र (कान), त्वक (त्वचा), चक्षु (आंख), रसना (जीभ), घ्राण (नाक) नामक इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं। ये इंद्रियां ही भोग के साधन हैं। पंचविषयों के इन क्षणिक सांसारिक सुख में इंद्रियां व्यक्ति को पूर्णतया डूबा कर रखती हैं। किंतु जैसे शरीर नाशवान है, वैसे ही शरीर के सुख-दुःख भी नश्वर हैं, इसलिए इंद्रियों के विषयों से संबंधित सभी सुख-दुःख भी अल्पकालिक हैं। इसीलिए भगवान इन सांसारिक सुख-दुःख को सर्दी-गर्मी की उपमा देकर उन्हें सहन करने को कह कर अर्थात स्थिर रह कर अपने कर्त्तव्य को करने का उपदेश देते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा, 'इंद्रिय और विषय का संयोग अनित्य है, वे गर्मी और सर्दी की तरह बार-बार सुखी-दुःखी करते हैं। हालांकि ये दोनों अस्थायी हैं। अतः अर्जुन! उन्हें स्थिर रह कर सहन करो।' किंतु संसार की नश्वरता को समझने के बाद भी मनुष्य जाग्रत नहीं है। उसे सोचना चाहिए कि ऐसे सुख से क्या लाभ जिसका परिणाम केवल दुःख हो! श्रीमद्भागवत में वेदव्यास जी तितिक्षा (अर्थात सुख-दुःख के द्वंद्वों में स्थिर रहना, सहन करना) का वर्णन करते हैं। समझाते हैं कि बाहरी विकट परिस्थितियां स्थिर व्यक्ति की आंतरिक समृद्धि को दूर नहीं कर सकतीं। तितिक्षा को 'धैर्य' भी कहा जाता है। यह गुण केवल मानसिक ताकत ही नहीं, बल्कि जीवन की सच्ची समझ और स्थिरता का भी प्रतीक है। जब व्यक्ति तितिक्षा का अभ्यास करता है, तो वह धैर्यपूर्वक परिस्थितियों को स्वीकार करता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है। संक्षेप में, तितिक्षा ऐसा गुण है जो हमें जीवन की कठिनाइयों को सहन करने, समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने और अंततः आत्मविकास की ओर अग्रसर होने में मदद करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने 'तान् तितिक्षस्व' कहकर सुख-दुःख के द्वंद्वों का निराकरण स्थिरता और धैर्य से करने का उपदेश दिया।

रीडर्स मेल

मीडिया की विश्वसनीयता

मीडिया को भारत के लोकतंत्र में चौथे स्तंभ का दर्जा दिया जाता है। उसकी विश्वसनीयता पर सवाल अब उठने लगे हैं क्योंकि लोक सभा चुनावों के नतीजों ने सभी मीडिया चैनलों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए थे। लगभग सभी चैनलों ने एनडीए को 400 सीट मिलने का दावा कर दिया था जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नारे से मेल खाता था और जो नतीजे सामने आए वो वर्तमान में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के अनुमान से बिल्कुल मेल खाते थे। ऐसे में चैनलों को वास्तविक रिपोर्ट पेश करनी चाहिए वरना उनके दर्शक उन पर से विश्वास खो देंगे और उनकी किसी भी खबर पर यकीन नहीं करेंगे। इन दिनों चैनलों के पास शोध विशेषज्ञों की कमी नहीं होती है। उनकी काबिलियत पर भी सवाल खड़े होने लगेंगे। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जमीनी हकीकत कुछ और हो व लोगों को कोई दूसरी तस्वीर पेश की जाए। ऐसे में सत्ता पक्ष के साथ उनके पक्ष के आंकड़े चलाने से चैनलों की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है।

सिद्धार्थ भट्ट, कानपुर

खेलों को प्रोत्साहन

हर वर्ष 29 अगस्त को भारत में हॉकी के जादुगर मेजर ध्यानचंद को उनकी उपलब्धियों को मान-सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। हमारा देश गांवों का देश है, सरकार को गांवों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित करने के लिए तत्पर रहते हैं। मोदी सरकार ने 'खेलो इंडिया स्कूल गेम्स' टैगलाइन से जो देश के लगभग सभी राज्यों के स्कूलों के विद्यार्थियों को विभिन्न खेलों में प्रतिभा दिखाने का मौका दिया है, वह काफी सराहनीय है। सरकार ने 'खेलोगे तो खिलोगे' का नारा भी दिया है, ताकि जन-जन को खेलों के प्रति प्रेरित किया जा सके। सरकार के ऐसे प्रयासों से ही हमारा भारत दुनिया भर में हर खेल में नम्बर वन बन सकता है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

उम्मीद वास्तविक या छलावा

काहिरा में शांति वार्ता से गाजा और इस्राइल के बीच संघर्ष में स्थायी शांति की उम्मीदें तो जग रही हैं, लेकिन यह वार्ता कितनी वास्तविक है, और कितना दिखावा, इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जब तक हिंसा के मूलभूत कारणों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक यह वार्ता 'हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और' वाली स्थिति में ही रहेगी। इस वार्ता का प्राथमिक उद्देश्य गाजा में हिंसा को रोकना और एक ठोस समाधान खोजना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों पक्षों की आक्रामक नीतियों ने अब तक किसी भी वार्ता को ठोस परिणाम तक पहुंचने नहीं दिया है। कुल मिलाकर काहिरा वार्ता में अगर सचमुच स्थायी शांति का बीज बोना है, तो 'आधा तीतर, आधा बटेर' जैसी नीति छोड़कर वास्तविक और ठोस कदम उठाने होंगे। अन्यथा, शांति की इस आशा को धूल चाटते देर नहीं लगेगी। दरअसल, दोनों तरफ को फैसला करना होगा कि वे वाकई ऐसी बैठक के नतीजे को मानेंगे।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़, उप्र

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-34, अंक 15

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 166

जीएसटी को सहज बनाएं

वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में संभावित बदलावों पर काम कर रहे राज्यों के मंत्रियों के एक समूह ने संकेत दिया है कि फिलहाल उनकी योजना चार दरों वाले मौजूदा ढांचे को बरकरार रखने की है। हालांकि अभी चर्चाएं चल रही हैं और कोई निर्णय नहीं लिया गया है लेकिन समूह के कुछ सदस्यों का कहना है कि चूंकि जीएसटी व्यवस्था स्थिर हो चुकी है इसलिए शायद इसके साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं होगा। बहरहाल, जीएसटी ढांचे को सहज बनाए जाने की तमाम वजह हैं जिनके चलते समूह को इस पर चर्चा करनी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो जीएसटी परिषद की अध्यक्ष भी हैं, ने जुलाई में अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार जीएसटी कर ढांचे को सरल और युक्तिसंगत बनाने के प्रयास करेगी और इसे बाकी बचे क्षेत्रों तक विस्तार दिया जाएगा। राज्यों के मंत्रिसमूह को इस प्रक्रिया की पहल करनी चाहिए। इस संबंध में सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि आगामी नौ सितंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस विषय पर चर्चा की जाएगी।

जैसा कि विशेषज्ञों ने सुझाया भी है, जीएसटी की दरों और स्लैब को युक्तिसंगत बनाने की सख्त आवश्यकता है। परिषद इस चरण में तीन दरों वाले ढांचे को अपनाने पर विचार कर सकती है। अनिवार्य वस्तुओं के लिए कर दर कम रखी जाए, अधिकांश वस्तुओं सेवाओं के लिए मध्यम दर रखी जाए और चुनिंदा वस्तुओं या नुकसानदायक वस्तुओं के लिए दरों को ऊंचा रखा जाए। यह सुझाव भी दिया गया है कि 12 और 18 फीसदी की स्लैब को मिलाकर 16 फीसदी का एक नया स्लैब तैयार किया जाए। इससे जटिलता में काफी कमी आएगी और दरों की बहुलता के कारण उत्पन्न विसंगतियों में से कई दूर होंगी। इसके अलावा समायोजन और दरों को सहज बनाने का काम इस प्रकार करना होगा कि समग्र जीएसटी कर संग्रह राजस्व निरपेक्ष दर के करीब पहुंच सके। ध्यान देने वाली बात है कि कर संग्रह का बड़ा हिस्सा 18 फीसदी के स्लैब से आता है।

शुरुआती वर्षों में जीएसटी दरों को समय से पहले कम कर दिया गया जिससे इसके प्रदर्शन में कमजोरी आई। हालांकि इस कर के क्रियान्वयन के बाद से संग्रह में प्रभावी इजाफा हुआ है। जैसा कि अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन और अन्य लोगों ने इस समाचार पत्र में लिखा है 2023-24 में उपकर समेत विशुद्ध जीएसटी संग्रह सकल घरेलू उत्पाद (जीएसटी) का 6.1 फीसदी था जो 2012-17 के जीएसटी से पहले के दौर के लगभग समान था। यह भी ध्यान देने लायक है कि मौजूदा संग्रह में क्षतिपूर्ति उपकर भी शामिल है जिसे उस कर्ज को चुकाने के लिए जुटाया जा रहा है जो महामारी के दौरान राज्यों के राजस्व में कमी की भरपाई के लिए लिया गया था। जीएसटी परिषद को निकट भविष्य में कर्ज चुकता हो जाने के बाद कभी न कभी इस उपकर के बारे में निर्णय लेना होगा।

एक सुझाव यह है कि इसे कर दर में शामिल किया जाए। हालांकि यह उपभोक्ताओं के वास्तविक कर व्यय पर असर नहीं होगा लेकिन किसी भी निर्णय की सावधानीपूर्वक जांच करना होगा। यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उपकर को सीमित समय के लिए लागू किया गया था और इसका एक खास उद्देश्य था-पहले पांच सालों में राज्यों के राजस्व में कमी की भरपाई के लिए संसाधन जुटाना। संग्रह जारी रहा क्योंकि सरकार को इस पूरी अवधि में राज्यों की भरपाई करनी पड़ी। व्यापक तौर पर दरों को राजस्व निरपेक्ष दर के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। इससे केंद्र और राज्य के स्तर पर राजस्व संग्रह में इजाफा होगा। बढ़ा हुआ राजस्व सरकार के दोनों स्तरों पर उच्च राजस्व को समायोजित करेगा। यह ऐसे समय में होगा जब देश को आम सरकारी बजट घाटा और सार्वजनिक ऋण कम करने की जरूरत है। इस विषय को टालने से जीएसटी व्यवस्था के लिए जरूरी समायोजन में देरी होगी।

अजय मोहंती

अमेरिकी चुनाव के बीच भारत की रणनीति

भारत को अमेरिका में दोनों दलों से मिले समर्थन को राजनीतिक एवं नागरिक समाज के साथ लगातार जुड़कर और मजबूत बनाना चाहिए। बता रहे हैं श्याम सरन

कमला हैरिस नवंबर में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में औपचारिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का सम्मेलन हैरिस के सफल अभियान के शिखर पर पहुंचने का साक्षी बन गया है। कुछ हफ्तों पहले तक हैरिस की पहचान एक मामूली राजनेता और कम प्रभावशाली उप राष्ट्रपति की थी मगर अब वह इस छवि से बाहर निकल चुकी हैं।

मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन ने जब अपनी पार्टी के दबाव में आकर चुनावी होड़ से हटने का निर्णय लिया तो हैरिस को बिना किसी विरोध के आनन फानन में अनौपचारिक रूप से पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। हैरिस के लिए यह सब इतना आसान होगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी को नहीं थी। उनके चुनाव अभियान के लिए अचानक धन का अंबार लगने लगा। कई हफ्तों तक बाइडन प्रशासन के अंदर इस बात पर जोर दिया जाता रहा कि वर्तमान राष्ट्रपति को दूसरे कार्यकाल के लिए भी दावेदारी पेश करनी चाहिए। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि बाइडन पीछे हटेंगे तो हैरिस स्वतः ही विकल्प बन जाएंगी, लेकिन उनमें 'राष्ट्रपति बनने की खूबियां' नहीं हैं। कहा जा रहा था कि वह रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डॉनल्ड ट्रंप को आसान जीत हासिल करने से नहीं रोक पाएंगी।

आज की बात करें तो जनमत सर्वेक्षणों में हैरिस पूर्व राष्ट्रपति एवं अपने प्रतिद्वंद्वी ट्रंप से आगे चल रही हैं। राजनीतिक हवा हैरिस के पक्ष में है। पूरे देश में उन्होंने एक खुशनुमा माहौल बना दिया है और उनके प्रचार अभियान के शेष बचे छह हफ्तों में कोई गंभीर उलटफेर नहीं हुआ तो वह अमेरिका में पहली महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। हैरिस राष्ट्रपति बनने के करीब पहुंच चुकी हैं और अगर निर्वाचित होती हैं तो विश्व के अधिकांश हिस्सों के लिए यह बड़ी राहत होगी। अमेरिका में मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग, विभिन्न देशों में कई नेता और समान विचारधारा के लोग हैरिस की जीत चाहते हैं। हैरिस सर्वेक्षणों में आगे चल रही हैं और उनके पक्ष में हवा बन रही हैं लेकिन कुछ ऐसे कारण भी हैं, जो आने वाले दिनों में उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिका में रहन-सहन महंगा होना हैरिस के लिए नुकसानदेह हो सकता है किंतु नवीनतम आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि कुछ सुधार हुआ है। आव्रजन एक अन्य विषय है, जिस पर ट्रंप अपने सख्त और मुखर नस्लवादी विचारों के कारण हैरिस पर भारी पड़ रहे हैं।

विदेश नीति के मोर्चे पर अगर बाइडन प्रशासन गाजा में संघर्ष विराम कराने में सफल रहता है तो फिलीस्तीन समर्थक, उदार एवं युवा मतदाताओं के बीच हैरिस की राजनीतिक पकड़ मजबूत हो जाएगी। मगर युद्ध जारी रहा और गाजा तथा पश्चिमी तट पर हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले कम नहीं हुए तो हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देने वाले मतदाता मतदान से दूर रह सकते हैं। यह बात अलग है कि इसकी वजह से ट्रंप के मतों में इजाफा नहीं होगा। हैरिस गाजा में तत्काल संघर्ष विराम कराने और हिंसा रोकने के पक्ष में बाइडन की तुलना में मजबूती से अपनी बात रख पाई हैं। वह इस मुद्दे पर अपनी आवाज और बुलंद कर सकती हैं मगर वह इजरायल विरोधी रुख भी अख्तियार नहीं कर सकती हैं। उनका रुख इजरायल विरोधी दिखा तो यहूदियों के वोट ट्रंप को जा सकते हैं।

यूक्रेन युद्ध का महत्त्व शायद कुछ कम होगा। अमेरिका में लोग इस युद्ध से और अपनी सरकार से यूक्रेन को मिल रहे समर्थन से उकता चुके हैं। यूरोप में भी ऐसी ही बात है। रूसी क्षेत्र में हाल में यूक्रेन की सेना का अचानक और साहसिक आक्रमण जारी रहा तो जनता यूक्रेन को सहायता जारी रखने के फैसले को समर्थन दे सकती है। इसके उलट अगर रूस आने वाले हफ्तों में सफलतापूर्वक यूक्रेन की सेना को पीछे धकेल देता है और पूर्वी यूक्रेन में और जमीन पर कब्जा जमाता है तो तस्वीर बदल सकती है।

लोगों ने सोचा होगा कि भारतीय मूल की अमेरिकी राजनेता के शानदार उदय के बाद भारत में भी लोगों के मन में दिलचस्पी और उनके प्रति लगाव बढ़ जाएगा। विदेश में भारतीय मूल के लोगों की सफलता की भारत में काफी सराहना होती है और इसे गर्व समझा जाता है। इस बात की चर्चा भी हो रही है कि किस तरह हैरिस की माता नए मौकों और बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका गईं। अमेरिका में हैरिस की राजनीतिक यात्रा को भी लोगों का ध्यान खींचना चाहिए था मगर मगर ऐसा नहीं हो पाया है। यह असामान्य बात जरूर है।

अमेरिका में चुनाव के बाद अगले वर्ष जनवरी में जो भी प्रशासन (ट्रंप के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी या ट्रंप के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक पार्टी) सत्ता संभाले, भारत को उसके साथ तालमेल बैठाना होगा। अमेरिका में अगर आप अपने मित्रों से बात करें तो अक्सर सुनने में आता है कि डेमोक्रेट मान रहे हैं कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार हैरिस के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक प्रशासन की तुलना में ट्रंप की अगुआई वाली रिपब्लिकन पार्टी सरकार को अधिक पसंद करेगी। वाकई ऐसा है तो भारत को यह धारणा दूर करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे। उन्हें वहां हैरिस से मुलाकात करनी चाहिए, जो इस मामले में फायदेमंद होगी।

पिछले एक दशक में भारत-अमेरिका संबंधों का दायरा बढ़ा है और इसमें काफी परिपक्वता भी आई है। कुछ मसलों जैसे बांग्लादेश आदि पर दोनों देशों के बीच मतभेद हैं मगर सामरिक एवं अहम नीतिगत मोर्चों पर उनके विचार एक जैसे हैं। भारत और अमेरिका में कोई नहीं चाहता कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का दबदबा हो। भारत विकास एवं बदलाव के महत्त्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, इसलिए अत्याधुनिक तकनीक (असैन्य एवं रक्षा क्षेत्रों दोनों के लिए) तक पहुंच इसके लिए अहम है। भारत के लिए अमेरिका खास तौर पर सेवा क्षेत्र के लिहाज से बड़ा बाजार है और भारत की आर्थिक तरक्की के लिए अमेरिका से पूंजी प्रवाह की अहमियत बढ़ गई है। पिछले कई वर्षों से अमेरिका में भारत को दोनों दलों का समर्थन मिलता रहा है। यह सिलसिला जारी रहना चाहिए और राजनीतिक एवं नागरिक समाज के साथ लगातार जुड़कर इसे मजबूत बनाया जाना चाहिए। पहले की ही तरह भारत की आंतरिक राजनीति एवं सामाजिक मुद्दों पर अमेरिका टीका-टिप्पणी करता रहेगा मगर हमारी प्रतिक्रिया सहज एवं परिपक्व होनी चाहिए।

एक ऐसा विषय भी है जिसे दोनों ही देशों को सावधानी से निपटना होगा। यह विषय कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी तत्त्वों की भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोगों द्वारा कथित हत्या के प्रयासों से जुड़ा है। अमेरिका में इस पर मुकदमा शुरू हो चुका है, जिससे यह मामले पेचीदा हो गया है। मगर इसकी छाया दोनों देशों की उस साझेदारी पर नहीं पड़नी चाहिए, जो अनिश्चितता भरे माहौल में भू-राजनीतिक संबंधों का आधार बन चुकी है।

(लेखक विदेश सचिव रह चुके हैं)

बजट में शहरीकरण की योजना

भारत में शहरीकरण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। अभी देश की 35 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरों में रहती है और अनुमान है कि 2050 तक 50 प्रतिशत आबादी शहरों में रहने लगेगी। शहरी विकास पर सरकारों के जोर का इससे बेहतर समय और क्या हो सकता था।

आर्थिक समीक्षा और बजट में समावेशी शहरी विकास की सरकार की परिकल्पना पेश की गई है, जिसमें सस्ते शहरी आवास, रोजगार सृजन विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में और युवाओं तथा बुजुर्गों के लिए रहन-सहन की सुगमता बढ़ाने जैसी जरूरतें शामिल की गई हैं। किंतु हाल में कुछ त्रासदियां हुईं, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में करियर बनाने की चाह में आए तीन युवाओं की अवैध बेसमेंट में डूबने से मौत और देश में भारी वर्षा के कारण हुई मौतें शामिल हैं। इन त्रासदियों ने हमारे शहरों की प्रशासनिक खामियां दुरुस्त करने की जरूरत सामने रखी है।

फिर भी इस वर्ष के बजट में शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले सभी के लिए किफायती आवास मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम के रूप में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों का वादा किया गया है। 'पीएम आवास योजना शहरी' के दूसरे चरण का लक्ष्य 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास की जरूरतों को पूरा करना है।

दूसरा, शहरों को 'विकास केंद्रों' में बदलने के लिए सरकार का इरादा उपनगरीय या शहरों के बाहरी हिस्सों के सुव्यवस्थित विकास के लिए योजना तैयार करने का है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उपनगरीय क्षेत्र आम तौर पर नियमित प्रशासनिक व्यवस्था और उसकी योजना का हिस्सा नहीं बन पाते। तीसरा, विकास बैंकों के साथ साझेदारी के जरिये शहरी सफाई पर जोर दिया गया है ताकि 100 शहरों में जलापूर्ति, गंदे जल के उपचार और ठोस कचरे के प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके।

बजट में एक दिलचस्प बात थी पहले से मौजूद शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास पर ध्यान देना। इसके लिए पहले औद्योगिक उद्देश्यों में इस्तेमाल की गई जमीन को रिहायश के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। इसे 'ब्राउनफील्ड' रणनीति कहा गया जिससे जमीन के सही इस्तेमाल के साथ पर्यावरण संरक्षण भी होता है क्योंकि बेकार पड़ी या ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रही जमीन भी काम में ली जा सकती है। चौथा, सरकार चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट तैयार कर रेहड़ी-फेरी वालों की मदद की योजना भी बनाएगी।

अमित कपूर और विवेक देवरॉय

भारतीय शहरों को आर्थिक विकास के इंजन में बदलने के लिए सरकार ने बुनियादी ढांचे, टिकाऊपन, समावेश और प्रसासनिक सुधारों पर संतुलित तरीके से जोर दिया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल को शहरी प्रशासन की मुख्य धारा में लाए जाने पर भी जोर दिया। सरकार ने भूमि प्रशान, नियोजन एवं प्रबंधन को बढ़ाकर भू प्रबंधन को प्राथमिकता दी है। उसने शहरी नियोजन एवं उपनियम तैयार करने को भी प्राथमिकता में रखा है, जिसे अगले तीन वर्षों में पूरा किया जाना है।

शहरी स्थानीय निकायों पर राजकोषीय बोझ कम करने के लिए कर प्रशासन और भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए एक उन्नत आईटी-आधारित प्रणाली के इस्तेमाल की बात भी कही गई है। शहरों को अधिक रहने योग्य बनाने और नागरिकों की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए परिवहन केंद्रित विकास योजनाएं तैयार और लागू की जाएंगी। इसके अलावा किराये के घरों के बाजार में पारदर्शिता लाने की कोशिश की जाएगी और ऐसे घरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए डॉरमिटरी शैली की एक साथ रहने की जगहें भी शामिल हैं। किंतु शहरी विकास के ये सघन प्रयास हमारे जैसे तेज शहरीकरण वाले देश में समग्रता के साथ होने चाहिए। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन को सहन करने लायक बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां अक्सर हमारे शहरों को पूरी तरह ठप कर देती हैं।

शहरी निवासियों के रहन-सहन में सुगमता बढ़ाने के लिए शहरी शासन की प्रशासनिक प्रक्रिया पर कड़ा नियंत्रण रहना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार न पनप सके। भूमि प्रबंधन पर विचार करते समय अवैध इमारतों और भूमि पर जबरन कब्जे जैसी समस्याओं पर भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इनकी परिणति अक्सर संघर्ष अथवा हिंसा में होती है। किराये के मकानों के मामले में सुधार के साथ ऐसे कानून भी लाए जाने चाहिए, जो मकान मालिकों के कर्तव्यों और किरायेदारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय करें। किराये पर अंकुश के कारगर तरीकों के बगैर किफायती आवास नहीं मिल सकते। हालांकि बजट में इन बातों पर चर्चा नहीं हुई मगर इसका यह मतलब नहीं कि संबंधित पक्ष आगे चलकर इन पर बात नहीं कर सकते।

भारत@100 की कल्पना में शहरी विकास सबसे अहम पहलुओं में शुमार है। उच्च-आय वाला देश बनने के लिए हम जिस तरह की आर्थिक वृद्धि चाह रहे हैं, उसे तभी हासिल किया जा सकता है, जब हमारे शहरों की योजना कुछ इस तरह बनाई जाए कि उनकी अधिकतम क्षमता पर काम किया जा सके। इसके लिए हमें शहरी इलाकों में रहने वाले हाशिये के समुदायों पर भी निवेश करना होगा ताकि वे आर्थिक लाभ से वंचित न रह जाएं।

विश्व बैंक का कहना है कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा शहरों में सृजित होने के कारण बेहतर योजना से शहरीकरण की प्रक्रिया टिकाऊ वृद्धि को तो बढ़ावा देगी ही, उत्पादकता और नवाचार भी बढ़ा सकती है। विश्व बैंक का यह भी कहना है कि 2047 तक आवश्यक शहरी बुनियादी ढांचे का लगभग 70 प्रतिशत अभी बनाया जाना है। ऐसे में सरकार को हर वर्ष जीडीपी का 1.2 प्रतिशत निवेश करना होगा। हम उस लक्ष्य से बहुत पीछे हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें शहरी विकास में सार्वजनिक और निजी निवेश दोनों के विकल्पों को अपनाना होगा।

(कपूर इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटिटिवनेस इंडिया के अध्यक्ष और देवरॉय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। साथ में जेसिका दुग्गल)

आपका पक्ष

जल संरचनाएं विकसित करनी होगी

अब 'जल संरक्षण' को जागरूकता और अपील से आगे बाध्यकारी बनाने का समय आ चुका है। जीवन रक्षक, कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र, उद्योग, मनोरंजन (तैराकी और नौका विहार), जलवायु विनियमन (वाष्पीकरण और वर्षा), परिवहन, प्राकृतिक सौंदर्य, नवीकरणीय ऊर्जा आदि क्षेत्र जल के स्रोतों के महत्त्व को उजागर करते हैं। पूर्वजों द्वारा पेयजल संग्रहण की सदियों पुरानी पद्धति बावड़ियां व कुएं आज भी मौजूद हैं। बावड़ियां, कुएं व तालाब आदि जल संरचनाओं के जरिये हर गांव में जलतंत्र विकसित करके पूर्वजों ने अनूठी मिसाल कायम की थी। ग्रामीण संस्कृति से गहरा नाता रखने वाले पारंपरिक जलस्रोतों की, कृषि अर्थतंत्र को समृद्ध करने में भी मुख्य भूमिका रही है। मगर आज खनन माफिया, उद्योगों व आग उगल रही फैक्टरियों से उत्पन्न जहरनमा प्रदूषण से नदियों

जल के प्राकृतिक स्रोतों बावड़ियों, कुओं आदि की देखभाल करने तथा नए निर्माण की जरूरत है

पानी दूषित हो चुका है। सैकड़ों सरकारी हैंडपंप व पेयजल परियोजनाएं दम तोड़ रही हैं। अतः इन पारंपरिक जलस्रोतों का अस्तित्व बचाना होगा। प्राकृतिक जलस्रोतों का प्रवाह बढ़ाने की दृष्टि से इनका पुनर्जीवीकरण, एक समर्पित मिशन के रूप में किया जाए, ताकि पीने के पानी की उपलब्धता के अतिरिक्त सिंचाई के साधन भी बढ़ाए जा सकें।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

क्लस्टर बनाकर विशेष खेल को मिले बढ़ावा

ओलिंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए चीन की तर्ज पर कम उम्र में ही प्रतिभा पहचान हेतु क्लस्टर बनाकर एक खेल विशेष को बढ़ावा देने के लिए लक्षित निवेश जरूरी है। खेल संगठनों का नेतृत्व संयुक्त रूप से खिलाड़ी और कुशल पेशेवर प्रशासकों द्वारा किया जाए। ताकि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सके। अमेरिका के एनसीएए की तर्ज पर कॉलेजिएट लेवल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास किया जाए। बुनियादी ढांचे में कॉरपोरेट निवेश को बढ़ावा मिलना चाहिए। प्रतिभाओं को पहचानने के लिए अधिक स्थानीय कार्यक्रम आयोजित हो। हर एथलीट को प्रायोजक नहीं मिलते। अतः सरकार द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और नियमित आहार और पोषण के लिए मानक आर्थिक सहायता अथवा मानदेय जरूरी है। प्रतिभा पहचान प्रक्रिया का पेशेवर और निष्पक्ष निर्णय व प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।

प्रिया तनु, बाड़मेर

खेल विशेषज्ञों का मार्गदर्शन आवश्यक

ओलिंपिक स्तर पर हमारे खेल प्रदर्शन का स्तर निरंतर गिरने के बावजूद भी मात्र एक रजत और 5 कांस्य पदक पाकर हम संतुष्ट हो जाते हैं। जरूरत है गहन चिंतन की है कि कतिपय मामूली सुधारों के बावजूद भी खेलों में हम अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच पाते है। ऐसे में आवश्यक है कि खेल संगठनों की बागडोर राजनेताओं के बजाय खेल विशेषज्ञों को सौंप दी जाए। खिलाड़ियों को भी यथासंभव हर सुविधा, सहयोग और प्रशिक्षण देना ही ओलिंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को सीएए के तहत 78 वर्षीय एक पाकिस्तानी ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपा। जोसेफ फ्रांसिस परेरा गोवा की आजादी से पहले पाकिस्तान गए थे और वहां की नागरिकता हासिल की। लेकिन 2013 में वह भारत लौट आए।

107 पदकों के साथ सम्मानजनक प्रदर्शन किया था भारत ने पिछले वर्ष यानी 2023 में आयोजित एशियाई खेलों में, परंतु इसी माह पेरिस में संपन्न ओलिंपिक में भारत को एक रजत पदक और पांच कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा।

राष्ट्रीय खेल दिवस

भारत में ओलिंपिक मेजबानी की आकांक्षा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण के दौरान पेरिस ओलिंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। ओलिंपियनों को दर्शकों के बीच एक गौरवपूर्ण स्थान मिला और प्रधानमंत्री ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बाद में सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 2036 ओलिंपिक की मेजबानी का संकल्प भी दोहराया। वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप ओलिंपिक की मेजबानी के विचार को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है

प्रतीकात्मक

लेफ्टिनेंट जनरल एमके दास
सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी

ओलिंपिक उच्चतम स्तर का खेल आयोजन है और इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी करने का मतलब है कि मेजबान राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर आ गया है। ग्रीष्मकालीन ओलिंपिक हर चार साल में आयोजित किए जाते हैं। आखिरी वाला अभी फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न हुआ है। अमेरिका के लास एंजिलिस में वर्ष 2028 और आस्ट्रेलिया में वर्ष 2032 तक का कार्यक्रम पहले ही तय है। इसलिए भारत को 2036 में ग्रीष्मकालीन ओलिंपिक के लिए दावा करने के लिए अभी से गंभीर प्रयास करना होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2036 में इसकी मेजबानी करने के अपने इरादे को स्पष्ट किया है। भारत सरकार देश में खेल के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए काम कर रही है। अहमदाबाद और उसके आसपास ओलिंपिक की मेजबानी के लिए प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारत को इंडोनेशिया और तुर्की से कड़ी चुनौती मिलेगी जो पहले ही 2036 ओलिंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगा चुके हैं। भारत 2036 ओलिंपिक के लिए आवश्यक प्रस्तावना के रूप में 2030 युवा ओलिंपिक की मेजबानी करने का भी इच्छुक है।

वर्ष 2036 ग्रीष्मकालीन ओलिंपिक की मेजबानी के लिए अंतिम चयन अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आइओसी) द्वारा एक विचार-विमर्श और लंबी प्रक्रिया के बाद किया जाएगा। यह आयोजन स्थल के मास्टर प्लान और दीर्घकालिक विकास योजनाओं के साथ मेजबान राष्ट्र के संरेखण के माध्यम से किया जाता है। आइओसी वित्तपोषण रणनीति व जनता के समर्थन के अलावा भू-राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक-आर्थिक कारकों को भी देखता है।

भारत पहले से ही विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 से पहले शीर्ष तीन में शामिल हो सकता है। इसलिए अगर हम अभी अपने आर्थिक दबदबे का लाभ उठाकर ओलिंपिक के लिए गंभीरता से बोली नहीं लगाते हैं तो यह एक अवसर खो दिया जाएगा। ओलिंपिक की मेजबानी स्पष्ट रूप से हमारी आर्थिक शक्ति की सार्वभौमिक स्वीकृति का संकेत देती है। सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थिरता के साथ मिलकर भारत को एशियाई शक्ति के रूप में ओलिंपिक की मेजबानी के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाता है। आर्थिक रूप से ओलिंपिक की मेजबानी एक महंगा उद्यम हो सकता है, लेकिन भारत और भारतीयों के लिए लाभांश लंबी अवधि में कई गुना मिलेंगे।

अवसंरचना निर्माण : ओलिंपिक का मार्ग मेजबान देश में कई लाभों के साथ खेल संस्कृति को फिर से जीवंत करने की ओर भी ले जाता है। विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण के अलावा अर्थव्यवस्था को व्यापक प्रोत्साहन मिलता है और एक लंबे समय तक चलने वाला पारिस्थितिकी तंत्र उभरता है। पर्यटन को एक बड़ा सहारा मिलता है और विमानन क्षेत्र बेहतर तरीके से जुड़ता है। बुलेट ट्रेन, मेट्रो, सड़क और रेल नेटवर्क जैसी बड़ी दृश्यमान परियोजनाएं बड़े पैमाने पर उभरती हैं। यह रोजगार के बड़े अवसर पैदा करता है और बहुत सारे स्टार्टअप अपने पैर जमाते हैं। परंतु केवल खेल अवसंरचना से ही खेल संस्कृति का सृजन नहीं होता है। खेल महाशक्ति बनने के लिए हमें विभिन्न खेल विधाओं पर ध्यान देना होगा।

भारत ने 2023 एशियाई खेलों में 107 पदकों के साथ सम्मानजनक प्रदर्शन किया, लेकिन पेरिस ओलिंपिक में एक रजत पदक और पांच कांस्य पदक की संख्या को संतोषजनक ही कहा जा सकता है। वर्तमान सरकार ने कई खेलों पर ध्यान केंद्रित किया है, जहां हम एक राष्ट्र के रूप में टैली में सुधार कर सकते हैं, लेकिन दुख की बात है कि हम चीन या जापान की तरह एक प्रमुख ओलिंपिक चैंपियन बनने से बहुत दूर हैं। ऐसी सफलता के लिए भारतीय खिलाड़ियों को खेल अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो अधिक पदक प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, ओलिंपिक में तैराकी में 37 स्वर्ण पदक उपलब्ध हैं, लेकिन भारत ने 2020 और 2024 ओलिंपिक में इनमें एक भी पदक नहीं जीता। इस प्रकार, भारत को एथलेटिक्स, तैराकी, शूटिंग, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन आदि में बड़े पैमाने पर सुधार करना है जो अधिक पदक प्रदान करते हैं।

स्कूलों में खेल को प्रोत्साहन : हमारे देश में स्कूली शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के कारण खेल को स्कूल के दिनों में ज्यादा महत्व नहीं मिलता है। अधिकांश स्कूलों में खेल सुविधाओं की कमी है या मुश्किल से उपलब्ध है। विशिष्ट स्पोर्ट्स स्कूल बहुत कम हैं। इस प्रकार युवा प्रतिभा को पहचानना बड़ी चुनौती हो जाती है। विभिन्न खेल निकायों और खेल प्रशासन को भी अधिक पेशेवर तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए। कुछ स्थानीय स्तर के प्रदर्शन के आधार पर राज्य सरकारों और कारपोरेट उद्योग द्वारा खिलाड़ी के लिए प्रोत्साहन आसानी से दिया जाता है। इससे हमारे खिलाड़ी आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और वे अपने प्रदर्शन में सुधार करने की कोशिश नहीं करते हैं। मेरी राय में, किसी भी खिलाड़ी को एशियाई खेलों के मानक से नीचे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। तथाकथित राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की उपलब्धियां जो फिलहाल प्रोत्साहन का हकदार हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाना चाहिए। एक राष्ट्र के रूप में हमें अपने खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उच्च मानदंड स्थापित करने होंगे।

खेल संस्कृति को बढ़ावा : भारत में सेना और रेलवे जैसे प्रमुख रोजगार प्रदाताओं ने अब तक बड़े पैमाने पर खेलों को बढ़ावा दिया है। अब कारपोरेट से निजी भागीदारी और प्रोत्साहन पहले से काफी बहुत बेहतर है। हम कुछ खेलों में सुधार करने के लिए सही रास्ते पर हैं, क्योंकि यह महसूस हुआ है कि परिणाम निवेश के लंबे समय बाद आते हैं। सही प्रतिभा की पहचान करने के अलावा, प्रशिक्षण में भारी मात्रा में निवेश अपेक्षित लाभांश देता है। सेना के नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलिंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक और पेरिस ओलिंपिक में रजत पदक जीतने का नतीजा इसका एक अच्छा उदाहरण है। एक एशियाई ताकत और उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत है। इसका मतलब है कि अभी से 10 से 12 साल के लड़कों और लड़कियों के बीच सही प्रतिभा की पहचान करना है। तभी ऐसी प्रतिभा को ओलिंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की संभावना है।

वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति की दृष्टि के साथ 2036 में ओलिंपिक की मेजबानी के लिए भारत की आकांक्षा एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया है। हम भारतीयों को 2036 ओलिंपिक की मेजबानी भारत में कराने के लिए सामूहिक रूप से काम करना चाहिए। साथ ही पूरी तैयारी करनी चाहिए कि भविष्य के ओलिंपिक खेलों में पदक तालिका को आगे बढ़ाया जा सके। सभी हितधारकों को भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने के लिए इस राष्ट्रीय गौरव की खोज में एकजुट होना चाहिए।

खेलों के मामले में और आगे बढ़े देश

योगेश कुमार गोयल

वर्ष 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के बाद से भारत में बेहतर खेल सुविधाओं का विस्तार होने लगा और खिलाड़ियों की तैयारियों पर ध्यान देने की संस्कृति विकसित होनी शुरू हुई। डेढ़ दशक में विकसित हुई खेल संस्कृति का ही परिणाम है कि विभिन्न राज्यों के पिछड़े इलाकों से भी खेल प्रतिभाएं निकलकर सामने आ रही हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रही हैं, जो तमाम बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ समय से टारगेट ओलिंपिक पोडियम योजना, खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट आदि कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने 19 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था और उनमें से 16 में पदक जीतकर अहसास करा दिया था कि यदि उन्हें सही ढंग से तराशा जाए तो वे दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में ऐसे खिलाड़ियों ने भी पदक तालिका में जगह बनाकर देश का मान बढ़ाया था, जिनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे। कुल 61 पदकों में से कई पदक महिला खिलाड़ियों ने जीतकर यह भी साबित किया था कि खेल जगत में अब भारत की बेटियां भी बड़े से बड़ा कीर्तिमान बनाने में सक्षम हैं।

भारतीय खेलों की दशा और दिशा सुधरने की सुखद तस्वीर यही है कि भारत की बेटियां भी अब खेलों की दुनिया में निरंतर स्वर्णिम इतिहास लिख रही हैं। पेरिस ओलिंपिक में दो पदक जीतकर नया इतिहास रचने वाली मनु भाकर इसका ज्वलंत उदाहरण हैं। खेलों में हमारी ये उपलब्धियां प्रशंसनीय तो हैं, फिर भी यह सवाल तो उठता ही है कि भारतीय खिलाड़ियों और उनकी तैयारियों में कुछ कमी जरूर है।

इन तथ्यों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि विभिन्न स्पर्धाओं में भारत को जीत दिलाने में बहुत बड़ा योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का रहता है, जहां की आबादी देश की कुल आबादी की लगभग दो प्रतिशत है, लेकिन ओलिंपिक एवं राष्ट्रमंडल जैसी स्पर्धाओं में 30-40 प्रतिशत तक पदक यहीं के खिलाड़ी जीतते रहे हैं। हालांकि यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन अहम सवाल यही है कि अन्य राज्यों में ऐसी ही खेल संस्कृति क्यों नहीं विकसित की जाती, ताकि वहां के खिलाड़ी भी ऐसा ही प्रदर्शन करने में सफल हों और भारत खेलों की महाशक्तियों को चुनौती देते हुए पूरी दुनिया में पदक तालिका में पहले स्थान पर उभर सके? यदि देशभर में खेल प्रतिभाओं के लिए स्वस्थ वातावरण तैयार किया जाए, ताकि खेलों के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

खरी-खरी

मेहमान आ रहे हैं!

पूरन सरमा

मैंने अपने एक मित्र को फोन किया, 'भाई, क्या कर रहे हो?' मित्र ने बहुत अनमने मन से उत्तर दिया, 'अरे यार, रेलवे स्टेशन जा रहा हूं, मेहमान आ रहे हैं।'

मैंने हंसकर कहा, 'क्यों मजाक कर रहे हैं, नई सदी में यह मेहमानों का क्या लफड़ा है? अब कौन मेहमान बनना पसंद करता है और मेजबान भी नहीं रहे।' मित्र ने जवाब दिया, 'मजाक नहीं कर रहा, आज वाकई मेहमान आ रहे हैं और वह भी तीन दिनों के लिए।' मैंने पूछा, 'अब क्या करोगे तुम?'

मित्र बोले, 'अब जो भी होगा देखा जाएगा, दरअसल मेहमान बहुत नजदीक के हैं। उनकी मेजबानी को टाला नहीं जा सकता।'

मैंने पूछा, 'और राशन पानी?'

वह बोले, 'वह तो चिंता की बात नहीं है। सैलरी परसों ही मिली है।'

मैंने कहा, 'भैया ध्यान रखना, अपने शहर में पर्यटन स्थल कई हैं। कहीं वे अपना प्रोग्राम न बदल दें। मेरा मतलब ठहरने की अवधि न बढ़ा दें।'

मित्र ने बताया, 'नहीं-नहीं, वह मैं दो दिनों में ही सलटा दूंगा, ताकि तीसरे दिन तो वे खिसक ही लें। अच्छा मैं बाद में बात करूंगा। जा रहा हूं स्टेशन।'

फोन तो काट दिया, लेकिन मैं डर गया। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, 'तुम्हारे भाई-भाभी भी तो कह रहे थे अगले माह यहां आने के बारे में।'

पत्नी ने कहा, 'अरे, वह तो घर के आदमी हैं। आ जाएं तो क्या फर्क पड़ता है और फिर वे अगले माह आएंगे। छोड़ो व्यर्थ की चिंता।'

वर्मा जी ने बिस्तर टैंट हाउस से मंगवाएं हैं, हम कैसे क्या करेंगे, क्योंकि सर्दी तो अगले माह में भी रहेगी और उन्हें सुलाना कहां है? मेरा मतलब अपने पास किराये के कुल दो कमरे हैं। मेहमानों को सुलाना तो पड़ेगा न,' मैंने कहा।

पत्नी बोली, 'आप, मैं और बच्चे एक जगह सो जाएंगे, उन्हें अपना वाला बैडरूम दे देंगे। आप क्यों फिक्र करते हैं। मैं सब मैनेज कर लूंगी।' मैंने कहा, 'लेकिन भागवान वे बीस को आएंगे। बीस तक तो सैलरी समाप्त हो जाती है। मैं पीएफ से लोन अप्लाई कर देता हूं।'

पत्नी बोली, 'यह आपकी व्यवस्था है, जो भी करना हो, करो। पैसा तो खर्च होगा ही।'

X पोस्ट

तमाम आलोचनाओं के बावजूद जय शाह एक अच्छे क्रिकेट प्रशासक सिद्ध हुए हैं। पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने क्रिकेट को क्लीन किया है। जगमोहन डालमिया के बाद कोई ऐसा व्यक्ति आया, जो इस खेल को इतना बढ़ा रहा है। बाकी खेलों में भी ऐसे लोगों की जरूरत है।

सत्या चौधरी@satyagodara

कंगना रनौत सांसद बन गई हैं, मगर नेताओं की तरह घुमा-फिराकर बयान देना नहीं सीख पाई हैं। बड़े राजनीतिक आंदोलन असल में हाथी की तरह होते हैं, जिनके चार पैर, एक सूंड़ और दो कान होते हैं। किसी एक अंग के बारे में जो फैक्ट है, वही बाकी अंग के बारे में सही हो, यह जरूरी नहीं।

रंगनाथ सिंह@rangnathsingh_

भाजपा कंगना रनौत से किनारा कर लेती है, लेकिन कांग्रेस सैम पित्रोदा की एक के बाद एक गलतियों को बड़ी आसानी से माफ कर देती है। भारतीयों की तुलना अफ्रीकियों या चीनियों से करने का मामला हो या फिर विरासत कर की बात करने पर कांग्रेस ने पित्रोदा को सिर्फ उनका निजी बयान कहकर छोड़ दिया और थोड़े दिन में मामला ठंडा पड़ने के बाद उन्हें उनका पद भी लौटा दिया।

निष्ठा अनुश्री@nishthaanushree

जागरण जनमत | कल का परिणाम

जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस व कांग्रेस का गठबंधन कारगर सिद्ध हो सकता है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या जनधन योजना वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पाने में सफल रही?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

पंचायत हो विश्व की मोदी हों सरपंच,
शांतिपूर्ण हल के लिए जाय सजाया मंच।
जाय सजाया मंच मिलें आ पुतिन-बाइडन,
जेलेंस्की भी आय वहीं खोलें अपना मन।
गिरें शांति के पक्ष सभी नेताओं का मत,
युद्ध रुके चहुंओर सफल तब हो पंचायत।
- ओमप्रकाश तिवारी

विरोध दबाने के बजाय भरोसा जीतना जरूरी

धनंजय प्रताप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद जैसी नगर सरकारों के विरुद्ध तीन वर्ष के पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। राज्य सरकार ने अध्यादेश लागू कर प्रदेश में अब नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के विरुद्ध तीन वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाने का कानून बना दिया। अब अविश्वास प्रस्ताव के लिए दो-तिहाई की जगह तीन-चौथाई पार्षदों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। दरअसल, नगर सरकारों के विरुद्ध पनप रहे विरोध को थामने के लिए राज्य सरकार को यह नई व्यवस्था लागू करना पड़ी है।

प्रदेश में जुलाई-अगस्त 2022 में नगरीय निकायों के चुनाव हुए थे। तब कई वर्षों बाद नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव जनता से सीधे न कराकर पार्षदों के माध्यम से कराया गया। यही कारण है कि अधिकतर अध्यक्ष-उपाध्यक्ष भाजपा समर्थक बने थे। अब इन जनप्रतिनिधियों के दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा था। पुराने नियमों के अनुसार इन संस्थाओं में पहले दो वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था, इसके लिए दो-तिहाई पार्षदों का समर्थन अनिवार्य था। सरकार को अनुमान था कि इन संस्थाओं में बड़ी संख्या में नगर सरकारों के विरुद्ध असंतोष पनप रहा है। इस आक्रोश के चलते नगरपालिका और परिषदों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही थी। यदि अविश्वास प्रस्ताव लाए जाते तो अधिकांश संस्थाओं में भाजपा पार्षदों की आपसी लड़ाई में नगर सरकार पर तीसरा कब्जा कर लेता। यही वजह है कि इस विरोध को थामने के लिए भाजपा सरकार ने अध्यादेश का सहारा लिया। पर सवाल यह है कि अध्यादेश के जरिए सरकार ने नगर सरकार में विरोध को तो थाम लिया, लेकिन चिंता का विषय यह है कि क्या आगे भी यह विरोध थमा रहेगा।

नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के संबंध में बनाया गया नया कानून। प्रतीकात्मक

सरकार का तर्क है कि अविश्वास जैसे कदमों को हतोत्साहित करने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन करने का निर्णय किया है। पर भाजपा के लिए यह कदम बेहद चिंताजनक है। पार्टी ने पिछले एक वर्ष के भीतर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बड़ी बढ़त के साथ चुनाव जीती है। आखिर फिर नगर सरकारों को बचाने के लिए यह कदम क्यों उठाना पड़ा। ऐसा लगता है कि लोकसभा-विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में आए, कहीं न कहीं यह दल-बदल भी एक वजह हो सकती है। इस अभियान के कारण छोटे नगर-कस्बों की स्थानीय राजनीति के समीकरण भी बदल गए हैं। भाजपा ने प्रदेश में लोकसभा में सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। विधानसभा में भी 230 में से 163 सीटों पर विजय हासिल की थी। ऐसे में यह चिंता की बात है कि पार्टी निचले स्तर पर पनप रहे विरोध को भांप नहीं पाई और अध्यादेश लाकर उसे थामना पड़ा। पर क्या एक वर्ष बाद इस स्थिति में कोई बदलाव आ जाएगा। अब 2025 अगस्त के बाद यह विरोध फिर सामने खड़ा होगा।

ऐसे में भाजपा को यह सोचना चाहिए कि विरोध थामने का यह तरीका बेहतर है या विरोध को थामने के बजाय जनता का भरोसा जीतना आवश्यक है। एक समय था जब मध्य प्रदेश में नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव सीधे मतदाता करते थे, तब अविश्वास प्रस्ताव जैसी कोई प्रक्रिया नहीं थी। तब मतदाता ही खाली कुर्सी और भरी कुर्सी के माध्यम से तय करते थे कि अध्यक्ष का कामकाज ठीक है नहीं, उसे पद पर बने रहने का अधिकार है या नहीं। सरकार ने ये दोनों व्यवस्थाएं बदल दीं और नगरीय निकायों में महापौर को छोड़कर बाकी निकायों में परोक्ष चुनाव कराए। पार्षदों ने अध्यक्ष चुने। सरकार भाजपा की थी तो सभी जगह नगर सरकारों पर भाजपा काबिज है। अब पार्षदों का यह विरोध धीरे-धीरे जनता के बीच पहुंच रहा है।

वर्ष 2022 के पहले लगभग तीन वर्ष इन सरकारों में चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। यहां प्रशासक तैनात थे। प्रशासकों ने इन संस्थाओं का ऐसा दोहन किया कि छोटी से छोटी नगरपालिका पर कम से कम 20 करोड़ की देनदारी बाकी है। इन संस्थाओं के सामने संकट यह है कि देनदारी चुकाएं या जनता को सुविधा मुहैया करवाएं। जनता परेशान हो रही है तो वह पार्षदों पर दबाव बनाती है। पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ आक्रोश जताते हैं और यही कारण है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति बनती है। सरकार ने तो अध्यादेश लाकर नगर सरकारों के विरुद्ध आक्रोश को एक वर्ष के लिए थाम दिया, लेकिन यही स्थिति एक वर्ष बाद फिर बनेगी। उसके लिए भाजपा को अभी से चिंता कर कोई ऐसी कार्ययोजना बना लेना चाहिए कि नगर सरकारों में सभी जनप्रतिनिधि मिल जुलकर चलें।

मंथन

दूर हो नदियों के प्रवाह की बाधा

आज हमारी नदियां संकुचित हो रही हैं। देश के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए नदियों के प्रवाह क्षेत्र में आने वाली तमाम बाधाओं को मुक्त किया जाना चाहिए

रमन कांत
अध्यक्ष, भारतीय नदी परिषद

देश की अधिकांश नदियां उफान पर हैं। रोजाना देश के विभिन्न हिस्सों से खबरें आती हैं कि नदी के तेज बहाव में गाड़ियां बह गईं, कुछ लोग बह गए, मकान बह गए, नदी का पानी खेतों तथा आबादी में घुस गया। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसे कौन से कारण हैं जो नदियां इतनी तबाही ला रही हैं? क्या ऐसा पहले भी होता रहा है या फिर अभी ही हो रहा है? हम इन सवालों के जवाब जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। केवल मौसम परिवर्तन की समस्या बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं।

ऐसा नहीं है कि पचास या सौ वर्ष पूर्व बाढ़ नहीं आती थी या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में इतनी तबाही नहीं होती थी। ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन मीडिया के इतने साधन और इतनी घनी आबादी का दबाव पहले नहीं था, जिस कारण से ये खबरें या घटनाएं उस अनुपात में नहीं मिल पाती थीं। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमारे लिए देश के नदी तंत्र को समझना आवश्यक है। भारत के संपूर्ण नदी तंत्र को हिमालयी नदियां और प्रायद्वीप की नदियों में बांटकर देखा जाता है। अगर इसकी और तह में जाएंगे तो जहां हिमालय की नदियों को सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में विभाजित करके देख सकते हैं, वहीं प्रायद्वीप की नदियों को अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के रूप में विभाजित करके देख सकते हैं।

अतिक्रमण : पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला अभी अपनी युवावस्था में है, जिसके चलते हिमालय की सभी नदियां अपनी स्थाई घाटियां अभी तक नहीं बना पाई हैं और यहां के पहाड़ भी अभी पूरे नहीं बने हैं। जबकि प्रायद्वीप की नदियां अपनी घाटियां बना चुकी हैं और यहां के पहाड़ भी स्थाई हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में भी संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में विकास के नाम पर मनमाने तरीके से होटल, घर, सड़कें, पुल व बांध आदि बनाए जा रहे हैं। हिमालय क्षेत्र में नदियों की घाटियों व उनके संभरण क्षेत्र में अतिक्रमण किया जा रहा है। आबादी का बढ़ता दबाव और पर्यटकों की मांग पर उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में अनियोजित विकास हो रहा है। वहीं पूर्वोत्तर भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर किसी के घर पर कोई दूसरा कब्जा कर ले और जब मकान मालिक अपना कब्जा छुड़ाने आए तो कब्जाधारी को पीड़ित बताकर कहा जाए कि उसे घर से निकाल दिया गया।

वास्तव में नदियों की जमीनों पर कब्जे जमा लिए गए हैं। बरसात में जब नदियों में अधिक पानी आता है तो उन कब्जाधारियों के मकान, दुकान व होटल आदि नदी की तेज धारा को सह नहीं पाते हैं तो ऐसे में वे स्वयं को पीड़ित बताने लगते हैं। उस घटना को सभी के सामने प्रस्तुत भी ऐसे किया जाता है जैसे नदी ने अपने संभरण क्षेत्र से बाहर आकर सब कुछ तबाह कर दिया हो, जबकि ऐसा नहीं है। नदी के बहने का अपना एक क्षेत्र होता है, उसमें नदी वर्ष दर वर्ष इधर-उधर बहती है। यह नदी की प्रकृति है, लेकिन नदी अगर दस या बीस वर्षों तक एक ही ओर बहती रहे तो कब्जाधारी नदी के दूसरे छोर को कब्जा करने के लिए उपयुक्त भूमि मानने लगते हैं। नदियों की अपनी एक स्मरणशक्ति होती है तथा उनमें बाढ़ आने का एक पैटर्न होता है। इसे दस, बीस, पचास व सौ वर्षों के अंतराल में भी विभक्त किया जाता है। बाढ़ का यह पैटर्न असल में वर्षा के अल्प, अधिक या अत्यधिक होने से तय होता है।

देश में कोई नदी ऐसी नहीं है जो अपने बाढ़ क्षेत्र से बाहर अपने पानी को फैलाती है। पिछले वर्ष दिल्ली में यमुना नदी जब लाल किले की दीवार तक पहुंच गई तो हाय-तौबा मच गई कि यमुना नदी ने तबाही मचा दी है, जबकि यमुना नदी वास्तव में लाल किले के पास से होकर ही बहती थी। लाल किले से लेकर यमुना नदी के वर्तमान किनारे तक पूरा क्षेत्र यमुना का अपना है। इसी प्रकार हिंडन नदी का पानी जब निकट की आबादी में घुस गया तो हंगामा हो गया कि नदी ने तबाही मचा दी है, जबकि गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में हिंडन नदी का संभरण क्षेत्र कब्जा लिया गया है। वर्तमान में त्रिपुरा की बाढ़ हो या फिर हिमाचल प्रदेश की नदियों से आने वाली तबाही, ये नदियों के गूढ़ संकेत हैं। नदियां बोल नहीं सकती हैं, लेकिन वे प्रत्येक वर्ष बरसात में हमें अपने वेग से आगाह करती हैं कि अब संभलने का समय है।

नदियां प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और प्रकृति अधिक समय तक अन्याय नहीं सहती है, यह सब इतिहास से जाना-समझा जा सकता है। नदियों की हदबंदी से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को प्रतिबंधित किया जाए। यदि मानव के मूल अधिकार हैं तो मानव की जीविका को चलाने वाली नदियों के अधिकार भी होने चाहिए। अगर देश की नदियां मुक्त होती हैं तो उनकी संपूर्ण जैव-विविधता पुनः लौट आएगी तथा उनके प्रदूषण में भी कमी आएगी। अब देश में नदियों को मुक्त किया जाना चाहिए। इसमें जहां समाज को अपनी भूमिका तय करनी चाहिए, वहीं सरकार को भी सख्त कदम उठाकर इसे प्रोत्साहित करना चाहिए।

अतिक्रमण से बचाव करने पर ही कायम रह सकेगा नदियों का अस्तित्व। फाइल

****

दैनिक जागरण

दृढ़ इच्छाशक्ति से ही इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं

राष्ट्रपति की पीड़ा

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज की प्रशिक्षु महिला डाक्टर की अस्पताल में ही दुष्कर्म के बाद हत्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इन शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त कर जनता के आक्रोश को ही अभिव्यक्ति दी कि वह इस घटना को लेकर निराश एवं भयभीत हैं और आम लोगों की तरह गुस्से में हैं। उन्होंने यह भी बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत हो गया, अब कुछ करना होगा, क्योंकि सभ्य समाज में ऐसे अपराध स्वीकार्य नहीं। अच्छा होता कि उनकी प्रतिक्रिया पर राजनीतिक दल दलगत हितों से ऊपर उठकर गंभीरता से विचार करते, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ दलों के नेता इस पर भी ओछी राजनीति कर रहे हैं। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने तो उनके कथन पर आपत्ति जताई ही, कांग्रेस को भी परेशानी हो गई। इन दलों के नेताओं का तर्क है कि राष्ट्रपति ने अन्य घटनाओं पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? यह कुतर्क ही है, क्योंकि राष्ट्रपति ने साफ कहा कि एक ओर छात्र, डाक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो दूसरी ओर अपराधी अन्य जगहों पर घूम रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ितों में स्कूली बच्चियां भी शामिल हैं। स्पष्ट है कि वह दुष्कर्म की अन्य घटनाओं की ओर भी संकेत कर रही थीं। क्या राष्ट्रपति के बयान से असहमत विपक्षी नेता यह चाह रहे हैं कि उन्हें दुष्कर्म की हर घटना का उल्लेख करना चाहिए? आखिर वह कितनी घटनाओं का उल्लेख करें, क्योंकि दुष्कर्म की न जाने कितनी घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं।

आखिर राष्ट्रपति के कथन पर क्षुद्रता का परिचय दे रहे नेता उनकी यह बात सुनने को क्यों नहीं तैयार कि समाज को ईमानदार एवं निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की जरूरत है और उसे खुद से कुछ कठिन सवाल भी पूछने चाहिए? ये सवाल तभी पूछे जा सकते हैं, जब नेता दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध पर सस्ती राजनीति करने से बाज आएं और कोलकाता जैसी घटनाओं पर लीपापोती करने का काम न करें। कोलकाता की घटना पर देश इसीलिए गुस्से में है, क्योंकि ममता सरकार और उनकी पुलिस ने इस घटना पर लीपापोती करने की कोशिश की। इसी कारण उसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से फटकार मिली। राजनीतिक दलों को यह समझने की सख्त जरूरत है कि सभ्य समाज को शर्मिंदा करने वाली दुष्कर्म की घटनाओं की एक स्वर में निंदा की जानी चाहिए। इन घटनाओं पर राजनीति तभी होती है, जब शासन-प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही ढंग से नहीं करता। निःसंदेह यह भी समझा जाना चाहिए कि दुष्कर्म की घटनाएं एक सामाजिक बीमारी का परिचायक हैं। महिलाओं को कमतर समझने और उनके प्रति दूषित मानसिकता रखने वाले ही इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। समाज को ऐसे तत्वों को हेय दृष्टि से देखने के साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी सक्रिय होना होगा। इसमें सफलता तब मिलेगी, जब राजनीतिक दल अपना रवैया सुधारेंगे।

बड़ी पहल

लोक-परलोक में आस्था रखने वाले हिंदू समाज में कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिन्हें सामर्थ्य न होने के बावजूद लोग निभाते हैं और कभी-कभी तो कर्ज में भी दब जाते हैं। मृत्युभोज भी ऐसी ही परंपरा है और चूंकि हमारे समाज में पीढ़ियों से व्याप्त है, इसलिए इसका सम्मान तो किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बहाने आडंबर दिखाने की प्रवृत्ति अब खत्म होनी चाहिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक गांव रेवन की पंचायत ने सर्वसम्मति से मृत्युभोज न करने का निर्णय लेकर न केवल अन्य लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है, बल्कि अपने प्रगतिशील सोच को भी सामने रखा है। इस गांव के लोगों का कहना है कि आत्मा की शांति के लिए तर्पण, हवन और ब्राह्मण भोज किया जाना तो उचित है, लेकिन सामूहिक मृत्युभोज के बहाने वैभव का प्रदर्शन उचित नहीं है। यह सही भी है, क्योंकि कहीं-कहीं तो मृत्युभोज का इतना भव्य आयोजन देखने को मिलता है जैसे कोई सामाजिक समारोह हो। झांसी में भले ही अभी एक गांव ने इस तरह के समारोह को त्यागने की घोषणा की है, लेकिन संभव है कि अन्य गांव भी अनुसरण करें। वस्तुतः आजादी के बाद हिंदू समाज की जागरूकता से ही कई कुप्रथाओं का खात्मा हुआ है। बाल विवाह हमारे यहां सबसे बड़ा सामाजिक अभिशाप था और यह अब लगभग खत्म है। दहेज को लेकर भी सामाजिक चेतना बढ़ रही है। अस्पृश्यता भी खत्म है और अब मृत्युभोज को लेकर भी सामाजिक विमर्श देखने को मिलेगा। जिस दिन लोग 'समाज क्या कहेगा' के भय से मुक्त हो जाएंगे, उसी दिन से अपनी सामर्थ्य के हिसाब से परंपराओं का निर्वहन भी करने लगेंगे। पूर्व में भी कई ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं, जब लोगों ने मृत्युभोज न करके उसमें खर्च होने वाली राशि को समाज में निर्बलों पर खर्च कर दिया। अच्छा होगा कि इस पर होने वाला खर्च बच्चों की शिक्षा और लड़कियों के विवाह पर हो।

दोहराई जाए आइफोन की सफलता गाथा

गुरचरण दास

सेवा क्षेत्र में तो भारत विश्व के 'बैक-आफिस' के रूप में तब्दील हो गया, लेकिन 'दुनिया के कारखाने' के रूप में रूपांतरित नहीं हो पाया है

विश्व में सबसे तेज गति से वृद्धि कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित न हो पाना ऐसी ही एक चुनौती है। इसका मुख्य कारण यह है कि देश किसी बड़ी औद्योगिक क्रांति के सूत्रपात में विफल रहा है। हालांकि हाल में सामने आई एक सफलता गाथा ऐसी स्थापित धारणाओं को ध्वस्त करने वाली है। इसने उम्मीदें जगाने के साथ ही यह भी सिखाया है कि अभी और क्या-क्या किया जाना शेष है। क्या इससे सबक लेते हुए हम लेबर इंटेंसिव यानी बड़े पैमाने पर श्रम की खपत करने वाले क्षेत्रों में इस सफलता को दोहरा सकते हैं? भारत में बेरोजगारी समस्या नहीं, बल्कि रोजगार के लिए काबिल लोगों की कमी उससे बड़ी समस्या है। तमाम लोग खेतों से लेकर बाजार तक कम उत्पादकता वाले कामकाज या असंगठित रोजगार में सक्रिय हैं, लेकिन वे गुणवत्तापरक एवं अधिक उत्पादक रोजगार के आकांक्षी हैं। हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान कई सर्वे में सामने आया कि अच्छी नौकरियों को लेकर कितना असंतोष है। अनपेक्षित चुनाव नतीजों में एक पहलू यह भी माना गया।

निःसंदेह 1991 में आरंभ हुए आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। सेवा क्षेत्र में तो भारत विश्व के 'बैक-आफिस' के रूप में तब्दील हो गया है, लेकिन 'दुनिया के कारखाने' के रूप में रूपांतरित नहीं हो पाया है। जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी अभी भी 15 प्रतिशत से कम है, जिसमें देश की 11 प्रतिशत आबादी लगी हुई है, जिनके माध्यम से विश्व में आपूर्ति की जाने वाली महज 2 प्रतिशत वस्तुओं का ही उत्पादन हो पा रहा है। विश्व में कोई भी देश खुद को विनिर्माण महाशक्ति बनाए बिना विकसित नहीं हो पाया। इसके बिना वह लोगों को गरीबी से उबार नहीं पाया है। जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन सभी ने लेबर इंटेंसिव विनिर्माण में खुद को संवारने एवं निर्यात बढ़ाने वाले तरक्की के मंत्र को अपनाया। चीन इसका सबसे ताजा उदाहरण है। अच्छी बात है कि भारत में भी इस मोर्चे पर कुछ शुभ संकेत दिखने लगे हैं। दिग्गज कंपनी एपल ने अपनी वैश्विक आपूर्ति के लिए उत्पाद तैयार करने के लिहाज से भारत को अपने दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में चुना है। 2021 तक आइफोन पूरी तरह चीन में बनते थे। आज आइफोन निर्माण के चलते भारत में डेढ़ लाख प्रत्यक्ष नौकरियां और करीब साढ़े चार लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिला है। अभी देश में 14 अरब डालर के आइफोन निर्मित हो रहे हैं, जिसमें से 10 अरब डालर के फोन का निर्यात किया जा रहा है। यह आइफोन के वैश्विक उत्पादन का केवल 14 प्रतिशत ही है, जिसके 2026 तक बढ़कर 26 से 30 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। स्वयं को निर्यात के एक गढ़ के रूप में स्थापित करने के लिए भारत को आइफोन के कंपोनेंट यानी उसमें लगने वाले कलपुर्जा निर्माताओं को भी लुभाना होगा, जिनकी समूचे वैल्यू-एडिशन में करीब 85 प्रतिशत की भागीदारी है। ऐसे अधिकांश कंपोनेंट निर्माता मुख्यतः चीनी हैं। उनके आने से न केवल रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे, बल्कि कौशल विकास के विस्तार के साथ ही तकनीकी हस्तांतरण की प्रक्रिया भी तेज होगी। यही वह राह है, जिससे हमारे एमएसएमई ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ सकते हैं। वर्षों पहले मारुति के मामले में ऐसा हो चुका है। इसका एक अतिरिक्त लाभ चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को पाटने में भी होगा।

अवधेश राजपूत

देश में आइफोन सफलता गाथा साकार हो सकी तो इसका श्रेय संवेदनशील सरकारी वार्ताकारों को भी जाता है, जिन्होंने खुलेपन से कंपनी के आग्रहों को सुनकर उसकी आवश्यकता के अनुरूप प्रविधानों को हरी झंडी दिखाई। इस सफलता गाथा का एक सबक यह भी है कि कोई भी देश केवल घरेलू बाजार के दम पर पर्याप्त रोजगार अवसर नहीं सृजित कर सकता। चीन हमसे कहीं बड़ा बाजार है, लेकिन सफलता के लिए वह भी निर्यात पर निर्भर है। इसके लिए ऊंची टैरिफ दरों से परहेज करना होगा। इसके बिना भारत ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा नहीं बन सकता।

रोजगार सृजन में एमएसएमई के मुकाबले बड़ी कंपनियां कहीं अधिक मददगार हो सकती हैं। उनके लिए आपूर्तिकर्ता की भूमिका छोटी कंपनियों के लिए भी लाभदायक होगी। इसलिए सरकार को ऐसी दिग्गज कंपनियों को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो चीन में विनिर्माण को लेकर जोखिम महसूस कर रही हैं। वैश्विक बाजार में सफलता के लिए उत्तम कोटि के उत्पाद अपरिहार्य होते हैं। इस दिशा में अगला कदम यह होना चाहिए कि लेबर इंटेंसिव क्षेत्रों में दिग्गज ब्रांडों को लुभाकर आइफोन की सफलता गाथा दोहराई जाए। इसके लिए कौशल विकास का स्तर भी सुधारना होगा। कौशल मिशन जैसे हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि वे उद्योग जगत की जरूरतों के अनुरूप काम नहीं कर रहे। ऐसे में, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और काम के दौरान प्रशिक्षण ही कारगर उपाय हैं।

चीन, वियतनाम और अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उत्पादन लागत के मोर्चे पर भारत पिछड़ा रहा। इस स्थिति में सुधार के लिए की गई पीएलआइ जैसी पहल सब्सिडी न होकर भूमि, श्रम, ऊर्जा और परिवहन लागत जैसे उन पहलुओं पर समायोजन करती है, जहां भारत पिछड़ा है। डब्ल्यूटीओ नियमों के चलते निर्यात प्रोत्साहनों को लेकर हाथ बंधे होने के कारण स्मार्टफोन पीएलआइ ने उत्पादन के ऐसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए, जिन्हें रोजगार और निर्यात में भारी बढ़ोतरी के जरिये ही हासिल कर पाना संभव था।

भारत में एपल की सफलता से संदेश गया है कि विनिर्माण के लिए भारत प्रतिकूल नहीं है। अब परिधान, फुटवियर, खिलौना और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भी इस कामयाबी को दोहराया जाए। इसके लिए केंद्र को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। राज्यों को भी आगे आना होगा। अभी दक्षिण और पश्चिम के राज्य ही इन पहलुओं को समझ रहे हैं। याद रहे कि ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने के लिए भारत को केवल एशियाई प्रतिस्पर्धियों से ही नहीं, बल्कि ओहायो जैसे अमेरिकी राज्यों से भी कड़ा मुकाबला करना है। इसके लिए आवश्यक सुधारों को जितना जल्दी आरंभ किया जाए, उतना ही बेहतर।

(प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े लेखक जाने-माने स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

संकीर्ण स्वार्थों के लिए जाति का सहारा

जगमोहन सिंह राजपूत

इस समय देश में जाति को लेकर जो भी चर्चा हो रही है, उसमें उसके उन्मूलन की कोई बात नहीं हो रही

लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति के लिए हर नागरिक को प्रयास करने का अधिकार है। अपेक्षा यह है कि इसके लिए जो भी तरीके और रणनीतियां अपनाई जाएं, वे लोकतंत्र और संविधान के दायरे में हों। यह तो कक्षा छह-सात का विद्यार्थी भी जानता है कि भारत का संविधान जाति प्रथा को पूरी तरह अस्वीकार करता है। सामान्य नागरिक की अपेक्षा यही रहती है कि कोई भी दल ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिसमें उसे जाति या वर्ग विशेष का सहारा लेना पड़े। संविधान निर्माता जानते थे कि इस प्रथा की जड़ें कितनी गहरी हैं, फिर भी उन्होंने जाति प्रथा उन्मूलन को स्वीकार किया, क्योंकि एक सशक्त राष्ट्र के स्वरूप लेने के लिए इसके उन्मूलन की आवश्यकता को वे समझते थे। इस समय देश में जाति को लेकर हर प्रकार की चर्चा चल पड़ी है, जिसमें इसके उन्मूलन के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस समय संविधान बना, तब लोगों ने किन परिस्थितियों में जाति प्रथा उन्मूलन को आवश्यक समझा, कैसे अपने को उसके लिए तैयार किया, इसकी सबकी अपनी-अपनी समझ हो सकती है, मगर इसका पक्षधर होना इस युग में असंभव है।

जब भारत को आजादी मिली, तब मैं केवल चार वर्ष का था। समय के साथ आजादी, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र और लोकतंत्र जैसे शब्दों और उनके अर्थ से परिचय होता गया। बहुत कुछ स्कूल और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों से सीखा। आज यह सोचकर आश्चर्य होता है कि उस कठिन समय में भी देश में हर ओर सकारात्मकता थी। सभी एक-दूसरे के निकट आना चाहते थे। देश के विभाजन और उसके कारणों को सामान्य नागरिक की तरह परिचित होकर जब उस समय की ओर निगाह डालता हूं तो ग्रामीण समाज की प्रौढ़ता और वैचारिक परिपक्वता के प्रति नतमस्तक ही हो सकता हूं। तब पारस्परिकता हर ओर दिखाई देती थी। जाति प्रथा प्रचलित थी, लेकिन लोगों को यह बात करते सुनता था कि जैसे जमींदारी समाप्त हुई, वैसे ही अब जाति प्रथा भी समाप्त हो जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हर प्रांत और जाति से विद्यार्थी आते थे। बड़े-बड़े नेता भी आते थे। पंडित नेहरू राष्ट्र के दुलारे थे। लोहिया जी उनकी आना-पाई तक की विवेचना और आलोचना करते थे। हम सब आनंद से सुनते थे, लेकिन यह भी देखते थे कि कभी किसी

भारत के भविष्य से खेलने वाली राजनीति। प्रेट्र

के मुंह से स्तरहीन भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। संसद में बहस के जो समाचार छपते थे, उनमें देश के प्रति चिंता, समस्याओं पर अध्ययन-पश्चात तैयार किए भाषण, पारस्परिक आदर के साथ राजनीतिक दुर्भावना की पूर्ण अनुपस्थिति युवाओं को प्रभावित करती थी। आज हर ओर फैली नकारात्मकता को देखकर निराशा होती है। जिन अनगिनत लोगों ने ग्रामीण वातावरण में जाति प्रथा को देखा-परखा या जिया होगा, वे सहमत होंगे कि तब भी आपसी सहयोग, पारस्परिकता और सामाजिक भागीदारी उपस्थित थी। स्थिति उतनी भयावह नहीं थी, जितनी आज के अनेक नेता अपने कुतर्क को संबल प्रदान करने के लिए बताते हैं। उसे सही दिशा देना उस समय अधिक आसान था। सभी जाति के बच्चों को यही सिखाया जाता था कि आयु में बड़े सभी वर्गों के लोगों को सम्मानसूचक ढंग से ही संबोधित करना है। सभी चाचा, काका या ताऊ ही थे। उस समय अधिकांश का विश्वास था कि गांधी जी ने जो कुछ सिखाया है, उसकी पूरी समझ विकसित होने के बाद और शिक्षा के प्रचार-प्रसार के पश्चात जाति भेद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे विचार उन लोगों के भी थे, जो साक्षर नहीं थे, लेकिन मानवीय गुणों से ओतप्रोत थे।

स्वतंत्रता संग्राम लोगों को जातियों में बांटकर नहीं लड़ा गया। नेताजी ने जो आजाद हिंद फौज बनाई, वह उन सभी सिद्धांतों का व्यावहारिक स्वरूप थी, जिसमें जाति, पंथ, भाषा या क्षेत्र जैसे किसी सोच का कोई स्थान नहीं था। जिस जाति प्रथा उन्मूलन के लिए कितनों ने संकल्प लिया और जिससे मुक्ति के लिए गांधी, मदन मोहन मालवीय आदि ने अनेकानेक प्रयास किए, उसे केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए बनाए रखने के कितने ही प्रयास नेता दशकों से करते आ रहे हैं। सामाजिक नकारात्मकता के बीज पिछले कुछ दशकों से लगातार बोए जा रहे हैं। 1960 में संसद को पहली बार देखकर मैं नतमस्तक हुआ था कि देश के लिए नेतृत्व का प्रवाह यहां से होता है और यहां ऐसे मनीषी बैठते हैं, जो अपने त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। आज वहां अधिकांश सदस्य इसलिए जाने जाते हैं कि वे कितने वैभव के धनी हैं। जब राजनीति में सोच सत्ता तक पहुंचने की लालसा से आच्छादित हो जाता है, तब व्यक्ति अप्रत्याशित निर्णय ले लेता है, जो देश के लिए तो निराशाजनक होते ही हैं, उसके लिए भी आत्मघाती सिद्ध होते हैं। 1975 का आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस संसद को याद करें, जिसने संविधान के आत्मा से छेड़छाड़ करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। संविधान निर्माताओं के प्रति इससे बड़ा अनादर क्या हो सकता था कि संविधान के आमुख को ही बदल दिया जाए और उसमें वे शब्द डाले जाएं, जिन्हें संविधान सभा में बहस के बाद अस्वीकृत कर दिया गया था। इस बदलाव के समय सारा विपक्ष जेल में था। डा.आंबेडकर के अनुयायी होने का दावा करने वाले इस अपमान को कैसे सहन कर रहे हैं?

जो नीति या निर्णय देश के भविष्य, भाईचारे, सामाजिक और पंथक सद्भाव को ध्यान में रखकर नहीं लिए जाते, वे देश के प्रति द्रोह ही हैं। जो लोग निजी या दलगत स्वार्थों के लिए जाति को प्रासंगिक बनाए रखने की किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष कोशिश में संलग्न हैं, वे निश्चित ही भारत के भविष्य से खेल रहे हैं। आखिर ये लोग अपने को गांधी का उत्तराधिकारी कैसे कह सकते हैं?

(लेखक शिक्षा, सामाजिक सद्भाव और पंथक समरसता के क्षेत्र में कार्यरत हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सपनों का सौंदर्य

हम सभी सपने देखते हैं। उन सपनों में अपने हिसाब से रंग भरते रहते हैं। सपना और कल्पना दोनों अलग-अलग चीजें हैं। सपनों की दुनिया को वास्तविकता के धरातल पर उतारा जा सकता है। जबकि कल्पना लोक से बाहर निकलने का साहस कम ही लोग कर पाते हैं। सपनों का सौंदर्य हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह प्रेरणा हमें कर्म करने की ओर प्रेरित करती है। बिना परिश्रम किए सपनों की दुनिया में खोए रहना बेईमानी है। हमें सपनों को धरातल पर उतारने के लिए भगीरथ प्रयत्न करने होते हैं। तब जाकर ही सपनों के साम्राज्य पर विजय प्राप्त की जा सकती है। स्वप्न विहीन व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। लक्ष्यों को साधने के लिए भविष्यद्रष्टा होना पड़ता है। बड़े स्वप्न, बड़े लक्ष्य को भेदने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जब सपने पूर्ण होते हैं तो अप्रतिम आनंद के स्रोत फूटने लगते हैं।

स्वप्न देखने का लाभ तभी है जब हम उसे पूर्ण करने के लिए जीवटता और समर्पण के साथ लग जाएं। एक विद्यार्थी का स्वप्न होता है कि वह अपनी कक्षा में प्रथम आए, एक किसान का स्वप्न होता है कि उसकी खूब पैदावार हो। हर व्यक्ति जीवन के हर पड़ाव में कोई न कोई सपना अवश्य देखता है। यदि वह इन सपनों की यथार्थता के लिए पूर्ण मनोयोग से जुट जाता है तो सफलता का सर्वोच्च शिखर प्राप्त कर लेता है। किसी घटना या जन्म से दिव्यांग व्यक्ति भी जीवन में सफल होने के सपने बुनने लगता है। वह अपने लिए कोई एक कार्य क्षेत्र चुनता है। फिर हर चुनौती से लड़ता हुआ सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। उसकी निरंतरता उसे उसके कार्यक्षेत्र में निपुण बना देती है। यदि वह सफल होने के स्वप्न नहीं देखता और उसे पूर्ण करने के लिए परिश्रम के रथ पर सवार नहीं होता तो शायद ही वह सफल हो पाता। हमें जीवन में सपनों को पूर्ण करने के लिए परिश्रम के पथ पर गतिशील रहना चाहिए।

ललित शौर्य

हैप्पी नहीं, शुभ होते हैं भारतीय त्योहार

राजकुमार जैन

शुभ कहना एक लोक मंगल कामना से भरा भाव होता है, जबकि हैप्पी यानी खुशी एक नितांत निजी भाव है

समाज में त्योहार ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जो लोगों को कलात्मक अभिव्यक्ति, संगीत, भोजन और परंपराओं के विभिन्न रूपों का उत्सव मनाने और उनका आनंद लेने के लिए एक साथ लाते हैं। अभी त्योहारों का समय है। राखी मनाई जा चुकी है, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भी उत्साह से मनाई गई है। गणेश चतुर्थी के साथ दस दिनी गणेशोत्सव मनाने की तैयारियां जोरों पर है, नवरात्र भी पूरे देश में मनाया जाएगा। सबसे बड़े त्योहार दीपावली का इंतजार सभी को रहता है। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है और यही हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं।

त्योहार किसी समुदाय, क्षेत्र या देश की सांस्कृतिक पहचान में निहित होते हैं तथा उसकी परंपराओं और विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने का काम करते हैं। हम भारतवासी अपने सभी त्योहार सदियों से मनाते आ रहे हैं। त्योहारों पर एक दूसरे को शुभकामना प्रेषित करने की परंपरा भी सदियों पुरानी है और हम भारतीय यह कार्य या तो हिंदी में या अपनी क्षेत्रीय भाषा में करते आए हैं। शुभकामना यानी शुभ होने की कामना करना और इसी कामना के साथ शुभकामना देते समय शुभ होली, शुभ दीपावली, शुभ दशहरा या त्योहार के नाम के साथ शुभकामना कहा जाता था। लेकिन देखने में आ रहा है कि हमारे विशुद्ध भारतीय त्योहार आधुनिकता के अतिक्रमण से ग्रसित हो रहे हैं। शुभ दीपावली कब हैप्पी दीवाली में बदल गया किसी को खबर तक नहीं हुई।

किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्र पहचान के साथ एक विशिष्ट भाषा भी जुड़ी होती है जो राष्ट्रीय एकता का मूलाधार होती है। भाषा एक राष्ट्र की जीवन शैली, आचार-विचार, सामाजिक-धार्मिक प्रवृत्तियों, सांस्कृतिक एकता तथा देशवासियों की चित्तवृत्तियों का परिचायक होती है। और एक बात जब आप शुभ कहते हैं तो यह एक लोक मंगल कामना से भरा भाव होता है और हैप्पी यानी खुशी एक नितांत निजी भाव है। अंग्रेजी में शुभ का समानार्थी शब्द और दीपावली की उत्सवी उल्लास की भावना से सराबोर समानार्थी शब्द खोजने में आपके पसीने छूट जाएंगे। दीपावली निजी न होकर लोक मंगल का पर्व है। तो यहां शुभ दीपावली कहना ही उचित है, न कि हैप्पी दीपावली। जब हम शुभ की बात करेंगे तो हैप्पी तो बिना कहे ही हो जाएंगे।

भारतीयता का भाव हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है और यह प्रतीक एक एक शब्द को जोड़कर गढ़ा जाता है। दीपावली के इस महापर्व पर यह संकल्प लेना जरूरी है कि हम निजता से परे जाकर लोकमंगल की बात करेंगे। भगवान श्रीराम लोक मंगल के अधिष्ठाता हैं और हम उनके वंशज पूरे विश्व का शुभ चाहते हैं, इसलिए बार बार, हर बार दीपावली शुभ हो कहना ही उचित है। **(लेखक सामाजिक मामलों के जानकार हैं)**

मेलबाक्स

अपना रवैया बदले भाजपा

'संकट के दौर से गुजरती भाजपा' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राजीव सचान ने तथ्यों के आधार पर यह रेखांकित किया कि तीसरे कार्यकाल में अपनी सरकार के दौरान भाजपा का रुख-रवैया बदला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सिर पर तमाम उपलब्धियों का सेहरा बंधा हुआ है, किंतु इस कार्यकाल की कार्यशैली उनकी विरासत को प्रभावित कर रही है। भाजपा इतनी छोटी सी बात कब समझेगी कि जब एक समर्पित कार्यकर्ता पर हमला होता है तो वह किले की एक ईंट टूटने जैसा होता है। एक-एक ईंट के दरकने से किला अंततः ध्वस्त हो जाता है। कुछ ही दिन पूर्व पार्टी ने कंगना रनौत द्वारा कही गई सच्ची बात को झुठला दिया। इससे आम कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। जब पार्टी खुद को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में प्रचारित करती है तो उसे अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं के पीछे भी मजबूती से खड़ा रहना चाहिए।

संपूर्णानंद वर्मा, हेतिमपुर (देवरिया)

दीर्घावधि में भाजपा की रणनीति

दैनिक जागरण के 28 अगस्त के अंक में प्रकाशित लेख ''संकट के दौर से गुजरती भाजपा'' तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में सम्यक विश्लेषण है। कंगना रनौत का किसान आंदोलन से संबंधित वक्तव्य तथ्यों के आधार पर सही था और छद्म किसान नेताओं की धमकियों और 26 जनवरी को संसद मार्च के वक्तव्य में बांग्लादेश जैसी स्थिति की आशंका उसकी पुष्टि थी। किसान आंदोलन के चलते पिछले कार्यकाल में सरकार ने तीन नए कृषि कानून भी वापस लिए। सरकारी सेवाओं में उच्च स्तर पर लेटरल एंट्री के निर्णय को वापस लेने के निर्णय और भाजपा द्वारा जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों में प्रथम सूची को वापस लेने जैसे निर्णय पर विपक्ष ने प्रश्न उठाए हैं, परंतु ऐसे निर्णय वापस लेने के लिए भी साहस चाहिए। विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और सरकार के प्रत्येक निर्णय का भारी विरोध उसकी एक मात्र रणनीति है। इन सबके बावजूद देश में स्थिरता है, जहां पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव में विदेशी हस्तक्षेप से लोकतंत्र तो छोड़िए, उनका अस्तित्व भी खतरे में है। वहीं विदेशी ताकतें भारत को भी अराजकता व दंगों में झोंकने के षड्यंत्र रच रही हैं। विपक्षी दल उनके एजेंडा को धरातल पर उतारने को आतुर हैं। जातिगत जनगणना, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को दोहराना, संविधान पर भ्रम फैलाना, समान नागरिक संहिता पर जन विद्रोह खड़ा करना, वक्फ कानूनों के संशोधन पर बवाल करना, हिंदुओं को हिंसक बताना, सनातन का लगातार अपमान करना, जम्मू-कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को बहाल किए जाने की बात करना, लेकिन देश की प्रगति के लिए कोई चर्चा नहीं करना, यही विपक्ष का सरकार विरोध अब देश के विरोध का पर्याय बन चुका है। भाजपा विपक्ष के किसी भी जाल में नहीं फंसी है। इसे 'संकट' कहना उचित नहीं है, बल्कि संकट में तो विपक्ष है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

जम्मू-कश्मीर की समझदार जनता

जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। राज्य में जनाधार बढ़ाने को नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हाथ मिलाया है। कश्मीर की स्थिति दुनिया जानती है। जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल बनाने वाली वर्तमान केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर धरातल पर शांति स्थापित की है। कश्मीर की वादियों में गोलियों की बौछार जीवन पर भारी थी। पीडीपी और कांग्रेस के शासन काल में जनता त्राहिमाम कर रही थी। नेशनल कांफ्रेंस कई वर्षों तक सत्ता में रही थी। केंद्र में कांग्रेस का शासन था। लेकिन कश्मीर में चलने वाली गोलियों का कोई जवाब नहीं था। कश्मीरी पंडितों को एक-एक कर मार गिराने वाले आतंकियों के कारनामों पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं था। अब जनता धरातल पर बदलाव देखना पसंद करती है। चुनाव में घोषणाएं की जाएंगी। कांग्रेस की घोषणा कभी पूरी नहीं होने वाली लोकलुभावन घोषणा है। जनता समझदार हो चुकी है।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एमेरिटस-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****